हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 जनवरी, 1975

खंड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 14 जनवरी, 1975

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(11)1
बहिर्गमन	(11)16
वर्श 1975–76 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा मतदान	(11)16

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14:00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उतर

Mr. Speaker: Question Hour.

Nehru College Ajronda

***1129. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) whether the building and rooms of Nehru College Ajronda (Faridabad) have been locked by the Government and kept under the supervision of any authority of the Faridabad Complex; and

(b) whether any steps are proposed to be taken by the Government to utilise the goods and buildings of the said college for some School, College or hospital, if so, the details?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik):

(a) No.

(b) The Matter is sub-judice.

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि लीगल कंस्लटे ान के बाद क्या उस कालिज की गुड्ज को जो कि ने ानल प्रापर्टी हैं किसी और संस्था को देने पर विचार किया जाएगा ?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, वह कालिज डिसऐफीलिएट हो गया है। उसकी प्रापर्टी का हमारे से कोई सम्बन्ध नहीं हैं फरीदाबाद काम्पलैक्स से है।

Buses in Hissar Depot

***1186. Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) the total number of vehicles with the Haryana Roadways Hissar depot together with the number of vehicles, which have been declared unserviceable upto 31-12-1974;

(b) the total number of Haryana Roadways buses which broke down on their way from Delhi to Hissar during the period from 1-1-74 to 31-12-1974; and

(c) the total number of new buses given to the Hissar depot in 1973-74?

Development Minister (Col. Maha Singh):

(a) 211 and 32 respectively.

(b) 80.

(c) 58.

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि 31—12—1974 तक 211 बसों में से 32 बसें अनसर्विसेबल थी। क्या वह बताएंगे कि इस डिपो की रिक्वायरमैंट कितनी है जिससे कि ओवरलोडिंग बन्द हो जाए ?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब, जितने पैसिन्जर्ज बढ़ते जाते है उतनी ही हम बराबर बसें बढ़ाते जाते है और आगे जाकर जैसा मैनें पहले अर्ज किया 16 बसें जल्दी ही हिसार डिपो को देने जा रहे है।

कर्नल अमर सिंहः स्पीकर साहब, 'बी' पार्ट के जवाब में बताया गया है कि 80 बसें रास्तें में ब्रेक डाउन हुई। क्या मल्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन बसों में सवारियां कितनी थीं, जब ब्रेक डाउन हुई?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, सवारियों को तो इससे को ताल्लुक नहीं है और न ही सवारियां ब्रेक डाउन के वक्त गिनी जाती है।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिवाड़ी डिपो की कितनी बसें ब्रेक डाउन हुई?

कर्नल महा सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल हिसार डिपो के बारे में है, रिवाड़ी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अमर सिंहः मिनिस्टर महोदय, ने 'सी' पार्ट के जवाब में बताया है कि 1973–74 में कुल 58 बसें दी गई। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1973 में कितनी बसें दी गई और 1974 में कितनी दी गई?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, 1973–74 में टोटल 58 बसें दी गई जिसमें से 43 हिसार डिपो के पास रही और 15 बसें जो नए डिपो बने जैसे भिवानी उनको ट्रासफर हो गई।

चौधरी पीर चंदः क्या मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि हिसार से तीन डिलैक्स बसें हिसार से दिल्ली और हिसार से चण्डीगढ़ को चलती थीं उनको बन्द करने का क्या कारण है?

कर्नल महा सिंहः क्योंकि डी–लैक्स बस का किरया बढ़ा दिया गया है, इसलिए अब सवारियां कम मिलती हैं इसलिए उनको बन्द कर दिया गया है अगर सवारियां मिलें तो अभी चालू की जा सकती है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हिसार से चण्डीगढ़ और दिल्ली जो डि–लैक्स बसें चलती थीं, क्या वह दूसरी रोड़ पर चलने लगी है?

कर्नल महा सिंहः ती हा, दूसरी रोड़ज पर चलती हैं। हमारे पास और भी बसें हैं, अगर सवारियां मिलें तो हम चला सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया है कि डी–लैक्स बस का किराया दुगना कर दिया है इसलिए कम सवारियां मिलती हैं।

श्री गुलाब सिंह जैनः हिसार से चण्डीगढ़ को जो डी–लैक्स बस चलती थी और वह अब बन्द की दी है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सवारियां न मिलने का कारण यह तो नहीं कि उसके 15 मिनट बाद ही सेमी–डी–लैक्स बस चलती थी, जो वाया जींद जाती थी और उसका रूट भी छोटा था, इसलिए डी–लैक्स बस की सवारियां नहीं मिलती थी? क्या सरकार डी–लैक्स बस को दोबारा चलाने का विचार करेगी, और डि–लैक्स और सैमी डि–लैक्स बस में एक घण्टे का फर्क कर दिया जाएगा?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय इस पर विचार किया जाएगा।

राव बंसी सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो 80 बसें ब्रेक–डाउन हुई उसका क्या कारण था और उन कारणों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए है?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय कारण तो बहुत हैं, लेकिन मोटे कारण जो हैं, वे हैं ईजन डिफैक्ट, ट्रांसमी ान

डिफैक्ट और डिजल डिफैक्ट जिसके बारे में आई.ओ.सी. की रिपोर्ट की गई है और टायर पन्चर भी हुई है।

श्री गिरी ा चन्द्र् जो ीः मंत्री महोदय ने बताया है कि हिसार से चलने वाली डी–लैक्स बस बन्द कर दी गई, क्योंकि सवारियां नहीं मिलती थीं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यमुनानगर से चण्डीगढ़ की डी–लैक्स बस चलाने पर विचार करेंगे अगर वहां से सवारियां मिल सकें, तो?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय अगर जो ी जी बताएंगे कि किस टाईम डी–लैक्स वहां से भरकर चल सकती है और किस वक्त भर कर यहां से भर कर वापिस जा सकती है तो जरूर चला दी जाएगी।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली से हिसार जो बसें चलतीहैं वे 80 ब्रेक डाउन हुई। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐसी बसे थीं, जिनमें स्टेपनी नहीं थी और कितनी टायर की कमी के कारण खड़ी रहीं?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से तो आंकड़े नहीं है, लेकिन स्टेपनी होती है, मगर कभी टायर की कमी की वजह से दिक्कत भी हो जाती है। हमारी टायर मांगने की कोि ा ा होती है, लेकिन आजकल दे ा में स्थिति ऐसी है कि कभी टायर नहीं मिलते हैं।

चौधरी पीर चंद: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि डी–लैक्स बस का किरया बहुत ज्यादा है इसलिए उसको कम करने पर गौर करेंगे और हम सवारियां भेजने की कोि ा ा करेंगे?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि गरीब के खर्च पर अमीर को चलना मुनासिब नहीं है। डी–लैक्स बस में करीब आधी सवारियां होती हैं, आर्डिनरी बस से इसलिए डि–लैक्स बस का किराया आर्डिनरी बस से दुगना रखा गया है ताकि गरीब को ज्यादा बोझ न उठाना पड़े।

चौधरी फूल चंद (मुलाना): मंत्री महोदय ने बताया है कि 80 ब्रेक डाउन हुए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होने का सबसे बड़ा कारण कहीं यह तो नहीं कि रोड़ पर जो पुरानी बसें हैं उनको चलाया जा रहा है और इस वजह से ब्रेक डाउन होते हैं।

Mr. Speaker: No. It is a suggestion, not a supplementary.

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक से चण्डीगढ़ को डी–लैक्स बस चलाने पर गौर किया जाएगा।

कर्नल महा सिंह: रोहतक से डी–लैक्स बस चलाने के लिए पहले ही डिपार्टमैंट को एग्जामिन करने के लिए कह रखा है।

पता चला है कि अभी सवारियां नहीं मिलती गर्मी में ज्यादा सवारियां मिलेंगी, तो सब चलाएगें।

चौधरी बृजलालः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरसा से दो बसे चण्डीगढ़ के लिए चलती हैं। क्या डबवाली से भी एक बस चलाने की कृपा करेंगे?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, डबवाली से अगर सवारियां मिलेंगी, तो वहां से भी चला देंगे।

राव बंसी सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी नारनौल से मंत्री महोदय के आर्डर से बस चलाई गई है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे एक बस जिसको चले हुए अभी आठ–दस दिन हुए है वह मोबिल आयल खाने लगी है, इसका मेन कारण क्या है, क्या इस बात की इन्क्वायरी करवाएंगे?

कर्नल महा सिंहः जरूर इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे।

श्री अमर सिंहः अभी मंत्री महोदय ने पार्ट 'बी' के जवाब में बतायर है कि 80 ब्रेक डाउन हुए है तो ऐसी हालत में मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोई मोबाइल वर्क ाप चलाने की तवजीज है?

कर्नल महा सिंहः अध्यक्ष महोदय एक बस के बाद दूसरी बस आ जाती है और वह बस सवारियों को लिफ्ट करके ले जाती है।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हम को क्वै चन नहीं पूछेंगे और न ही किसी डिस्क ान में हिसा लेंगे क्योंकि हमें यहां हाउस में बोलने के लिए पूरा टाईम नहीं दिया जाता और क्वै चन आवर के बाद हम बाहर चले जाएंगे––(ाोर)––

श्री अध्यक्ष महोदयः यह क्वै चन पूछने का टाईम आप को मिल रहा है।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, किस तरह का टाईम उनको नहीं मिल रहा है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, आपके पास तो सार रिकार्ड मौजूद है, आप देख सकते हैं कि इनको पार्टी की स्ट्रैन्थ के अनुसार कितना अधिक टाईम दिया गया है।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मैं कल बोलने के लिए खड़ा हुबा तो उस समय और कोई मैंबर खड़ा नहीं था। श्री बनारसी दास गुप्ता जी आए, इन्होंने मैम्बर को खड़ा किया, लेकिन मुझे बोलने का टाईम नहीं दिया गया और हमें कह दिया जाता है कि बैठ जाओ, टाईम नहीं मिलता, इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर यहां पर नहीं बोलेंगे।

Mr. Speaker: That I will see. But now it is question-hour. If you want, please put your question.

———————

तारांकित प्र न संख्या 1145

माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे अतः यह प्र न सदन में पूछा नहीं गया।

———————

तारांकित प्र न संख्या 1201

यह प्र न माननीय सदस्य द्वारा पूछा नहीं गया।

———————

तारांकित प्र न संख्या 1208

यह प्र न माननीय सदस्य द्वारा पूछा नहीं गया।

———————

तारांकित प्र न संख्या 1256

माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे अतः यह प्र न पूछा नहीं गया।

——————

Income to Market Committee Faridabad

***1130. Shri K.N. Gulati:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state---

(a) the yearwise income accured to the Market Committee Faridabad during the last 3 years; and

(b) the total amount spent by the Market Committee Faridabad for providing facilities to Anaj Mandi and Subzi Mandi during the last 3 years?

कृशि मंत्री (चौधरी भजनलाल) :

		रूपये
(क)	1971–72	109201
	1972–73	142424
	1973–74	145415

(ख) सब्जी मण्डी के लिए कोई रा ाी खर्च नहीं की गई किन्तु अनाज मण्डी तथा न्यू इन्डस्ट्रीयल टाऊनि ाप सबयार्ड के लिए वर्श 1971–72 में 4806 रूपये, 1972–73 में 6594 रूपये तथा 1973–74 में 1120 रूपये खर्च किए गए।

श्री के.एन.गुलाटी: अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दो तीन सालों की इन्कम करीबन 4 लाख बताई और तीन सालों में खर्चें की रा ि ा 10 हजार बताई है, क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन मंडियों की हालत में सुधार किया जाएगा? क्या कोई ऐसी स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, दो तीन बार पहले भी यह सवाल आया था उस वक्त भी मैंने बताया था और इस हाउस में आ वासन भी दिया था कि जिन मंडियों की हालत ठीक नहीं है, उनके लिए हमने महकमों को आदेश दे रखे हैं कि जिन मंडियों की हालत खराब है, उनको ठीक करने की कोि ा ा की जाए।

श्री गौरी भांकरः क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का कश्ट करेंगे कि मार्किट कमेटियों को जो 10 परसैन्ट सरकार देती है, उसको 20 परसैन्ट करने की सरकार की कोई स्कीम विचाराधीन है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, इस वक्त सरकार का काई ऐसा विचार नहीं हैं।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः क्या मंत्री महोदय बतांएगे कि झज्जर में जो सब्जी मंडी है, वह ठीक जगह पर नहीं है, कई बार वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, क्या उस को कहीं और ि ाफ्ट करने का सरकार का विचार है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, यहां पर क्वै चन तो फरीदाबाद के बारे में पूछा गया है लेकिन जैसा कि कटारिया साहब ने कहा है, उस को भी देख लेंगे और सुविधा के अनुसार अगर उचित समझा गया तो विचार करेंगे।

चौधरी पीर चंदः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मार्किट फीस बहुत ज्यादा है और यह जमींदारों पर बड़ा भारी बोझ है, क्या सरकार इस फीस को कम करने का विचार रखती है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, मार्किट फीस का भार जमींदारों पर नहीं पड़ता, यह फीस तो माल खरीदने वाले से ली जाती है।

चौधरी बृजलालः अध्यक्ष महोदय, पंजाब में मार्किट फीस किसी रिट के कारण कम हो गई है, क्या हरियाणा सरकार भी इस बात को कंसिडर करने के लिए तैयार है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, रिट तो हरियाणा के बारे मे हुई थी मगर पंजाब के एक्ट में किसी कमी के कारण ऐसा हुआ था इसी वजह से हाई कोर्ट ने उसको वानिस कर दिया। हरियाणा की रिट तो खारिज हो गई है, यहां तो फीस उसी तरह की चलेगी।

श्री के.एन.गुलाटीः अध्यक्ष महोदय, तैसा कि अभी मंत्री महोदय ने 4 लाख के करीब इन्कम और केवल 10 हजार रूपये का खर्चा बताया है, इसको ध्यान में रखते हुए, हमारे इलाके के पास से एक पाली रोड़ गुजरती है, और जिसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने एक बार आ वासन भी दिया था कि उसको बनवा दिया जाएगा, क्या एग्रीक्लचर मिनिस्टर महोदय इस रोड़ को जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटियों का जो पैसा होता है, वह सैन्ट्रल पूल में जमा होता है और जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि उसके बाद पी.डब्ल्यू. डी. वाले प्रायर्टी फिक्स करते हैं कि कौन सी सड़क पहले बनाई जाए। जैसाकि गुलाटी साहब ने कहा कि मुख्य मंत्री महोदय ने आ वासन भी दिया था तो पी.डब्ल्यू.डी वाले इसको कंसीडर करके भीघ्र ही उस सड़क को बनाने की कोि ा ा करेंगे।

पंडित चिरंजी लाल भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा क्लीयर कर दूं कि यह जो पाली रोड़ है, यह मेन रोड़ पर है, लिंक रोड़ पर नहीं है, इसलिए यहां कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने आ वासन दिया था तो जब हमार फण्डज अवेलेबल होंगे तब इस पर विचार कर लिया जाएगा।

चौधरी बृज लालः क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिरसा के अन्दर सब्जी मंडी है, और वहां प्लाट्स भी बिक चुके हैं, क्या सरकार जल्दी से जल्दी वहां पर काम भुरू करवाने का प्रयत्न करेगी?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, सिरसा में सब्जी की मंडी बनाई गई है और बहुत जल्द ही वह चालू होने वाली है।

चौधरी फूल सिंह कटारियाः हमारे इलाके कोसली झज्जर में काफी दिनों से मंडी बनाने की सरकार की प्रोपोजल है और वहां पर इसके लिए प्लाट्स भी बिक गए हैं, और दुकाने भी

चालू हो गई हैं, क्या इसको जलदी ही बनाने व चालू करने का सरकार का विचार है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, इस काम को हम बहुत जल्दी ही परयूस करने की कोि ा ा करेंगे और बनाने की कोि ा ा भी करेंगे।

श्री गुलाब सिंह जैनः क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिसा के अन्दर एक नई मंडी बननी थी, वहां काफी से ज्यादा दुकाने भी बन गई हैं सरकार वहां पर कितनी देर तक बोली भाुरू करवाने की कृपा करेंगी?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी ही इस बारे में एक बिल लाने की सोच रहे है जहां पुरानी मंडियां है, वहां किसानों को काफी दिक्कत होती है, इसलिये हम सोच रहे हैं कि जहां नई मंडियां बना दी गई हों वहां पर जल्दी ही बोली नई मंडियों में भाुरू करवा दी जाए।

चौधरी अमीर चन्द मक्कड़ः हामरे भााहबाद में सब्जी मंडी तो है, वह बहुत तंग जगह पर है, क्या वहां पर सरकार का कोई दूसरी जगह पर नई मंडी बनाने का विचार है?

चौधरी भजनलालः अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में एग्जामिन करवायेंगे, अगर जरूरत महसूस की गई तो जरूर बनाने की चेश्टा करेंगे।

श्री के.एन.गुलाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पाली रोड़ के बारे में क्वै चन किया था तो उन्होंने कहा कि यह मेन रोड़ पर नहीं है, लिंक रोड़ पर है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि .....

Mr. Speaker : Order please. Please put a question.

श्री के.एन.गुलाटी : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री ही कर रहा हूं कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने अ ाोरेन्स दी है, वह पूरी की जाए।

चौधरी भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अ ाोरेन्स नहीं दी, मैंने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी वाले इसके लिये प्रापर्टी फिक्स करते हैं कि कौन सी सडक्रक पहले बनाई जाए। अगर मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है तो जरूर बनाई जाएगी।

चौधरी बृज लाल : अध्यक्ष महोदय, डबवाली के अन्दर नई मंडी बना दी गई है लेकिन मार्किट कमेटियों की तरफ से जो स्ट्रीट लाइट का प्रबन्ध करना था, वह अभी तक नहीं हुआ है। वहां पर कब तक स्ट्रीट लाइट का प्रबन्ध हो जाएगा?

चौधरी भजनलाल : स्ट्रीट लाइट का प्रबन्ध भीघ्र करने की चेश्टा की जाएगी।

श्री गुलाब सिंह जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने अभी फर्माया कि इसके बारे में हम एक नय बिल लाने का

विचार कर रहे हैं तो क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जब तक यह बिल नहीं लाया जाता तब तक दोनों पुरानी और नई मंडियों में बोली भाुरू करवा दी जाएगी?

चौधरी भजनलाल : जब तक इस प्रकार का कोई बिल पास नहीं हो जाता तब तक दोनों पुरानी और नई मंडियों में बोली लगती रहेगी।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : अध्यक्ष महोदय, पहले भी कई दफा सरकार के नोटिस में यह लाया गया है कि पानीपत में ऊन की मंडी है और वहां पर हरिजन वगैरह ऊन बेचते है और उनसे मार्किट फीस ली जाती है। बल्कि बेचने और खरीदने वाले दोनों से ही मार्किट फीस ली जाती है और यह मेरी बात फैक्ट है।

श्री अध्यक्ष : कटारिया साहब, आप पूछना क्या चाहते है?

चौधरी फूल सिंह कटारियाः स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों से, जो ऊन बेचते है, फीस न ली जाए।

चौधरी भजनलालः स्पीकर साहब, इसमें किसी हरिजन या ब्राह्मण का सवाल नहीं है। यह जो मार्किट फीस है यह बेचने वाले से नहीं ली जाती है, मैम्बर साहिबान को भाायद इसका

मुगालता हो गया है, यह फीस केवल उन से ली जाती जो माल प्रचेज करते हैं।

——————

Water Supply Scheme

***1187. Shri. Amar Singh :** Will the Ministger for Irrigation and Power be pleased to stae the time by which the following water supply schemes will be complelted in Bawani Khera constituency in Bhiwani District-

(a) Rohnat Water Supply Scheme;

(b) Siwara Water Supply Scheme;

(c) Baliali Water Supply Scheme;

(d) Mujhadpur Water Supply Scheme;

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी) : इस कार्य के पूर्ण होने की कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पंचायतों द्वारा सार्वजनिक भाग जमा कराने तथा सफाई बोर्ड हरियाणा द्वारा राशि देने पर निर्भर है।

श्री अमर सिंहः मंत्री महोदय को पता होगा कि रोहनाट, सिवारा, बलियाली और मुजादपुर इन चारों गांवों का पानी कड़वा और खारी है तो क्या वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम जल्दी तैयार करवाई जाएगी?

श्रीमति भाारदा रानी : जब चौधरी अमर सिंह जी बता रहे है तो यह बात ठीक होगी कि वहां का पानी कड़वा और खारी है। अध्यक्ष महोदय, रोहनाट के लिये सन्1970 में एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल हो गई थी और स्कीम मन्जूर हो गई थी। उस समय यह चार गांवो की स्कीम थी और उस समय लोगों ने न तो अपना बैनीफि ायरी भोयर दिया और न ही जमीन दी। इसलिए आखिर में यह स्कीम कैंसिल हो गई। सिवारा के साथ भी यही हुआ। वहां के लोगों ने पानी लेने से इन्कार कर दिया था। अब उन्होंने दोबारा एप्लाई किया है और उनके लिये अब दोबारा एस्टीमेट्स तैयार किये जा रहे है। बलियाली के लिये स्कीम तैयार की जा रही है। मुझादपुर की 2 लाख 34 हजार रूपये की स्कीम सन् 1970 में मंजूर हुई थी और अब तक सैंनेटरी बोर्ड ने एक लाख तीन हजार रूपया दे दिया है लेकिन गांव वालो ने अभी तक जमीन नहीं दी है और न ही भोयर दिया है। चौधरी अमर सिंह जी उनको इतना भी परसू नहीं कर सकते कि पंचायत से जमीन और बैनीफि ायरी भोयर दिलवा दें।

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदया, बताएंगी कि जहां पर खारी और कड़वा पानी है अगर वहां के लोग जमीन देने के लिये और बैनीफि ायरी भोयर देने के लिए तैयार हों तो क्या वहां पर यह स्कीम लागू की जाएगी?

श्रीमति भाारदा रानी : ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यह इस पर भी डिपैंड करता है कि हमारे पास कितने साधन हैं नई स्कीमें भी साधनों पर डिपैंड करेंगी।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जिन्होंने अपना बैनीफि ायरी भोयर भी जमा करवा दिया है और जमीन भी दे दी है तो क्या उनको प्रायरिटी दी जाएगी?

श्रीमति भाारदा रानीः आप जिस स्कीम के लिये कह रहे है उसके लिये पिछली सैनेटरी बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी हो गई थी और कुछ पैसा भी दिलवा दिया है।

चौधरी बृजलाल : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जिन गांवों ने इस स्कीम के लिए पैसा करवा दिया है वहां पर यह स्कीम कब तक चालू हो जाएगी?

श्रीमति भाारदा रानी : यह तो सैनेटरी बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल मिलने के बाद ही बताया जा सकता है।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जैसे बरवाला मेरा हल्का है उसके अन्दर वाटर वर्कस स्कीम कम्पलीट हो चुकी है लेकिन उसके साथ दो–दो मील पर जो ढ़ानियां हैं क्या उनको भी पानी पहुंचाया जाएगा?

श्रीमति भारदा रानी : यह सवाल तो भिवानी जिले के चार गांवों का है।

श्री अमर सिंह : जैसे मंत्री महोदया ने फर्माया है कि गांव वालों ने जमीन देने से इन्कार कर दिया है। क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि अगर वे अब जमीन दे दें तो यह स्कीम कितने दिन में तैयार हो जाएगी?

श्रीमति भारदा रानी : अगर वे जमीन दे दें और अपना बैनिफि ायरी भोयर भी दे दें जो आज ही वहां पर काम भुरू करवा देंगे। वैसे हमने उनके साथ यह रियायत की है कि तीन साल हो गए उन्होंने न भोयर दिया है और न ही जमीन दी है अगर हम चाहते तो इसे कैंसिल कर सकते थै

श्री के.एन.गुलाटी : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि बल्लभगढ़ के कितने गांवों को इस स्कीम से पानी मिल रहा है और फरीदाबाद को कितना मिल रहा है?

श्रीमति भारदा रानी : बल्लभगढ़ के 28 गांवों में यह स्कीम चालू है उन गांवों के नाम इस वक्त तो मेरे पास नहीं हैं। जहां तक फरीदाबाद का ताल्लुक है वहां पर करीब अढ़ाई लाख की आबादी है और फरीदाबाद टाउनि ाप में सब को पाइप वाटर मिल रहा है।

श्री ओम प्रका ा गर्ग : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि थानेसर के कुछ गांवों ने एप्लाई किया हुआ है और वह अपना

भोयर भी देने के लिए तैयार है तो क्या उनको पानी दिया जाएगा?

श्रीममि भाारदा रानी : हां एक दो साल में कंसिडर कर लेंगे। लेकिन यह क्वै चन बवानी खेड़ा का है।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि सवाल में जिल चार गांवों का जिक किया हुआ है इनका अलग–अलग एस्टीमेट किस प्रकार है?

श्रीमति भाारदा रानी : रोहनाट का जो नया एस्टीमेट बना है वह 4 लाख 83 हजार का है। सिवारा के साथ कई और गांव मिला कर उसका एस्टीमेट 14 लाख 22 हजार का था अब उसका नया एस्टीमेट 5 लाख 57 हजार का बना है। बलियाली का एस्टीमेट बन रहा है। मुझादपुर का पुराना एस्टीमेट 2 लाख 34 हजार का था अब उसको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिये वह एस्टीमेट ज्यादा होगा।

———————

तारांकित प्र न संख्या 1146

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थें

———————

तारांकित प्र न संख्या 1211

चौधरी रामलाल वधवा अपना प्र न पूछने के लिए खड़े नहीं हुए।

———————

तारांकित प्र न संख्या 1209

चौधरी ि ाव राम वर्मा अपना प्र न पूछने के लिए खड़े नहीं हुए।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मैं सवाल तो नहीं पूछता हूं। आज हम खामो ा प्रोटैस्ट इसलिये कर रहे है क्योंकि हम हाउस का टाईम बचा रहे है। कल जब मैं और जिस दिन राम लाल जी खड़े हुए थे तो कोई मैम्बर नहीं खड़ा हुआ था लेकिन इनको बीच में ही बैठा दिया गया। उसके बाद कल जब मैं खड़ा हुआ.....

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातें करने की यह क्या स्टेज है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : स्पीकर साहब, हमें 15 मिनट भी नहीं बोलने दिया जाता।

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि ऐसी बात करने की यह क्या स्टेज है?

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें गलत हैं। क्वै चन आवर में प्वायंट आफ आर्डर भी नहीं होता और दूसरी बात गलत है। बात यह है कि इस ढ़ंग से तो कार्यवाही चलेगी नहीं। जहां तक अपोजी ान का ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि इनको ज्यादा से ज्यादा एकोमोडे ान दूं और दे भी रहा हूं। जहां तक पुरानी प्रथा का ताल्लुक है पिछले एक साल का रिकार्ड निकाल लो जितना टाईम बनता है उससे ज्यादा दिया है और इस सै ान में अब तक भी ज्यादा टाईम दिया है। अगर कोई ऐसी बात हो तो आप मेरे चैम्बर में आकर बात कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत है। आपको नियमानुसार बोलने में पूरी आजादी है और खुली छूट है। काफी टाईम तक आप लोग बोलते रहे है। चौधरी दल सिंह 74 मिनट बोले है इस सै ान मैं आप भी बोले हैं और चौधरी राम लाल जी भी 45 मिनट के करीब बोले है और काफी लम्बी–लम्बी स्पीचें दी गई है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : कल मैं जितना टाईम बोला वह टोका टाकी और घंटी बजाने में ही चला गया।

एक आवाज : आप दौलता साहब के साथ झगड़ा करते रहे।

चौधरी ि िव राम वर्मा : वह टाईम इसमें भाामिल नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मुझे जबरदस्ती बैठाया गया और उसके बाद कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको पहले भी कहा कि आप मेरे पास चैम्बर मैं आकर बात कर सकते है।

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, चैम्बर में प्रैस नहीं होता, ये तो प्रैस को दिखाना चाहते है।

चौधरी ि िव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, देख लें एक मिनिस्टर कैसी बात कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : नो डिसक ान इन क्वै चन आवर। मेरे पास टाईम का हिसाब आ गया है। मैंने दोनों का टाईम मंगाया है गवर्नर ऐड्रैस का भी और जनरल डिसक ान आन बजट का भी।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : स्पीकर साहब, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात सबमिट करूंगा कि हमने बिजनैस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग में भी टाईम का फैसला किया था कि सदन के जितने मैम्बर हैं, हर मैंबर के हिसाब से टाईम बांट कर दे दिया जाए। हर आदमी मैंबर है, जो इंडिपैंडैट है वह भी मैंबर है। जनसंघ के ही दो मैंबर नही है हाउस में, इसलिये ही

मैंबर को टाईम बांट कर दे दिया जाए। अगर इस तरह नहीं दिया जाएगा तो हम भी अपने मैंबरों के हिसाब से टाईम मांगेगे, इंडिपैडैंट भी मांगेगा और दूसरी पार्टियां भी मांगेगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि जनसंघ वाले ही बोलते रहें और दूसरे देखते रहे। आप चाह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अभी बुला लो फी मैंबर के हिसाब से आप जितना टाईम देंगे उस हिसाब से जनसंघ वाले चाहे दो बोल ले चाहे एक बोल ले। इसी तरह इंडीपैंडैंट के चाहे 6 बोल लें चाहे एक बोल ले और हमारी तरफ से चाहे कितने ही बोलें आप टाईम अलाट कर दो। यह नहीं हो सकता कि ये तीन घंटे बोलते रहे और दूसरे को टाईम न मिले। और फिर वाक आउट भी करेंगे। चले आओ। चाहे ये सारी उम्र के लिए वाक आउट करके चले जाएं हमें इस बात की बिल्कुल चिन्ता नहीं है। टाईम के ऊपर हमारा हक है और हम पब्लिक के चुने हुए रिप्रजैटेटिव हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी सी चिन्ता मुझे हो जाती है.....

चौधरी ि ाव राम वर्मा: स्पीकर साहब, भाायद मुख्य मंत्री जी को यह पता नहीं कि परसों जब चौधरी राम लाल जी खड़े थे तो कोई मैंबर भी नहीं खड़ा हुआ था लेकिन उनको फिर भी बीच में ही बिठा दिया गया और कल जब मैं खड़ा हुआ तो

कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ था फिर भी मुझे पूरा नहीं बोलने दिया गया।

चौधरी बंसी लाल : आप जनसंघ वाले अपना टाईम ले लो, आप दो हैं (विघ्न) इन्होंने मजाक समझ लिया है असैम्बली को.....

श्री अध्यक्ष : जो टाईम बोलने का दिया गया है उसका मैंने हिसाब मंगवा लिया है और उसके मुताबिक गवर्नर ऐड्रैस पर जो डिसक ान हुई है उस पर ट्रैजरी बैंचिज ने टाईम लिया हैं 4 घंटे 14 मिनट और अपोजि ान ने 3 घंटे 39 मिनट। फिर जनरल डिसक ान आन दि बजट और इन डिमांड्ज की डिसक ान पर कल तक जो डिसक ान हुई है, क्योंकि यह एक नेचर की तकरीबन डिसक ान होती रही है डिसक ान आन बजट पर भी और डिमांडज पर भी तो उस पर जो टाईम लिया गया है वह ट्रैजरी बैंचिज ने लिया है 3 घंटे 32 मिनट और अपोजि ान ने लिया हैं 4 घंटे 32 मिनट। तो इसलिये किसी को कुछ कहने की कोई गुन्जाय ा नहीं है।

चौधरी चांद राम : आप अपोजि ान कहते किसको है यह सात मैंबर हैं अपोजि ान के।

श्री अध्यक्ष : यह बात मैं कैसे हाउस में मान सकता हूं। जो अपोजि ान हमारे सैकेटेरियट के रिकार्ड पर है वही रहेगी अनलैस इट इज चैंजड।

चौधरी बंसी लाल : अगर सात मैंबर हैं तो सात के हिसाब से टाईम दे दो इनको और 70 हम को दे दो।

श्री अध्यक्ष : जो रिकार्ड हमारा है विधान सभा सैकेटेरियट का उसके मुताबिक मैं मैंबरों को बोलने का टाईम दूंगा।(विघ्न)

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसीलिये आज हम समय बचा रहे हैं (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

गृह मंत्री (श्री के.एल.पोसवाल) : स्पीकर साहब आप टाईम सब मैम्बरान को हिसाब से दे दीजिये हमें कोई एतराज नहीं हैं लेकिन हम किसी और को फालतू नहीं बोलने देंगे।

चौधरी बंसी लाल : मिनिस्टर फार पार्लियामैंट्री अफेयर्ज ने सही कहा है अगर आज यह टाईम इन्डिविजअल मैंबर से ज्यादा या अपनी पार्टी से ज्यादा लेंगे तो हम नहीं बोलने देंगे यह पक्की बात है यह टाइम भी खा जाते है और फिर ब्लेम भी करते हैं, स्पीकर की अथौरेटी को भी चैलेंज करते हैं, हाउस को भी चैलेंज करते हैं हम इनको इन के मिनट से एक मिनट ज्यादा हाउस में बोलने नहीं देंगे।

Mr. Speaker : That we will take up in the meeting of the Business Advisory Committee.

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब टाईम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मैंबरान के हिसाब से बांट दिया जाए एक मैंबर के हिस्से में जितना टाईम आता है उस हिसाब से बांट दिया जाये।

चौधरी बंसी लाल : इस हाउस में जो अपोजि ान है, रियल अपोजि ान है भ्रुरू में आये थें उस दिन से आज तक जो है वह सिर्फ वि ाल हरियाणा पार्टी है (विघ्न) चौधरी चांद राम तो चार पांच पार्टियों में जा लिये है आज तक हम ने तो कोई बेरा नहीं कि कौन सी में हैं इस ने तो अपनी मर्जी वाली बात कर रखी हैं (हंसी)

श्री अध्यक्ष : देखिये बाहर का एटमासफियर इतना ठंडा है अन्दर इतनी गर्मी होने की तो कोई बात है नहीं (हंसी) वैसे मैं हाउस की जो सैंस है, जो आपने अपने ख्यालात जाहिर किये हैं उसका हिसाब लगा कर देख लूंगा कि पार्टीज की स्ट्रैंथ कितनी–कितनी है उसके हिसाब से किस ढ़ंग से उनको टाईम देना चाहिये उतना दूंगा उससे कम नहीं रहने दूंगा।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : स्पीकर साहब, आपके हिसाब से आजाद मैंबरों का अगर हक कटा हो तो अब पूरा कर देंगे? (हंसी)

चौधरी बंसी लाल : मैं तो दौलता साहब की इस बात की ताइद करूंगा कि अगर इनका हक कटा हो तो पूरा करना चाहिये।

Mr. Speaker. No further discussion please.

Construction of a Bridge over the Augmentation Canal

***1257. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the construction of the bridge sanctioned on the Augmentation Canal near village Alahar in Radaur Block of Kuruksherta District has been completed?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha**) :** No, Sir.

चौधरी चांद राम : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो पुल है जिसके बारे में मैंने सवाल किया है वह सरकार ने मन्जूर कर दिया है या नहीं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब वैसे तो यह ऑगमैंटे ान कैनाल के बारे में बात थी लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि जहां तक मुझे पता है यह पुल मन्जूर हो चुका है तकरीबन पौने दो लाख का इसका एस्टीमेट है और इस साल में बनाने का यत्न करेंगे।

चौधरी चांद राम : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगर यह पुल मन्जूर हो चुका है तो कब बनना भाुरू होगा और अगर बनना भाुरू हो गया है तो कब तक मुकम्मल होगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, सितम्बर से पहले कलोजर होती है तो जब कलोजर होगी तो कोि ा ा करेंगे कि बने। इसके साथ–साथ चार पुल और बनने है।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ाी : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि भाादी पुर और पांजूपुर में पुल बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : मुझे एग्जैक्ट नाम का तो पता नहीं लेकिन मुझे इतना पता है कि दो पुल अंडर कन्सिड्रे ान हैं। मैं इस बारे यह अर्ज करूंगा कि यह नहर 45 मील लम्बी है और इस बारे रूल्ज यह हैं कि ढ़ाई मील से कम पर पुल नहीं बन सकता। तो इस 45 मील लम्बी नहर पर 49 पुल बने हैं और पांच और मंजूर किया है। 54 पुल बना दिये है अगर फिर भी पुलों की मांग है तो बड़ी अजीब बात है।

चौधरी चांद राम : क्या लहार गांव के लोगों ने दरखास्त दी कि भाम ाान भूमि दूसरी तरफ है फल्ड की वजह से पानी रूक जाता है गांव में इसलिये.....

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, दरखास्त का तो पता नहीं लेकिन एक बात का पता है कि पुल मंजूर है।

Mr. Speaker: Question hour is over.

बहिर्गमन

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हाउस का समय बचाने के लिये हम जाते हैं डिसक ान में हिस्सा नहीं लेते ताकि समय बच जाये और मैंबरों को मिलें क्योंकि यहां तो मिनट–मिनट की बात भाुरू की दी है तो फिर तो यह भी कह सकते है कि बिल्कुल ही न बोलो।

(इस समय सर्वश्री ि ाव राम वर्मा और राम लाल वधवा वाक आउट कर गये)

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा): स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह भी वाक आउट कर गये हुये हैं लेकिन रोज रजिस्टर पर हाजरी लगा जाते हैं। (हंसी)

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : स्पीकर साहब, यह बात कमाल की है यह रोज रोज करने वाले है यह हाउस का बाई काट करने वाले हाजरी जरूर लगाते हैं। (हंसी)

गृह मंत्री (श्री के.एल.पोसवाल) : दल सिंह जी हाजरी रोज लगा जाते हैं।

वर्श 1975–76 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा (पुनरारम्भ) तथा मतदान

चौधरी मनफूल सिंह (झज्जर) : स्पीकर साहब, सदन में डिमांड्ज पर पिछले दो रोज से बहस चल रही है और मैं भी दो चार डिमांड्ज के बारे में.....

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, मैं जब कल हाउस एडजर्न हुआ उस वक्त बोल रहा था इसलिये मुझे टाईम मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप उठे ही नहीं। I have now called upon the Hon. Member.

चौधरी मनफूल सिंह : तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं सदन में दो चार डिमांड्ज के बारे में जिक्र करूंगा। पहले मैं एग्रीकल्चर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस साल यानि 1975–76 में एग्रीकल्चर पर 9,16,13,200 रूपये। यह ठीक है कि हरियाणा सरकार ने पिछले चार पांच साल में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जितना खर्च किया है उतना भाायद ही किसी और स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो। कई स्कीमें जो इस बारे में हैं वह पूरी हो चुकी हैं और कईयों पर काम चालू है। पंडित जवाहर लाल नेहरू कैनाल की जो स्कीम है इस पर इस पांच साल योजना में 35 करोड़ रूपये खर्च होने हैं। दौलता साहब ने एक बात ठीक ही कही है इस मैं कोई भाक नहीं है कि हमारी हरियाणा सरकार

ने इस प्रदे ा में जितना रूपया जरई पैदावार बढ़ाने के लिये खर्च किया है उतना भाायद ही किसी और स्टेट ने किया हो। एग्रीकल्चर प्रोडक ान हमारे दे ा प्रदे ा का उद्दे य है और ि ाक्षा के मैदान मैं तरक्की नहीं होगी। अगर हमार एग्रीकल्चर सॉउंड है और हमारा आम देहात में रहने वाला जो है वह माली तौर पर ठीक है खु ाहाल है तो आप समझ लें कि सारा ही दे ा खु ाहाल है और खु ा है खु ाअसलूब है। हमारे देहात के अन्दर 80 फीसदी दे ा की आबादी बसती है और यह सारी 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है या तो वह खुद मालिक के तौर पर खेत पर काम करते है या खेती मजदूर के तौर पर काम करते है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यह सारे लोग खुं ाहाल हैं तो सारा दे ा ही समझो खु ाहाल हैं। अब यह सवाल पैदा हो सकता है कि बावजूद इस बात के कि इतने ज्यादा पैसे एग्रीकल्चर पर खर्च होते हैं दे ा में अनाज की कमी क्यों हो और 25/26 साल की आजादी के बाद भी हम इस काबिल क्यों नहीं हैं कि अनाज के मामले में अपना गुजारा खुद कर सकें दूसरे दे ा की इस बारे में अगर फिगर्ज को देखें तो किसी दे ा में भी 20 फीसदी से ज्यादा लोग खेती पर काम नहीं करते बल्कि दूसरे दे ाों को करोड़ों रूपये का अनाज एक्सपोर्ट करते है। मैं अर्ज करता हूं कि हर दे ा के हालात मुख्तिलिफ हैं। जर्मनी और जापान को लें यह इन्डस्ट्रीलाइज दे ा हैं और उनकी ज्यादा आबादी इन्डस्ट्री का काम करती है। मैं कैनेडा की मिसाल लेता हूं। वहां पर 20 परसैंट आदमी खेती का काम करते है और हमारे

यहां 80 परसैंट करते है। कैनेडा वाले करोड़ों रूपये का अनाज बाहर भेजते है। हमारे दे ा का रकबा जिस पर खेती होती है वह 38 करोड़ एकड़ है और कुल आबादी 58 करोड़ की है। कैनेडा की आबादी पौने तीन करोड़ है और रकबा जो का त के नीचे है वह हिन्दुस्तान के मुकाबले में अढ़ाई गुणा है हिन्दुस्तान में एक आदमी के हिस्से पौना बीघा आती है। हम कितनी ही पैदावार क्यों न बढ़ा लें, गुजारा नहीं हो सकता। यही सवाल पैदा होता है कि जब तक आबादी की बढ़ोतरी न रोकी जाए, आबादी कम न हो जाए, हम कितनी ही पैदावार कर लें, गुजारा नहीं हो सकता। आबादी कम करने का महकमा सिर्फ बहन जी का ही महकमा नहीं है, यह स्टेट का सांझा महकमा है, जब तक आबादी कम नहीं होगी तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। जब तक हम सब मिल कर सहयोग नहीं देंगे तब तक न एजुके ान में, न प्रोडक ान में तरक्की हो सकती है। चौधरी भजनलाल जी इतनी जनता के लिए अनाज कैसे पैदा करेंगे जब तक आबादी हर रोज बढ़ती जाएगी। इस बात को कोई सोचता ही नहीं जो दे ा के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। आयंदा आने वाली नस्लें हमें बख्भोंगी नहीं। वे सोचेंगे कि कौन ये विधायक थे, कैसे मिनिस्टर थे जिनके टाईम में आबादी इस तरह से बढ़ती चली गई। कैनेडा की आबादी जितनी सन्1925 में थी आज भी वही है। 15–20 लाख की आबादी है जो फौरन कंट्रीज से लोग जाते है लेकिन तो कैनेडा की औरिजनल आबादी हे वह उतनी ही है जितनी सन् 1925 में थी। इसके मुकाबले में हमारे यहां पिछले

50 साल में आप देखें क्या हालत है, यह एक गम्भीर मसला है, इस पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो यह दे ा किस तरह बच सकता है? जिसने चाइना की हिस्ट्री पढ़ी है उसको मालूम होगा कि चाइना में क्या हालत होती जा रही है। वहां की आबादी बढ़ गई, इन्फले ान आया और इकोनोमी भौटर हो गई। इकोनोमी भौटर क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने आबादी की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1952 में कहा गया था कि हिन्दुस्तान ग्रेटैस्ट डैमोक्रेटिक रिपब्लिक है और आज भी हम फख्र से कहते है कि दुनियां में सबसे बड़ा डैमोक्रेटिक रिपब्लिक हिन्दुस्तान है, चाइना की भी यही हालत थी। उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों को नहीं रोका, काफी इन्फले ान चलता रहा? इकोनोमी भौटर हो गई, क्या हालत हो गए यह आप जानते है। अगर हमारे दे ा में भी यही हालत हो गई तो खतरनाक नतीजे होंगे। इसके साथ ही साथ पुलिटिकल पार्टियां फायदा उठाने के लिए वायलैंस पर उतर आई हैं, इनको इन्फले ान का, हर बिगड़े हुए हालात का फायदा उठाना है। अपने मोटिव को हासिल करने के लिए, ला एंड आर्डर को डिस्टर्ब करके दे ा में क्रांति लाना चाहते हैं। लोग इस ढ़ंग की क्रान्ति नहीं चाहते। इस सिचुए ान का फायदा उठाकर चाइना के टाईप का निजाम लाना चाहते है। कुछ लोग कहते है पार्टी–लैस गवर्नमैंट बनाई जा सकती है। मुझे समझ नहीं आती कि वह किस प्रकार की गवर्नमैंट बनाई जा सकती है। मुझे समझ नहीं आती कि वह किस प्रकार की गवर्नमैंट है? ही आदमी कहता है कि आबादी बढ़ रही है, लेकिन एम.एल.ए. या मिनिस्टर के बंगले का

घेराव करने से तो आबादी नहीं घटेगी? यह तो डैमोक्रैटिक फेज है, इसका फायदा उठाने के लिए फासिस्ट फोर्सिस्ज काम कर रही है, इन फोर्सिस्ज को रोकना चाहिए। यहां पर फैमिली प्लानिंग के बारे में कहा गया, एग्रीकल्चर के बारे में कहा गया, सरकार इस तरफ खूब काम कर रही है, कोि ा ा कर रही है कि फैमिली प्लानिंग से आबादी कम आये। जिम्मेदार आदमी कोि ा ा कर रहे है लेकिन सही मायनों में इसका यह हल नहीं है। 70–70 साल के बूढ़े आदमियों की नसबन्दी और 50–50 साल की औरतों का औप्रे ान करते हैं, इससे कुछ बनने वाला नहीं। ठीक ढ़ंग से, सही मायने में जैसे काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा। इसके लिए कोई एक आदमी जिम्मदार नहीं है, मिनिस्टर साहब जिम्मेदार नहीं है। न मिनिस्ब्र कुछ कर सकते है, न विधायक कुछ कर सकते है और न सरकारी कर्मचारी कुछ कर सकते है। इसके लिए तो सैन्ट्रल लैजिस्ले ान हो और आबादी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर पाबन्दी हो कि एक या दो बच्चे पैदा होने के बाद उसकी नसबन्दी या ओप्रे ान हो जाए, वरना दे ा बच नहीं सकता। आज 58 करोड़ है कल 78 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए जो हड़तालें करते है, पार्लियामैंट पर 6 मार्च को हमला करने की बात करते हैं, उनका यह कदम ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि ठीक तरह से ये विधायक, पार्लियामैंट के सामने जाकर फोर्सफुल तरीके से एक मैमोरैंडम लिख कर दें कि वे सैंट्रल लैजिस्ले ान लाएं। इस संकट से बचने के लिए सैन्ट्रल पार्लियामैंट कानून बना दे कि एक या दो बच्चे पैदा होने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा,

औपरे ान होगा। अगर इस डैमोक्रेटिक इंस्टीच्यु ान को कायम करना है, बजाये इसके कि नाजायज फायदा उठाकर तोड़ फोड़ करें और डैमोक्रेटिक सिस्टम को उजाड़ा जाए, इस डायरैक ान की तरफ कदम बढ़ायें। स्पकीर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार को सुजै ान दूंगा कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए केंद्रिय सरकार कोई ठोस कदम उठाये। हमारी यह बावत केंद्रीय सैन्ट्रल एक्ट बनाया जाए जिससे इस आबादी पर कानूनी पाबन्दी हो। यह टैक्स लगाने से नहीं हो सकता क्योंकि गरीब आदमी टैक्स से रोक नहीं सकता। पिछले 8 सालों से सरकार पूरी कोि ा ा कर रही है, हर ढ़ंग से कोि ा ा कर रही है, इसमें कोई भाक नहीं लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जब तक सरकार कोई रैडिकल चैंज नहीं लायेगी तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है।

स्पीकर साहब, दूसरा प्वायंट मेरा ऐग्रीकल्चर के बारे में है। ऐग्रीकल्चर प्रोडक ान में कैसे बढ़ावा हो सकता है? आज फ्रग्मैंटे ान आफ लैंड बहुत ज्यादा है। जमीन के टुकड़े–टुकड़े होने से रोका जाए। यह ठीक है कि लड़के और लड़की का हक बराबर हैं, लेकिन हमारे पास जो जमीन है, वह फी आदमी ¾ किल्ले हिस्से आती है। इसके बाद जिस तरह से लड़के और लड़कियों के दाखलखारिज किए गए हैं उसके हिसाब से मु कल से लड़के के हिस्से में दो चार बिस्वे आती जाएगी। यह ठीक है कि लड़के और लड़की का हक बराबर है, लेकिन मेरी यह

सुजै ान है कि जमीन का दाखलखारिज लड़कों के नाम हो, लड़की को तो उसके हस्बैंड के हिस्से में से हिस्सा मिलता है। यह ठीक है कि जो लड़की बगैर भाादी ुदा हो, उसको मां–बाप की जायदाद से हिस्सा होना चाहिए। लड़की के नाम दाखलखारिज होने से, सिवाए इसके कि मुकदमेबाजी हो, उलट–पलट करवाया जाए, और कोई फायदा नहीं है। लड़की का हक उस घर में है, जहां वो ब्याही जाती है। लेकिन एक्ट के तहत जिस घर में लड़की ब्याही जाती है, वहां से भी हिस्सा लेती है, और जिस घर में जाती है, वहां से भी लैती है, इससे तो ज्यादा फैगमैंटे ान आफ लैंड होती है, ज्यादा मुकदमेबाजी होती है, भाई–बहन का प्यार खत्म हो रहा है। स्पीकर साहब, आप अदालत में जाकर देखें, कितने मुकदमें, कितने केसिज भाई बहन के चल रहे है। स्पीकर साहब, कितने केसिज हैं, जो बाद में फर्जी वसीहत बनाई जाती है। मिने केसिज हैं, जो बाद में रजिसट्री करवाकर दोबार बहनें भाइयों के नाम भेजती हैं, इससे मुकदमेंबाजी बहुत ज्यादा हो गई। हिन्दू संस्कृति के मुताबिक बाप का जो प्यार लउ़की के साथ होता था, वह नहीं रहा। यह ठीक हे कि उनका हक बराबर है, ऐसे ही लड़का है, ऐसे ही लड़की है, लेकिन ऐग्रिकल्चरल लैंड की फैगमैंटे ान होने से, जमीन के टुकड़े होने से बात नहीं बनती, पैदावार तो पहले ही कम होती है, फिर टुकड़े–टुकड़ै होने से पैदावार कैस बढ़ जाएगी? यह तो और कम हो जाएगी। एक बैल के का त करने के लिए भी जमीन उनके पास नहीं रही। दूसरी बात है किसान

को फर्टीलाइजर और बीज देने की। किसान का उत्साह पैदा करने के लिए कि वह ज्यादा अनाज उगाए, फर्टिलाइजर और सीड की सबसिडी दी जाए, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। फर्टिलाइजर की कीमत दुगनी हो गई है, पैदावार और कम होती जा रही है। मैंने पहले भी गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुउ आपकी मार्फत सरकार से कहा था कि गेंहू की पैदावार कम होने के और भी कारण हैं। गेंहू की स्पोर्टिंग प्राईस जो, सरसों, चना वगैरा की निस्वत कम है। लोगों को जो, सरसो, चना पैदा करने के लिए कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कम बिजली लगती है, कम खर्च बोआई होती है और खाद नहीं डालनी पड़ती। 1972–73 में जो गेहूं हुआ था, उससे कम 1973–74 में हुआ। 1975 में अभी बारि ें भी हो गई है लेकिन फिर भी पिछले साल की बनिस्बत इस साल गेहूं कम होगा, क्योंकि बिजाई कम हुई है। इसका कारण यह है कि गेहूं पर जो किसान के पैसे लगते है, उससे आधे में, या तीन चौथाई खर्च में वह दूसरी फसलें पैदा कर सकता है। उन फसलों के भाव भी वही है। तो क्यों किसान गेहूं का त करेगा। उन जगहों पर जहां किसान के लिए कोई आलटरनेटिव नहीं है, जहां कोई दूसरी फसल हो नहीं सकती, वहां वह मजबूरी में गेहूं भले का त कर दे, वरना दूसरी जगह वह गेहूं का त नहीं करेगा। हमारे यहां तो किसान ने चने, जौ और कपास आदि जो वह बो सकता था, वह बोया है, लेकिन गेहूं उसने, का त नहीं किया है।

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं किसानों के कर्जे की बाबत बात कहूंगा। किसान को मार्गेज बैंक से जो कर्जे मिलते है, उनमें एक आईटम गहने की जमीन छुड़ाने, रहने की जमीन छुड़ाने का भी है। मेरे ख्याल में कोई 15 परसैन्ट कर्जा लोगों के पास रहन का होता है। आज कितने ही किसान ऐसे हैं, जिनहोंने अपनी जमीन गहने रखी हुई है, रहन रखी हई है, लेकिन मार्गेज बैंक से उन्हे कर्जा नहीं मिलता। इसी तरह से ट्यूबवैल के कर्जे की बात है। ट्यूबवैल का कर्जा हमारे यहां तो सिवाय साल्हावास ब्लॉक के सारे जिले का बन्द कर दिया है। पता नहीं वह क्यों बन्द किया गया है? मैं आपके द्वारा, स्पीकर साहब, ऐग्रीक्लचर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे कृपया इस बात को देखें कि यह क्यों बंद किया गया है? यह कर्जा तो बहुत जरूरी है। तो इस संबंध में सरकार से यही अर्ज है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्जे दिए जाएं, ताकि वे अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें।

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान की डिमांड के ऊपर एक और कहना चाहूंगा। आज जो पावर्ज हैं, वे हायर आफिसर्ज मैं सैन्ट्रलाइजड है। इससे इन ऐफि ाऐंसी भी है और कुरप ान भी है। एक टीचर अगर गलती करता है, गैरहाजिर है, इन–डिस्पिलिन फैलाता है, तो हैडमास्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से यदि पटवारी गलती करता है, तहसीलदार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से एक

कलर्क अगर गलती करता है, उसका सामना करता है, गालियां देता है तो बी.डी.ओ. उसका कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी अर्ज है कि अगर आप डिस्पिलिन लाना चाहते है, इनऐफि ाऐंसी और कुरप ान को खत्म करना चाहते है, तो पावर को डिसैन्ट्रेलाइज करें। अगर तहसीलदार को अख्तियार हो, तो पटवारी को सस्पैंड कर दें। उसको डर होगा, भय होगा कि उसका इमीजिएट आफिसर वह है। आज इस तरह की बात नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा टीचर हैडमास्टर का मुकाबला करते है। हमारे गांव में दो टीचरों ने हैडमास्टर पिटवा दिया बच्चों से। बच्चों को बरगला करके उन्होंने हैडमास्टर पर पथराव करवाया और उसको जख्मी कर दियां मुझे भी इस बात का पता लगा। मैंने डी.ई.ओ. को कहा। डी.ई.ओत्र ने इनक्वायरी करवाई और कह दिया कि हैडमास्टर का कसूर है। कितनी गलत बात है। बच्चों ने पत्थरों से भी ो तोड़े, हैडमास्टर को बच्चों से पिटवाया गया, बच्चों ने उसे चोटें मारी, लेकिन कहते हैं कि कसूर हैडमास्टर का है? मैंने पर्सनली कह करके उन दो टीचरो का तबादला करवाया। वे कुछ नहीं कर सकते, अगर हैडमास्टर के पास पावर्ज हों। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर आपने इनऐफि ाऐंसी और कुरप ान को दूर करना है, तो पावर्ज को सैन्ट्रलाईज करो।

श्री अध्यक्ष : देखिए, बात यह है कि आनरेबलमैंबर जब बोलते है तो आ ाा यह करते हैं कि बीच में उनको बन्द न किया

जाए। इसका तो फिर कायदा यही होगा, जैसे हाउस में पहल क्वै चन उठ चुका है कि मैं हाउस की सैन्स ले लूं और टाईम लिमिट स्पीचिज पर लगा दूं, प्रत्येक स्पीच की इतनी लिमिट होगी ताकि प्रत्येक मैंबर उतने ही टाईम में बोले, बीच में कोई रूकावट न कर और जब टाईम खत्म हो जाए तो खुद ही बैठ जाए।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, वैसे तो आप जैसा मर्जी करे। चाहे आप मैंबर के हिसाब से कर लें, या चाहे कुछ और कर लें, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर पार्टी के हिसाब से कर दें, तो ज्यादा अच्छा है। अगर एक पार्टी के और मैंबर नहीं बोलते तो भले ही एक मैंबर बोल ले।

श्री अध्यक्ष : क्या ठीक है यह बात?

(इस पर कोई नहीं बोला)

चौधरी मनफूल सिंह : स्पीकर साहब, अब मैं देहात की सर्विसिज की बाबात कुछ अर्ज करूंगा। स्पीकर साहब, जिन हालात में देहात के अन्दर बच्चे ि ाक्षा प्राप्त करते हैं, जिस किस्म के टीचर वहां पहुंचते है, उसके हिसाब से मैं तो यह कहूंगा कि वहां एजुके ान का स्टैंडर्ड सही नहीं है, बैटर एजुके ान उनको नहीं मिलती है। वहां एटमासफीयर इतना अच्छा नहीं है, जितना होना चाहिए। सरकार इस पर कृपया गौर करे। यह बात नहीं होनी चाहिए कि जिस टीचर के खिलाफ ि ाकायत हो, उसे झज्जर, नाहड, साल्हावास, नारनौल या महेन्द्रगढ़ भेज दिया जाए।

इसी तरह दूसरी सर्विसिज की बात है। अगर कोई पटवारी ठीक नहीं हैं, तो उसे नारनौल, महेन्द्रगढ़, झज्जर, नाहड़ या साल्हावास भेज दें, यह बात ठीक नहीं है। तो मेरी सरकार सक दरख्वास्त है कि देहात के अन्दर हमारे यहां बच्चो को एजुके ान के मामले में कम सुविधा मिलती है। चाहिए तो यह कि कंपिटिटिव एग्जामिने ान के लिए उनके कलए कोई कंसै ान हो, रूरल एरिया के लिए कोई रिजर्वे ान हो। उम्मीद है सरकार इस और भी ध्यान देगी। इन भाब्दों के साथ आपका स्पीकर साहब ज्यादा समय ने लेते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी सरजीत सिंह मान (ोरहदा) : आदरणीय स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले डिमांड नम्बर 2 जो इरीगे ान एंड पावर की है, उसके ऊपर बोल रहा हूं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो हमारी गवर्नमैंट ने इस बारे में जितना काम किया है, उतना भाायद ही किसी और गवर्नमैंट ने किया होगा। जहां तक नहरो का ताल्लुक है, बहुंत नहरे नई बनी है। बहुत अच्छा काम इस दि ाा में हुआ है, लेकिन इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर साहब को आपके द्वारा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में इस वक्त तीन भाूगर मिल्ज है, और उनके अपने जैनेरेटिंग सैट्स है जो पन्द्रह हजार यूनिट बिजली पैदा कर सकते है। वे भाूगर बनाने के लिए केवल पांच महीने चलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते है। गवर्नमैंट यदि चाहे तो उन तीनों प्लांट्स को पांच महीने के बाद भी चलाया जा सकता है, ताकि वे अपनी स्टेट के

लिए इलैक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें। और कुछ नहीं, तो नजदीक के भाहरों और देहात में कहीं न कहीं काम आ जाएगी। फिर स्पीकर साहब, मेरा सुझाव यह भी है कि बड़े–बड़े थर्मल प्लांट्स लगाने की बजाय यदि हम डिस्ट्रिक्ट हैडकवार्टरज पर छोटे–छोटे थर्मल प्लांट्स लगाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। बड़े प्लांटस तो पता नहीं कितने साल मैं लगेंगे छोटे प्लांट्स 6–6 महीने या साल–साल के अन्दर लग जाएंगे। मैं तो स्पीकर साहब, यह भी कहूंगा कि मैरेजिज और फंक ान्ज में जो बिजली लगती है, उस पर पाबंदी लगा दी जाए, ताकि वह दूसरे जरूरी कामों के लिए प्रयोग हो सके।

स्पीकर साहब, जहां तक लाईन लौसिज का ताल्लुक है, यह ठीक है कि वे हमारी स्टेट में सबसे कम हैं, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके, उनको और भी कम किया जाए।

रावी ब्यास के पानी के मुताल्लिक स्पीकर साहब, गुप्ता साहब ने कहा है कि 23 तारीख की मीटिंग में फैसला हो जायेगा। यह बात ठीक है लेकिन इस सम्बंध में मेरी गुजारि ा यह है कि जितनी जल्दी से जल्दी यह फैसला हो जाए, उतना ही अच्छा है ताकि हमें यह पता लग जाए कि कितना पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा।

स्पीकर साहब, प्राईस राइज के बारे में तो गवर्नमैंट से यह कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम कन्जयूमर गुड्ज के

प्राईस राइज को तो ये किसी न किसी तरह कंट्रोल करें, ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिल जाए। आज किसी भी चीज को ले लें, सीभी चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ रही है। सजै ान तो इस बारे में मेरे पास कोई है नहीं लेकिन मैं गवर्नमैंट से यही रिक्वैस्ट करूंगा कि जिस तरह से भी हो सकें, वह कम से कम कन्जयूमर गुड्ज की प्राईस को जरूर कन्ट्रोल करे।

इसके बाद स्पीकर साहब इंडस्ट्रीज की डिमांड आती है। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि मिनी स्टील और सीमेंट प्लांट्स लगने चाहिए। हमारे यहां तो महेन्द्रगढ़ में सीमेंट का पत्थर काफी है। अगर सरकार छोटे–छोटे प्लांट्स लगाने की कोि ा ा करे तो ये भी भाायद कामयाब होंगे और लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा।

ऐग्रीकल्चर की डिमांड का जहां तक संबंध है, इस बारे मैं स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि जहां तक हो सके, हमारी गवर्नमैंट को सैन्ट्रल गवर्नमैंट को प्रैस करना चाहिए कि जो भी प्राईस वह फिक्स करे, वह जरा टाईम से फिक्स करे ताकि जमींदार को टाईम पर पता लग जाए कि उन्हें किस चीज की क्या प्राईस मिलेगी, और वो उस चीज को बो सकें। सैन्ट्रल गवर्नमैंट को इस बार हमें प्रैस करना चाहिए और पहले प्राईस फिक्स करानी चाहिए। जमींदारों को यह पता होना चाहिए, कि इस चीज की यह प्राईस मिलेगी ताकि वे उसी चीज को कल्टीवेट करें।

स्पीकर साहब, एनीमल हस्बैंडरी के विशय मैं डिमांड है। इस बारे में सिर्फ यही कहूंगा, कि दूध की कीमत जरूर बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल दूध की कीमत बहुत कम है। अगद दूध की कीमत नहीं बढ़ेगी तो कौन गाय और भैंस रखेगा। जो आजकल दूध का भाव है, उससे तो चारे का भी खर्चा पूरा नहीं होता है।

फैमिली प्लानिंग के विशय में चौधरी मनफूल सिंह जी ने जो बात कही है, उससे मैं ऐग्री करता हूं। जब तक हम यहां हाउस मैं लेजिस्ले ान नहीं लाएंगे और सैन्टर से पास नहीं कराएंगे तब तक फैमिली प्लानिंग रूकने वाली नहीं है। यह जो भी हमें पैसा मिलता है, यह सारा ही बेकार में जाता है। मैं तो समझता हूं कि 60 साल से कम आदमी का आपरे ान नहीं होता है। इसलिए लैजिस्ले ान लाना बहुत ही जरूर है।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मुझे बता दें, टाईम मिलेगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको टाईम मिलेगा। अभी आपकी भी टर्न आ जाएगी।

चौधरी पीर चन्द : अध्यक्ष महोदय हमें बता दें।

श्री अध्यक्ष : जो आजाद मैंबर है, कभी नहीं बोलते हैं, उनको भी तो टाईम मिलना चाहिए। जो न गवर्नर एड्रैस पर बोलें

हैं, न बजट पर बोले है, न डिमांड पर ही टाईम मिला है इनको भी तो टाईम देना है।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब हमारा भी ख्याल रखें।

श्री अध्यक्ष : जिसकी जितनी स्ट्रैन्थ है, उसके हिसाब से टाईम मिलेगा। जितने आपके मैम्बर हैं, उतना ही टाईम मिलेगा।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के तो 14 मैम्बर थे, लेकिन अब दो ही रह गए हैं–(हंसी)

श्री अध्यक्ष : इसको मैं घटा–बढ़ा नहीं सकता।

डाक्टर ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो रोज से डिमांडज पर चर्चा चल रही है। पे तर इसके कि मैं डिमांडज नम्बर पांच और दस पर जो कि एक्साइज एंड टैक ोसन और हैल्थ के बारे में है, मैं अपने विचार रखूं, मैं जमहूरियत में अपोजि ान का हाउस मे क्या रोल होना चाहिए, इस बारे में एक मिनट के लिए अपने विचार रखना चाहता हूं। आ ाा है कि अध्यक्ष महोदय आप मुझे इंजाजत देंगे। स्पीकर साहब, आज हमारा दे ाा जम्हूरी दौर से गुर रहा है जैसा कि जम्हूरियत का तकाजा है, जम्हूरियत दो ग्रुपों में बंटी हुई है एक बरसरे–इक्तदार है दूसरा अपोजी ान ग्रुप। जहां तक दोनों ग्रुपों का ताल्लुक है, दोनों में इख्तलाफ रहता है, सोचने का ढ़ंग

जुदा–जुदा होता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि जहां अपोजी ान और बरसरे–इक्तदार ग्रुप एक दूसरे से मुतफिक नहीं है, तो बाहमी सहयोग भी इस नजरिए से न हो। दोनों ग्रुपों का सहयोग होला भी उतना ही जरूरी है जितना की इस दे ा के अन्दर जम्हूरियत की उपयोगिता को होना है। बरसरे इक्तदार ग्रुप अगर मनमानी करने लगे, अपोजी ान को नजर–अन्दाज करता चला जाए, तो ऐसी सूरत में डिक्टेटरि ाप जन्म लेती है। अगर किसी वजह से अपोजी ान धड़ा, अपोजी ान ग्रुप सरकार की मुखालफत करनी भुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में प्रान्त के विकास की रफ्तार, डिवैल्पमैंट की रफ्तार बड़ी हद तक ढ़ीली हो जाती है। इससे प्रांन्त का भला नहीं होता और न ही इस तरह से अपोजी ान का भला होता है। अपोजी ान भी सरकार को पूरा सहयोग दे। इसका मतलब यह नहीं कि अपोजी ान अपने उस हक से दसतबरदार हो जाए, जो उसका अपना पैदाय ी हक है, जो जम्हूरियत की देन है। अपोजी ान का यह हक है। किसी की यह ताकत नहीं की उसको हटा दे। सरकार की यह ताकत नहीं की उसे छीन ले, मगर उसके लिए अपोजी ान का भी कुछ तरीका होना चाहिए। कुछ ऐसे सेहतमनदाना ढ़ग से अपोजी ान का प्रोग्राम होना चाहिए कि वह सरकार को कि्टिसाइज करे, सेहतमनदाना ढ़ंग से करे। अगर अपोजी ान सेहतमनदाना ढ़ंग से करती है, तो अपोजी ान को मजीद मजबूती मिलती है अपोजी ान मजबूत होती है, साथ ही विकास के कामों का बढ़ावा मिलता है, प्रान्त की ज्यादा से ज्यादा डिवैल्पमैंट होती

है। उसके साथ अपोजी ान यह न समझ लै, कि जहां विकास को बढ़ावा देने से सरकार मजबूत होगी, विकास होते हुए भी बहुत सी ऐसी बातें है, जो सरकार को ले बैठती हैं। सरकार के अन्दर जो एलीमैंट होते हैं, उन पर काफी डिपैन्ड करता है। मैं अपोजी ान बैंचिज पर बैठा हूं, अपोजी ान का मैंबर होने के नाते हमें सरकार को कि्टिसाईज करने का पूरा हक है और यह हक हमारा हमें जम्हूरियत ने दिया है। हमें कोई खैरात नहीं मिली है, लेकिन हमें यह सोचना है कि जब हमें सरकार को कि्टिसाइज करे, तो हमारा कि्टिसिजम सेहतमनदाना हो, हैल्दी कि्टिसिजम हो मुखालफत बराय मुखालफत न हो। सरकार का कि्टिसिजम इसलिए न हो कि सरकार को गिराना है, बल्कि इसलिए हो कि हमें जम्हूरियत में अपना रोल अदा करना है और वह रोल सेहतमन्दाना अच्छा रोल अदा करके भी सरकार को हम गिरा सकते है। अगर घटिया तरीके अपनाएंगे, करैक्टर असैसिने ान के लिए झूठे अल्जामात लगाएंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, तो मैं समझता हूं इस से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि सरकार को ताकत मिलेगी। बदकिस्मति हमारी यह है कि विपक्षी दल के अन्दर यकजैहती यूनिटी नहीं है। आज अपोजी ान दस जगह पर बंटी हुई है। अपोजी ान है जरूर मगर अपोजी ान बराय नाम है। हम यह देख नहीं पाते कि हाउस के अन्दर कोई अपोजी ान है या सही अपोजी ान का रोल अदा कर रही है। (इस समय सभपतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ई वर सिंह पदासीन हुए) माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा ट्रेजरी बैंचिज पर

बैठे हुए अपने भाइयों से रिक्वैस्ट करूंगा कि अपोजी ान के जजबात का ख्याल रखें और जम्हूरियत जो कि पार्लियामैंटरी सिस्टम देती है, उसके साथ ही हमें फ्रीडम आफ थाट भी देती है। फ्रीडम आफ थाट से मतलब है कि अपोजी ान को बोलने और तहरीर व तकरीर करने की पूरी आजादी है जितनी की ट्रेजरी बैंचिज को है। चेयरमैन साहब, मेरी आपके द्वारा लीडर आफ दी हाउस से और ट्रेजरी बैंचिज से और अपने अपोजी ान के भाइयों से दरख्वास्त है कि वे सेहतमनदाना ढ़ंग से क्रिटिसिजम करें।

चेयरमैन साहब, आज से 8 साल पहले हरियाणा प्रान्त वजूद में आया। उस वक्त का हरियाणा हजारों सालों का पिछड़ा हुआ हरियाणा था। हजारों सालों का पसमान्दा सूबा था। आज से 8 साल पहले जो सरकार एस.वी.डी. की बनी, जिसका मैं भी मैंबर था, और सदन में कुछ और भाई भी विराजमान हैं, जो एस. वी.डी. के मैंबर थे, मगर वह एस.वी.डी. की सरकार अपनी नाअहलियत और भ्रश्टाचार की वजह से पहले ही साल दम तोड़ गई। उसके बाद सन्1968 में दूसरी सरकार बनी, जिसकी रहनुमाई चौधरी बंसी लाल के हाथों में आई। जिस वक्त चौधरी बंसी लााल चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने इस प्रान्त की सरकार को अपने हाथों में लिया उस वक्त यह सूबा इतना पिछड़ा हुआ था कि हर मैदान में पिछड़ा हुआ था। जहां तक मैं समझता हूं कोई भी मैदान ऐसा नहीं था, जिस मैदान में हम यह कह सके कि हम आगे थे या यूनाइटिड पंजाब के जमाने में हमारे इस रीजन को,

जिसको आज इंडीपैंडैंट हरियाणा स्टेट कहा जाता है, किसी भी प्रकार की डिवैल्पमैंट का मौका मिला हो। इसके बाद जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने मुख्य मंत्री बनकर इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया, अपने कंधौं पर लिया, वैसे हरियाणा के विकास की रफ्तार बढ़ने लगी, और बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। जिसके नतीजे में हजारों साल की पसमान्दगी को बेहो ा करता हुआ यह सूबा बड़ी तेजी से विकास के मैदान में आगे बढ़ा। तमाम हरियाणा इलैक्ट्रिफाई हुआ, सड़कों का जाल फैला, जरई और सनअती मैदान में हरियाणा ने बड़ी भारी तरक्की की। इसके साथ साथ नए अस्पताल खुले, नए स्कूल खुले, कालेज खुले, बन्ध बनें, ट्यूबवैल लगे और कुएं खुदे। गर्जे कि एक ऐसा सैलाब आया कि हम उसे तामीरी सैलाब से मसावत दे सकते है, आज हरियाणा हिन्दुस्तान के नक ो पर अपने लिए एक अहम मुकाम बन चुका है और मैं समझता हूं कि यह सब कुछ इतना विकास, इतनी तरक्की या इतनी खु ाहाली जो इस सूबे में आई, उसका केडिट अगर किसी को जाता है, तो यह आनरेबल चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल को जाता है। उनको को ही यह वाहिद केडिट जाता है। चेयरमैन साहब, हमारे दे ा में सताजी हालत किस हद तक खराब हो चकी है इस बात का अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज हमारे दे ा के अन्दर खाने–पीने की चीजों के अन्दर मिलावट करने का एक भारी सैलाब आ चुका है। आज खाने–पीने की कोई भी चीज खालिस रूप के अन्दर हमारे हाथों तक नहीं पहुच सकती। हम यह कह सकते है कि हमारी इस स्टेट के

अन्दर या हमारे दे ा के अन्दर मैडीकल साईंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जहां इतनी भारी तरक्की हुई, है, वहां उस तरक्की के साथ–साथ यह भी हुआ है कि आज अगर मैडिकल साईंस को हमारे अस्पतालों के अन्दर कुछेक दवाइयों की जरूरत है, तो वे भी लोगों को असली दस्तयाब नहीं होती। आप ही देखिए यह कितनी भारी बुराई है। मैं यह चाहूंगा कि इस बुरी आदत का खात्मा करने के लिए सरकार तेजी से हरकत मैं आए और इसके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे यह रूक सके। जहां तक मैं समझता हूं, मैं इस बारे में एक सुझाव दे सकता हूं। जब तक सरकार इसके लिए कोई वाजह कानून नहीं बनाएगी, या मौजूदा कानून के अन्दर कोई इस प्रकार की कोई अमैंडमैंट नहीं करेगी कि जिससे यह जुर्म बड़ा संगीन और नाकाबले जमानत हो जाए, तब तक यह बुरी आदत खत्म नहीं होगी। आज हालत यह है कि अगर कोई खालिस चीज मिल सकती है, तो वे दो चीजें ही है, एक हवा और एक धूप। इन पर मिलावट करने वालों को कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं तो हो सकता है ये दोनों चीजे भी खालीस न मिलतीं। मैं आपके द्वारा सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगाा कि सरकार मिलावट और नकली अदबीयत के बारे में एक ऐसा जामा कानून बनाए कि यह तुर्म काबले मदाखलत पुलिस और नाकाबले जमानत हो और इस पर संगीन सजा दी जा सके। चेयरमैन साहब, दूसरी बात जो मैं कहूंगा वह टैक्स इवेजन की बात। टैक्स की चोरी हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी का मामूल बन गई है और मैं समझता हूं कि इस हमाम में हम सब नंगे हैं। कारोबारी लोग

अक्सर अपनी आमदनी कम दिखाकर बहुत कम टैक्स देते हैं या कुछ हालात में तो ये लोग बिल्कुल ही टैक्स नहीं देते। चेयरमैन साहब, मुलाजम पे ाा लोग अपनी आमदनी को जो कि एक जाहिर आमदनी है, उसको तो नहीं छुपा पाते, उस पर तो वह टैक्स दे देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुलाजमा पे ाा लोगों को जो ऊपर की आमदनी होती है, उस पर वे लोग भी टैक्स नहीं देते। इस पैसे को कोई भी मुलाजम नहीं बताता चाहे वह कोई डाक्टर हो, या चाहे वह कोई वकील हो। यह चीज इतनी फैली हुई है कि हम सभी इस बीमारी का ि ाकार हैं। इसी वजह से आज यह हालत है कि दे ा के अन्दर जितनी भी डिवैल्पमैंट है, जितना भी विकास है, वह सब एक ऐसी स्टेज पर आ गया है कि सरकार जाम हो कर रह गई है। अब मैं अपनी स्टेट को लेता हूं। हमारे बजट के अन्दर 17 करोड़ के लगभग का घाटा है। 16 करोड़ 99 लाख रूपये का घाटा है। मैं नहीं समझता कि यह 16 करोड़ 99 लाख रूपए का घाटा कैसे पूरा होगा? सरकार के पास इसका एक ही तरीका है कि सरकार और नए टैक्स लगाए। पहले ही टैक्सों ने हमारी कमर इतनी तोड़ दी है कि हम मजीद और टैक्सों का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। अगर और वाजिद टैक्स लगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी माली हालत इसकी इजाजत नहीं देती कि हम और बोझा डालें। अगर सरकार इस इवेजल को कन्ट्रोल करे, टैक्सों की चोरी को रोके तो मैं समझता हूं कि यह जो 17 करोड़ का घाटा या खसारा है, यह 34 करोड़ के मुनाफे मे तबदील हो सकता है, ब ार्ते कि सरकार इसके लिए हंगामी

इकदामात कर और इवेजल को रोकने के तरीकों को पूर्ण रूप से अपनाए। चेयरमैन साहब, इस बारे में मेरा एक छोटा सा गुर है जिसे मैं सुझाव के तौर पर सरकार के सामने रखना चाहता हूं। कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इवेजन कहां होती है? जो मुलाजम पे ाा होता है, उनकी आमदनी के बारे में तो मैं नहीं कहता कि हम किस तरीके से उसको चैक कर सकते है, मगर बिजनैस कम्युलिटी की तरफ से चूंकि बहुत भारी टैक्य इवेजन होता है इसके लिए मेरा सुझाव है कि म्युनिसिपल लिमिट्स के अन्दर जितना रा–मैटीरियल आता है, सरकार म्युनिसिपल कमेटी की औक्ट्राय पोस्टस और हैड–आक्ट्राय आफिसर पर अपनी पूरी नजर रखें और वहां से यह फिगर्ज कुलैक्ट करें कि जितना रा–मैटीरियल म्युनिसिपल हदूद के अन्दर दाखिल हुआ और जितना माल तैयार होकर म्युनिसिपल हद से या कारखानों से बाहर जाता है, उस पर भी सरकार पूरी नजर रखे। सरकार ट्रांसपोर्ट और रेलवेज पर पूरी नजर रखे और यह देखे कि कितना माल ट्रांसपोर्ट से या रेलवेज से बाहर जाता है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है और मेरा वह सुझाव यह है कि सरकार को ऐक्साईज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट माल को बाहर ले जाने के लिए तब तक क्लीयरैंस सर्टिफिकेट न दे, जब तक कि वह टैक्स पेड सर्टीफिकैट नहीं दे देता। जब तक वह टैक्स पैड सर्टिफिकेट नहीं देता, तब तक कोई भी ट्रांसपोर्ट या रेलवेज उस माल को लोड ने करें। जिसके पास टैक्स पैड सर्टिफिकेट नहीं हो, उसका माल किसी भी ट्रांसपोर्ट या मालगाड़ी में लोड न करे। अगर

सरकार इन दो बातों पर सख्ती बरते और सरकार पूरे तरीके से इवेजन को काबू में करने लगे, तो इससे बहुत जल्दी हमारी हरियाणा स्टेट के अन्दर जो इवेजन की वजह से खसारा है, वह खत्म हो जाएगा और अगले साल का जब बजट आएगा तो वह बजट इताफे का बजट होगा। चेयरमैन साहब, आपकी तरफ से मुझे इ ाारा हो गया है, इसलिए इल लफ्जों के साथ मैं खत्म करता हूं।

चौधरी चांद राम (बवैन––अनुसूचित जाति) : चेयरमैन साहब, आप मुझे यह बता दें कि कितना समय मुझे दिया गया है? मैं तीन मैंबरों की तरफ से बोल रहा हूं।

चेयरमैन : आपको बीस मिनट दिए गए हैं।

चौधरी चांद राम : तीन मैंबरों की तरफ से बोल रहा हूं और सिर्फ बीस मिनट?

चेयरमैंन : आप बोलना तो भ्रुरू करें।

चौधरी चांद राम : चेयरमैन साहब, जब बजट स्पीच को देखतें हैं, बजट को देखते हैं, और पिछले साल की तरफ नजर डालते है तो हमारे सामने एक यह धोखा मात्र सा है। धोखा मात्र इसलिए कहता हूं कि हमारे वित मंत्री जी ने भ्रुरू में कहा कि मैं भ्रुरू में कहता हूं कि कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा और इसलिए मैम्बरान साहिबान को आराम से बैठ जाना चाहिए, ठंडे वातावरण में बैठ जाना चाहिए और आखिर में इन भाब्दों में कहा

कि 16.99 करोड़ का घाटा बगैर टैक्स लगाए अनकवर्ड रखा गया है। कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया कि इस को किस तरह से पूरा करेंगे। एक बात उन्होंने सुझाई कि हमें रिलीफ को पैसा भारत सरकार से मिलेगा और हमारा केस बड़ा पक्का है। हमारे यहां एक टीम आई हुई है, उसकी हमदर्दी हमारे साथ है। वह पैसा मिल जाएगा तो हमारा घाटा पूरा हो जाएगा। पिछले साल भी 16 करोड़ का घाटा दिखाया गया था लेकिन बाद में टैक्स पर टैक्स लगाए गए जिनका इसमें भी थोड़ा सा वर्णन है और आप देखें कि अब भी कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। भाायद इस वजह से टैक्स ने लगाए हों कि तीन बाइ–इलैक ान होने वाले है और हो सकता है कि पार्लियामैंट के भी सनैप पोल हो जाए। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि कोई टैक्स नहीं लगाएंगे लेकिन बीच में एक डोज दे दी। आपने पिछले साल यात्री किराया 2.90 करोड़ का बढ़ाया। आपने यह किराया 1.45 करोड़ बढ़ाया। आपने मार्किट फीस 2.90 करोड़ की बढ़ाई और जो आपने स्टामप ड्यूटी बढ़ाई वह अलग है, आपने जो व्हीकल टैक्स बढ़ाया वह अलग है और जो आपने बिजल का रेट बढ़ाया वह अलग है। यानी आपने तीनों करो से 8.95 करोड़ रूपया टैक्स बढ़ाया और यह अमीरों पर नहीं लगा यह गरीबों पर लगा। बजट की एक बुनियादी चीज होती है कि उसमें दो–तीन चीजें जरूर देखनी चाहिए। एक तो यह है कि बजट जो है, वह आमदनी और खर्च बताए। आमदनी और खर्च में बैलेन्स रखना चाहिए। अब तक सरकार घाटे का बजट पे ाा करती रही है।

यह तो हो सकता है कि कभी किसी साल में घाटे का बजट आ जाए। बजट तैयार करने वालों की यह कोई खूबी नहीं है कि पहले तो उनको ठीक याद न हो और आखिर में उन आइटम्ज पर टैक्स लगा दे। दूसरी बात बजट की यह होती है कि उन लोगों पर टैक्स लगता है जो उनको बर्दा ात कर सकें। अमीरों पर टैक्स लगना चाहिए। सो ालिज्म फैलाने का या नाबराबरी दूर करने का बजट का तरीका है और अमीरों से लेकर गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम उठाने हों, उन पर खर्च किया जाता है। अगर हम देखें तो पांच–छह साल के अन्दर गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर हो रहा है। आप यह कहते हैं कि पर–कैपिटा इन्कम हरियाणा के अन्दर बढ़ी है। अगर हम 1950–60 के आंकड़ों को देखें तो रियल इन्कम बढ़ी नहीं हैं, बल्कि रियल इन्कम घटी है। लेकिन आप घमण्ड करते हैं कि हरियाणा की पर–कैपिटा इन्कम बढ़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस छह साल में चौधरी बंसी लाल का राज्य रहा है। तीन चार महीने पंडित भगवत दयाल का रहा है और कुछ टाईम के लिए राव बिरेन्द्र सिंह का रहा। सब से ज्यादा समय के लिए चौधरी बंसी लाल का रहा है और इस पीरियड को देखें कि कितनी आमदनी बढ़ी है। मैं आपके सामने फिगर्ज रखना चाहता हूं कि 1967–68 में हमारी आमदनी 6,181 लाख थी। आज हमारी जो आमदनी है, वह 196 करोड़ 51 लाख है। आप अन्दाजा लगाइए कि हमारी इतनी आमदनी बढ़ी है और खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ा है। 1967–68 में खर्चा 5,532 लाख था और आज 181 करोड़ 30

लाख है। अब आप आमदनी और खर्च का हिसाब देखें कि आमदनी भाुरू में थी 61 करोड़ और वह बढ़ कर आपके पास 196 करोड़ हो गई। अब सवाल यह है कि टैक्स लगााने से आमदनी बढ़ी या लोगो की टैक्स पे करने की सामर्थ्य बढ़ी, लेकिन अगर हम बजट एट ए ग्लांस देखें तो इसमें कई आईटम है, जैसे इन्कम टैक्स जो भरत सरका का है, उससे हमें 1967—68 में आमदनी होती थी, वह थी 285 लाख और आज वह आमदनी 943 लाख है। प्रोफै ान टैक्स से 1976—68 में आमदनी थी, वह 16—17 लाख थी और आज वह पचास लाख है यानी तीन गुनी। एस्टेट डयूटी 1967—68 में आठ लाख थी और आज 17 लाख है। लैण्ड रेवैन्यू 1967—68 में 143 लाख था और आज 425 लाख है और पिछले साल 510 लाख था यानि तीन गुणा के करीब। इम्मूवेबल प्रापर्टी टैक्स से 1967—68 में आमदनी थी 32 लाख और आज वह है 70 लाख यानी दुगनी और पिछले साल यह आमदनी थी एक करोड़। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रे ान फी से आमदनी 1967—68 में थी 359 लाख और आज 796 लाख है जो दुगनी हो गई। स्टेट एक्साइज ड्यूटी से आमदनी 626 लाख थी और आज वह दो हजार लाख हो गई यानी तीन गुणा से ज्यादा हो गई। हमारा स्टेट भोयर आफ यूनियन एक्साईज डयूटिज में था 426 लाख और आज हमारा भोयर है 1255 लाख। सेल्ज टैक्स से 1967—68 में हमें आमदनी थी 954 लाख और आज वह 3760 लाख हो गई है यानि यार गुणा आमदनी हो गई। मोटर गाड़ियों पर1967—68 में टैक्स था 58 लाख और 1968—69 में वह 80 लाख था और आज

610 लाख है यानी दस गुणा के करीब हो गया। इलैक्ट्रिसिटी डयूटी से जो आमदनी थी, वह 1968–69 मैं 125 लाख थी और आज वह 397 लाख है। आप अन्दाजा लगाएं कि हमारी स्टेट की आमदनी कितनी बढ़ी है। वह तो बढ़नी ही थी, लेकिन आपने ज्यादा टैक्स लगा कर आपने लोगों पर बोझ डाला। आपकी खूबी इस बात की थी कि जो आपने टैक्स इकट्ठा किया उसके लिए आपकी स्टेट का इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टेट की बुनियाद, स्टेट की क्षमता कितनी बढ़ी है उस समय के लिए जब कि कोर्अ आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई कहत पड़ जाए, बाढ़ आ जाए। इस टैस्ट में आप बिल्कुल फेल हो गए।

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) कहा जाता है कि हमारा सूबा कृशि प्रधान है। हमारी ऐग्रीकल्चर के अन्दर 1968–69 में 27.64 टन पैदावार थी और 1969–70 में यह पैदावार 46.26 लाख टन हो गई। यानी एकदम 18.19 लाख टन ज्यादा हो गई। इसका क्रेडिट यह सरकार नहीं ले सकती क्योंकि आज अगर कोई भी बात होती है तो उस का असर एक दो साल बाद होगा। जो सबसे पहले सरकार थी, उसने कई कार्य किए होंगे। आपकी सरकार 1968–69 के बाद आई और उसके बाद प्रोडक्शन घटती गई और आज आप ने कहा कि हम इतनी तरक्की कर गए। पिछले साल 38.32 लाख टन यानी साढ़े सात लाख टन सालाना के हिसाब से खेतीबाड़ी की प्रोडक्शन में कमी हुई। तो सारे सूबे को यह आपकी देन है। एक तरफ तो आपकी पैदावार घटे

और दूसरी तरफ आप कहें कि हमने इतनी प्रगति कर ली। यह बात बनती नहीं है। फिर आप कहते हैं कि उस वक्त 29 हजार ट्यूबवैल थे अब हमने 1 लाख 33 हजार कर दिए, हमने नहरों में पानी छोड़ दिया, हमने नहरें पक्की करवा दीं। अभी फूल बरसाए जा रहे थे कि चौधरी बंसी लाल ने यह यह तरक्की के काम किए। इन्होंने जो तरक्की की है, वह यह है कि इन्होंने झीलें बनवाई, होटल और मोटल बनवाए, मौज मेलें की चीजें बनाई जैसे रैस्ट हाउस और डाक बंगले है। यह सरकार आज टट्यिों के अन्दर पंखें लगवा रही है, क्योंकि इन वजीरों की रफा हाजत तब तक नहीं हो सकती जब तक टट्यिों में पंखें न हो। अंग्रेज इस मुल्क में आया था वह भी गर्म हवा में काम करता था, लेकिन ये बागड़ के लोग जिनको खजूर के पंखे नसीब नहीं होते थे, आज वे कहते है कि टट्यिों के अन्दर पंखें लगने चाहिए। ये कहते हैं हमने बहुत तरक्की की। आज आप बिजली के बारे जमींदार से पूछ कर देखिए कि क्या हालत है। कितने घंटे बिजली मिलती है। बिजली के बारे में यह बताया जाए कि इतने रोड़ टैक्स लगाकर, इतनी आमदनी लेकर आपने कितनी बिजली पैदा की? जब पंडित भगवत दयाल की मिनिस्टरी थी, तो उस वक्त कहा गया था कि पानीपत और फरीदाबाद में थर्मल प्लांट लगाऐ जाएंगे। यह बात सन् 1966–67 की है। तो मैं वित मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सात साल सोए रहे? अब आप कहते है कि फरीदाबाद का ताप बिजली घर मुक्कमल होने वाला है और पानीपत के प्लांट का काम चल रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले

सात सालों में कितनी कीमतें बढ़ गई है? आप यह कहते है कि हमने इतना पैसा बिजली पर खर्च किया। ठीक है, वह आपने सामान खरीदने और बिजली के फैलाव पर किया हैं, लेकिन बिजली पैदा करने के लिए क्या किया गया? आज हालत यह है कि जब कभी प्राकृति का कोप हो जाता है तो आप जमींदार की मदद नहीं कर सकते। आज फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, सोनीपत और जितनी भी जगहों पर कारखाने लगे हुए हैं, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर वर्करों की रिट्रंचमैंट हो रही है इसका कारण यह है कि आपके पास बिजली नहीं है और बिजली न होने के कारण आप कारखानों को बिजली नहीं दे पाते और बिजली के अभाव के कारण कारखाने बंद पड़े है। आप हर जगह जाकर भााबासी मांगते हैं कि हमने बड़ा भारी तरक्की का काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद नहरों की बात आई। एक के बाद एक स्कीम में तबदीली होती जा रही, हर गांव में आपने बिजली चमका दी जैसे बादलों में बिजली चमकती है। चौधरी बंसी लाल जी ने किसानों को कहा कि मैं तुम को इतनी बिजली और पानी दूंगा कि तुम खुदा को भूल जाओगे। इन्होंने खुदा को तो क्या भुलाना था, लेकिन खुद ही हमें भूल गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अगर किसी गांव मे बिजली चमकती है तो वह बादलों कीतरह चमकती है। आज जब जमींदार ट्यूबवैल चलाने के लिए खेत में जाता है, तो टयूबवैल तक पहुंचते–पहुंचते बिजली खत्म हो जाती है। यहां पर मैंने एक सवाल पूछा था कि

जमुना पर डैम बनाएंगे? जब हरियाणा बना था, तो उस वक्त यह डैम 63 करोड़ रूपए में बन सकता था, लेकिन अगर आज बनाने लगे तो 150 करोड़ रूपए से ज्यादा लगेंगे। तो यह किसकी जिम्मेदारी है? मैं मानता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब की सैन्टर में बड़ी पहुंच है और श्रीमति इंदिरा गांधी इनको बड़ा मानती है, इनको बहुत अच्छा सर्टिफिकेट देती है। अभी यहां रोहतक में किसान मेला हुआ तो वहां पर ट्रकों में लाकर लोगों को इकट्ठा किया गया। वहां पर एक किसान ने कहा कि आप हमें उपदे ा देते है कि खेती की पैदावार ज्यादा बढ़ओ और हम आपसे मांग करते हैं कि आप हमें पानी और बिजली दें हम पैदावार बढाएंगे। अगर बिजली और पानी नहीं दिया जाएगा और सिर्फ उपदे ा ही दिए जाते रहेंगे तो पैदावार कैसे बढ़ सकती है? ऐसा कह देने पर उस बेचारे किसान की बहुत बुरी हालत हुई और उसे वहां से बाहर निकाला गया और पीटा गया। आप कहते है कि बिजली और पानी की कमी सन् 76 में पूरी हो जाएगी। जुई लिफ्ट स्कीम बन रही है, जवाहर लाल नेहरू कैनाल बन रही है। आपने साढ़े तीन सौ फीट पानी ऊंचा फैंकना है तो बिजली आप पैदा करेंगे वह तो लिफ्टों में ही इस्तेमाल हो जाएगी, वह जमींदारों के इस्तेमाल नहीं आएगी। आज बिजली आपको चाहिए आप उससे कम बिजली पैदा कर रहे है और फिर कहा जाता है कि हम बिजली ज्यादा पैदा कर रहे है। तो अगर मैं कोई और बात करूं तो कहेंगे कि चांद राम सेहतमनदाना बात नहीं करते। मैं जानता हूं कि ताकत का न ाा हो और जब बुखार ज्यादा चढ़ा हो, तो

कुनीन की गोली देनी पड़ती है और जब बीमार उसे खाता है तो उसे वह कड़वी लगती है।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी : सब इनकी वजारत थी, तो क्या ये भी कुनीन की गोली खाते थे?

चौधरी चांद राम : तो अब मैं पानी के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने कितना पानी दिया? जितना पानी हमारे पास 1966–67 में था आपने उसी को इधर–उधर मोड़ा है। आपने किसी नहर का मोरा तंग कर दिया है। किसी का ऊंचा कर दिया है। उनका पानी कम करके आपने पानी आगे भेज दिया। फिर इन्होंने एडमिट किया कि करनाल पानीपत और कुरूक्षेत्र में बहुत मीठा पानी है, जिससे कि बड़ी अच्छी खेती हो सकती है। इन्होंने सात आठ सौ फुट गहरी खुदाई की, जिसकी वजह से तीन प्राइवेट ट्यूबवैलों पर असर पड़ा, तो क्या कोई इस चीज की इनक्वायरी करने वाला है। आज उस जमींदार के टयूबवैल सूख गए है तो यह कोई अच्छी पालिसी नहीं है कि to rob Peter to pay Paul एक उजड़े और एक बने वाली बात कर रहे है। आज आप क्या कह रहे है कि एक का पानी कम कर दिया और वह दूसरे इलाके को दे दिया। आपकी पैदावार घटने का कारण यही है कि जो पैदावार करने वाले इलाके थे, आपने उनका पानी घटा कर दूसरे इलाके जहां पैदावार नहीं होती, उनको दे दिया हैं, इसलिए न उधर कुछ उपजा न इधर। इसी तरह जहां बिजली ज्यादा मिलती थी, वहां कम हो गई और जहां बिजली नहीं थी

थोड़ी उधर भेज दी, ऐसा करने से पैदावार किसी तरफ भी नहीं हो सकी। नहरी इलाकों में इन्होनें पहले तो जमींदारों का बीज जमीनों में गिरवा दिया लेकिन बाद में एक आधा पानी देकर और पानी नहीं दिया जिसकी वजह से उन बेचारों का बीज भी सूख गया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हम यह भूल रहे है कि हरियाणा को बने हुए करीब आठ साल हो गए और आठ साल मैं हम अपनी राजधानी का फैसला नहीं कर पाए और आज हम किराए की जगह पर बैठे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने एवार्ड दे दिया कि पांच साल में हरियाणा अपनी राजधानी बना ले और चण्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा तो क्या मैं इस सरकार से पूछ सकता हूं कि इसने फाजिल्का अबोहर लेने के लिए क्या कुछ किया है? यह दसियों लाख आदमी देहली ले गए और कई स्टूडैन्ट्स मरे इस चंडीगढ़ के सवाल के ऊपर लेकिन उनकी कुरबानी अकारत जा रही है। 29 जनवरी को पांच साल पूरे हो जाएंगे तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके पास क्या जवाब है कि आप आज तक हरियाणा को नई राजधानी नहीं दे सके? कहीं बनाते और मैं तो समझता हूं कि किसी सैन्ट्रल प्लेस में बना दो जो हरियाणा के बीच में हो तो सारा हरियाणा इकट्ठा रहेगा लेकिल अगर किसी ऐसी जगह बना दी जो किसी को अच्छी लगती या फलां को प्यारी लगती है तो आप हरियाणा का नुकसान कर जाएंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजधानी के मामले मैं और फाजिल्का अबोहर के मामले में तुरन्त कदम उठने चाहिए, आखिर वह प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड है उस पर अमल होना चाहिए। यह वह प्राइम

मिनिस्टर है जिसका सारे दे ा में नाम है दूसरे दे ाों में नाम है, वह जब इल दो स्टेट्स के झगड़े पर अपना अवार्ड दे चुकी है तो क्या आप मैं उस अवार्ड का इम्प्लीमैंट करवाने की हिम्मत नहीं है और क्या हरियाणा सरकार इतनी कमजोर है कि उसके साथ अन्याय होता रहेगा और उस हरियाणा के लोगों के साथा अन्याय होता रहेगा, जो वीरों की भूमि है। यह हरियाणा दे ा की रक्षा के लिए फौजी भेजता है दूसरे प्रदे ाों को जो कमी वाले है, अनाज पैदा करके देता है, आज यह हरियाणा दूसरे नम्बर की सरप्लस स्टेट है यह कपास पैदा करती है, गन्ना, धान और आलू पैदा करती है और दे ा को खु ाहाल बनाने में बढ़–चढ़ कर हरियाणा हिस्सा ले रहा है तो फिर भी वह नई राजधानी के बगैर और फाजिल्का अबोहर के बगैर रहे इसके साथ इन्साफ नह हो, उसके जायज हिस्से से वंचित रखे, वह पानी, बिजली जो उसके हिस्से की है उसके बगैर रहे तो इसका मतलब हम क्या लें क्या यह न लैं कि यह सरकार इतनी कमजोर है कि वह न्याय भी नहीं ले सकती? यह सवाल है जो इनके ध्यान में होने चाहिएं। आज मैंने एक सवाल पूछा कि कितने आदमी हरियाणा में दफा 107/151 में गिरफ्तार किए गए है। मैं अर्ज करता हूं कि ऐसे ऐसे मुअजज आदमी जो एक–एक हजार मन गेहूं पैदा करते है जिन का पोलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ इस डर से कि उनकी बी. एल.डी. से हमदर्दी है। जयप्रका ा जी देहली में आए है और कुरूक्षेत्र में आए है इसलिए उन मुआजज आदमियों को खेतों मैं काम करते हुए गिरफ्तार किया गया। मैं किस–किस के नाम लूं

और उनके नाम ले कर अपने आदमियों को मरवाना भी नहीं चाहता। रोहतक में एक जलसा हुआ। वहां एक बहुत माने हुए श्री महेंद्र सिंह वकील है, मुअजज आदमी है, लेकिन उनको हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। कार हमारे दफ्तर के सामने से ले जाई गई फिर कहा गया कि कार चोरी नहीं की। लेकिन मैं क्या कहूं और हम इस बात के लिए तैयार है मैं एक ऐसे झगड़े मैं से निकला था जो हरिजन आन्दोलन के नाम से म ाहूर है जो 113 दिन तक चला था और जिस में 22 हजार आदमी जेल में गए थे। हमारी संघर्श समिति की दस मांगें थी और वह दस मांगें गवर्नमैंट के गजट में छपी। चीफ मिनिस्टर साहब ने 17 दिसम्बर 1973 को ब्यान दिया कि दो कमेटियां पहले बन चुकी है अगर समझते हो कि यह नाकाफी है तो एक एड–हाक बनाएंगे और इन मांगों को पूरा करेंगे और सब के बीच मित्रता पैदा करेंगे यह इनके लफ्ज हैं, उस वक्त के लेकिल जो मित्रता पैदा करने की बात हुई वह नजर नहीं आई और इस बारे में मैं तो यह कहता हूं कि भाई फूल सिंह कटारिया ने जो कल यहां पर तकरीर की वह सारे मैंबरान और वजीरों में बांट दी जाए। मैं ही नहीं कहता वह भी कहते है कि एक रूपया फी साल हरिजन के हिस्सा में नहीं आता है, हरिजनों के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं, उनके लिए भेड़ बकरी चराने के लिए कोई चारगाह नहीं, प ुपालन के लिए कोई सुविधा नहीं, चारगाह नहीं। हमारे गवर्नर साहब ने अपने एक अभिभाशणा में तीन चार साल हुए कहा था कि डेढ़ लाख एकड़ सरपलस जमीन निकलेगी वह तमाम हरिजनों को देंगे।

उसके बाद जो अभिभाशण आजा है, उसमें कहा गया कि नहीं डेढ़ लाख नहीं चालीस लाख एकड़ थी और यह जमीन देकर इन्होंने हातम ताई की कब पर लात मारी है। तो बंसी लाल जी के राज में यह साढ़े छः एकड़ जमीन है जो हरिजनों को दी गई, लाखों से चले थे और यहां तक पहुंच गए। मैं कहता हूं कि गरीब हरिजनों को जमीन की याद बार बार न दिलाओ। उनको भूल जाने दो जमनी की बात लेकिल उनको भूलने भी नहीं देते। फिर कहने लगे हरिजनों को ही नहीं बैकवर्ड क्लासों को भी देंगे। 22 लाख की आबादी तो हरिजनों की है और 15 लाख के करीब यह बैकवर्ड क्लासों के लोग है, आप हिसाब लगाते जाइए। उसके बाद यह नाहरा आया कि भूतपूर्व फौजियों को भी यह जमीन देंगे और इसके साथ जो नाम कटे है उनको भी उम्मीद बंधा दी कि उनको भी मिलेगी। इस के बाद एक और कैटेगरी को बीच में ले आए और वह यह कि जिनकी पांच किल्ले से कम जमीन है उनके भी पांच किल्ले पूरी करेंगे। अब यह जो पांच किले से कम वाले है, बाकी तो छोड़ो, जो दो तीन मैंने और बताए कि उनकी कितनी तादाद है। यह एक हरियाणा गवर्नमैंट की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के श्री भल्ला ने छापी है। उन्होंने बताया है कि यह जो पांच एकड़ से कम वाले है उनकी माली हालत क्या है और वह किन हालात में से गुजर रहे है। वह लिखते हैं:-

"Their mean income per capita is 352 against Stage average of 757 for all cultivators and Rs. 133 for every big peasant households".

यह 1972 के आंकड़े है। जो पांच एकड़ से कम के किसान है, उनकी तादाद 1,94,916 है और कुल किसान आबादी का जो खेती का काम करते हैं, उसका यह 27.6 फीसदी है और इनके पास जो जमीन है वह कुल जमीन का जो का त के तहत है 8 करोड़ 87 लाख एकड़ उसका 7.6 फीसदी है। इसमें उन्होंने यह भी लिखा कि वह पावर्टी लाइन से भी नीचे रह रहे है। वह साल में 240 रूपए कर्ज लेकर खेती करते है और अगर उनकी कन्जम्प ान और उनकी आमदनी का हिसाब लगाएं तो जो उनको खेती से होती है और अदर सोर्सिज से भी होती है, तो उनको घाटा पड़ता है और घाटा यह पड़ता है कि .....

Deputy Speaker : You have taken 30 miniutes. I have told that you should not be give more than 20 miniutes. So please wind up now.

चौधरी चांद राम : मैं तीनों मैंबर की तरफ से बोल रहा हूं जो मेरी पार्टी के है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा मैं और मैनें भ्रुरू में ही पूछा था कि आप मुझे कितना टाईम दे रहे है।

उपाध्यक्षा : आपकी पार्टी के हिस्से में 9 मिनट आते है अगर हिसाब लगाकर देखा जाए लेकिन आप 30 मिनट तक बोल चुके है। तो आप अब पांच मिनट में खत्म कर दे।

चौधरी चांद राम : मैं गवर्नर साहब के एड्रैस पर नहीं बोला.....(विघ्न)..... मैं कोि ा ा करूंगा कि जल्दी खत्म कर दूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 10 एकड़ से कम जमीन वाले 56 फीसदी है और ये बिलो पावर्टी लाईन रह रहे है जो कर्ज लेते है कर्ज में जीते है और कर्ज में ही मरते है। यह लोग हरिजन और बैकवर्ड क्लासों के अलावा हैं जो 56 फीसदी हैं। इनकी टोटल पापुले ान एक करोड़ की आबादी मैं 54 लाख है। जहां तक पर–कैपिटा की बात हैं इसमें लिखा है कि इन लोगों को आमदनी बहुत कम होती है, ये कर्जे में रहते है और पावर्टी लाईन में रहते है। अब भाई बताओ की आप कैसे कहते है कि हरियाणा तरक्की कर रहा है? इनकी इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 10 एकड़ से कम जमीन रखने वाले जमींदार 20–30 एकड़ जमीन रखने वालो के मुकाबले में ज्यादा पैदावार करते है। अगर छोटे जमींदारों को बैल दिए जाएं, पूरी सहूलतें दे, तो पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है। अगर स्टेट से लैंडलार्डीजम खत्म करना है तो कोई कंस्ट्रक्टिव कदम उठाएं, यह स्टेट के लिए ज्यादा फायदे की बात साबित होगी। खाद, तकावी, कर्जे कौन लेते है? बड़े बड़े जमींदार ले जाते है, एक एक जमींदार बीस–बीस, तीस–तीस हजार रूपया कर्जा ले जाता है लेकिल छोटे किसानों को नहीं मिलता। हमने अपने टाईम में एक बात की थी कि 5 एकड़ से कम जमीन वाले जमींदार पर उगाही माफ कर दी थी लेकिन आपने 5 एकड़ वालों पर उगाही लगा दी। किसान के पास तो जमानत है, हरिजन के पास कोई जमानत नहीं है इसलिए इनको

पासबुक बना कर दे दी जाए और कह दिया जाए कि वह बिना जमानत कर्जा ले लें। इस बेचारे गरीब जमींदार के पास ज्यादा से ज्यादा बीस–तीस हजार की जमीन है, चार चार किल्लें जमीन है, उनको पटवारी वगैरा परे ाान करते है कि परनोट दो। इनको इस चक में नहीं डालना चाहिए, सीधा हिसाब होना चाहिए कर्जा लो वापिस कर दो। यह काम हरियाणा में क्यों नहीं करते, पंजाब में तो ऐसा है। हरिजनों को रिजर्वे ान भी पूरी नहीं दी जाती। यहां हाउस में पूछा था कि कितनी आफसिर एच.सी.एस है। इन्होंने कहा कि 114 के करीब एच.सी.एस. आफिसर है जिन मैं से 15 आफिसर हरिजन है। इन में हरिजनों की परसैंटेज बढी ही नहीं। एच.सी.एस. (जुडि ाियल) की संख्या 64 है। चौधरी अमर सिंह ने सवाल पूछा था जिसके जवाब मैं इन्होंने बताया था कि एच.सी.एस. (जुडि ाियल) में ि ाड्यूल्ड कास्ट 5 परसैंट है। आप बतायें कि परसैंटेज के हिसाब से कितने होने चाहिएं? 13 के करीब होने चाहिए लेकिन 13 में से आज 5 परसैंट है। अब आप पास मार्क्स की बात ले लें। पहले पास मार्क्स 45 परसैंट होते थे लेकिन अब वे कहते है कि 55 परसैंट होने चाहिए। अब जब हरिजन थोड़ा बहुत पढ़ने लगे तो परसैंटेज बढ़ा दी। एक साहब कह रहे थे कि हरिजनों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। 18 दिसम्बर 1970 को हाई कोर्ट का फैसला हुआ था जिसमें हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों हार गई थीं क्योंकि यह केस पंजाब के वक्त मैं चला हुआ था। केस था रिजर्वे ान इन प्रमो ान, हीरालाल वर्सिज प्रताप सिंह। केस दर्ज हुआ और हाई

कोर्ट में गवर्नमैंट को हराया। इसके बाद हरियाणा गवर्नमैंट ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि रिजर्वे ान इन प्रमो ान होनी चाहिए। 12 सितम्बर 1963 को रिजर्वे ान इन प्रमो ान का फैसला हुआ और मान लिया गया कि पहल वैकेंसी हरिजन को दी जा सकती है। क्लास 1 और क्लास 2 मैं रिजर्वे ान दी जा सकती है, इस सिलसिले में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने भी एक लैटर हर स्टेट गवर्नमैंट को सर्कुलेट किया था कि क्लास 1 और क्लास 2 में तो रिजर्वे ान दूर रही, क्लास 3 और क्लास 4 में भी रिजर्वे ान इन प्रमो ान पूरी नहीं हुई। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कह रहा था कि यह गवर्नमैंट जिसका अपना फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था लेकिन उसके बाद सरकार कहती है कि हम दोबारा फैसला करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते ही नहीं हैं? जब सच्चर का जमाना था तो इन्होंने कहा था कि तीसरी वैकैंसी हरिजन को दी जाएगी मुझे अच्छी तरह से याद है लेकिन पता नहीं कानून वाले कैसे इन्टरप्रटे ान करते है? उन्होंने कहा था कि तीसरी वेकैंसी हरिजन को देंगे लेकिन इसके साथ ही साथ एक और हुकम जारी कर दिया कि रिक्रूटिंग एजेंसीज, जैसे एस.एस.एस. बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमी ान, तीसरी वेकैं ाी होने के बाद सीनियारिटी फिक्स करेंगे लेकिन इससे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिडैंडैंट हो गया। तीसरी वेकैंसी हरिजन को देने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि 100 मैं से 20 देंगे और उनकी

सीनियारिटी आखिरी 20 में यानी 80 वेकैंसीज के बाद फिक्स कर देंगे और इस तरह से हरिजन जूनियर मोस्ट हो गए। इससे क्या फायदा, यह कहां का ला? जहां तक एस.एस.एस. बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमी ान का ताल्लुक है, उन में तो फिलहाल कोई हरिजन है ही नहीं। एक फैसला जो हाई कोर्ट ने होल्ड किया तो डिपार्टमैंट वाले, हाई कोर्ट के फैसले के ओवर एंड अबब कैसे ओपीनियन दे सकते हैं?

Deputy Speaker : Please wind up.

चौधरी चांद राम : मैं अभी खत्म करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह गवर्नमैंट आये साल धानक, भंगी, चमार वगैरा का सवाल पैदा करती है लेकिन इनको देती कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि उनको पूरी रकम दो, एक रूपया फी हरिजन जो उन पर खर्च करने जा रहे है इससे उनका सुधार नहीं होने वाला। चौधरी फूल सिंह कटारिया के एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल फिनांस कारपोरे ान को 58 लाख रूपया दिया गया लेकिन इसके मुकाबले में हरिजल कल्याण निगम मैं, हरिजन की भलाई के लिए सिर्फ 9 लाख दिया गया। आप देख लें कि 9 लाख रूपये से क्या हरिजनों का भला हो जाएगा? इस किताब में लिखा है कि हरिजन चिरकाल से पिछड़े हुए है लेकिन हिस्ट्री नहीं बताई कि कब से पिछड़े हुए है। क्या ये हिस्ट्री ये हिस्ट्री नहीं बता सकते थे कि कब से पिछड़े हुए थे? डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं बड़े अदब से आपकी मारफत बताना

चाहता हूं, मेरी आदत नहीं है धमकी देने की। पिछले एजीटे ान में मैं मजबूर होकर खड़ा था। आज भी हरिजन दुखी है और दुख से कहते है कि अगर किसी ने एजीटे ान पर जोर दिया तो करना पड़ेगा। आज हरिजन की जूती का काम बाटा ने ले लिया, तानी का काम मिलों ने ले लिया, यहां तक कि मिट्टी की खोदने का काम भी नहीं मिलता, वे कांग्रेस के राज में मारे–मारे फिरते हैं.....

Deputy Speaker : Please wind up.

चौधरी चांद राम : एक मिनट जी। मैं कहता हूं कि इनको एजीटे ान करने पर मजबूर न किया जाए। ये लोग तो आपका काम हाथ जोड़कर कर सकते हैं, आपकी सरकार बनाते रहे हैं, आप पर उम्मीद ही उम्मीद लगाए बैठै है, इनको कोटे दो, परमिट दो और इनकी जो संघर्श समीति की 10 मांगें है उनको मान लिया जाए, अगर नहीं मानेंगे तो इंडिया में ऐसी गड़बड़ी, ऐसा असन्तोश फैलेगा जिसको आप काबू में नहीं कर पायेंगे।

श्रीमति भाारदा रानी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम। चौधरी चांद राम जी हरिजनों के बारे में इतना बोल रहे है, क्या वे फैमिली प्लानिंग के बारे में हरिजनों को कहेंगे कि वे सबसे कम बच्चे पैदा करें? क्या वे यह भी देखेंगे कि हरिजन फैमिली प्लानिंग को एक्सैप्ट करते हैं या नहीं!

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। (व्यवधान) एक भाई ने कहा कि उसने फैमिली प्लानिंग की है (व्यवधान) मैं फैमिली प्लानिंग के हम में हूं लेकिन स्वेच्छा से। कुरप्ट करने का जो ढ़ंग है यह ठीक नहीं। 12–12 साल के लड़कों का आप्रे ान हुआ है (घंटी) कमी ान लेकर जो नसबंदी या औप्रे ान करते हैं मैं इसके खिलाफ हूं (व्यवधान) अगर करनी है तो स्वेच्छा से की जाए ने कि दबाव डालकर और लालच से। असूलन मैं फैमिली प्लानिंग के हक में हूं।

चौधरी ई वर सिंह (पूंडरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिमांड पर चर्चा हो रही है। मैं फिनांस मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने जुडि ियस बजट पे ा किया है। इन्होंने बजट में खसारा भी दिखाया है। खसारे के बारे में मैं अर्ज करता हूं, जैसा कि कहा गया है–

मैं वो सौदागर हूं जिसने

नफा देखा है खसारा में।

फिनांस मिनिस्टर साहब ने नफा भी देखा है लेकिन जो लूप होल्ज है उन को प्लग करके वह घाटा पूरा किया जा सकता है। बजट जो होता है उसमें स्टेट ने अपने रिसोर्सिज दिखाने होते हैं कि घाटा पूरा करने के लिए क्या क्या साधन हैं, किस तरह से आमदनी होनी है और उस आमदनी को किस हैड में कैसे

बांटना है, किस किस चीज को प्रायर्टी देनी है, उसके मुताबिक खर्च करना होता है। इस बजट में ज्यादा रकम इरीगे ान एंड पावर को अलाट की गई है। यह बिल्कुल ठीक है कि इरीगे ान और पावर की प्रायर्टी मिलनी जरूरी है। पावर एक ऐसी चीज है जिससे इरीगे ान का काम चलता है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो अहम कार्य है ये दे ा की म ाीनरी है। इस म ाीनरी को चलाने के लिए पावर एक अहम चीज है, ये पावर से चलते है और इरीगे ान और पावर को बढ़ाने के लिए काफी कुछ अकदामात उठाए गए है। हमने नहरों को पक्का करना है। ये एम.आई.टी. सी. के ट्यूबवैल्ज तो इसी सरकार ने भाुरू नहीं किए, यह तो स्कीम बहुंत पहले की है। जब सांझा पंजाब था, कैरों साहब के वक्त की स्कीम चली हुई है। उस वक्त भी वे चौधरी ि ाव राम के खेत में ट्यूबवैल लगाने जा रहे थे और वैस्टर्न जमुना कैनाल में पानी डालने का प्रोग्राम था। फिर जब वे राव बिरेन्द्र सिंह की मिनिस्टरी के वक्त में एम.एल.ए. थे उस वक्त भी ट्यूबवैल लगा करके पानी वैस्टर्न जमुना कैनाल में डालने की स्कीम थी। तो इस तरह कयी स्कीमें सब पुरानी है। स्कीमें बड़े बड़े इंजीनियर बनाते है और पानी अगर जमीन के नीचे है तो उसे निकालने में कोई बुराई नहीं है। पहले बहुत सालों तक बारि ों होती रहीं जिससे सीपेज भी बढ़ा और सेम भी आई और उस वक्त यह सोचा जाने लगा कि अगर इस तरह ट्यूबवैल्ज लगा दिए जाए नहरों के पास तो उससे वह सीपेज नहरों में डाली जा सकती है और वहां की जो जमीन खराब हो गई है वह ठीक की जा सकती है। यह

एक थ्योरी थी लेकिन अब दो साल से बारि ा की कमी है। कुछ लोग महसूस करते है कि जहां ट्यूबवैल्ज लगे हुए है, उनके पास ड्रौट की वजह से, उनका जो वाटर लैवल है वह नीचे चला गया है। इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जहां ऐसे केसिज है वहां ट्यूबवैल्ज का कुछ पानी उन किसानों को जो इफैक्ट हुए है, जो नजदीक के है, अगर दे दिया जाए तो अच्छी बात होगी। हाउस मैं वैसे ऐलान हुआ तो है कि जो किसान ज्यादा इफैक्ट हुए है, नजदीक के है, उन्हे वह पानी दिया जा सकता है। अगर वह पानी दे दिया जाए तो ये लोग बहुत खु ा होंगे और उन्हें बिजली की कमी भी महसूस नहीं होगी। वे ट्यूबवैल्ज लगभग 24 घंटे चलते है लेकिन दूसरे ट्यूबवैल्ज बांट में जितनी बिजली आती है उसके हिसाब से चलते है। फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारी सरकार ने नहरों को पक्का करने और नहरों से जो आगे निकलने वाले खाल हैं उनको पक्का करने की जो स्कीम बनाई है यह बहुत सराहनीय है। इससे सीपेज जो होती थी वह बचेगी और पानी भी बचेगा। बजट में डिप्टी स्पीकर साहिबा आगे निकाली जाने वाली नहरों, जैसे जवाहर लाल नेहरू कैनाल, और बहुत सारी लिफ्ट इरीगे ान स्कीम्ज का भी जिक किया गया है। सिर्फ यही नहीं, व्यास का जो पानी आएगा उसके हिसाब से भी प्लानिंग की गई है ताकि सारी स्टेट में इक्वल डिस्ट्रिव्यू ान हो और उन लोगों को भी पानी दिया जाए जहां पानी की कमी है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं लेकिन एक बात मैं इस सम्बन्ध में जरूर कहूंगा। डिप्टी स्पीकर

साहिबा, जमुना कैनाल से सिंचित होने वाले जो एरियाज हैं, जैसे करनाल और कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्स का एरिया, वहां वाटर अलांउस 32 परसैंट है जबकि भाखड़ा का वाटर अलांउस 64 परसैंट के करीब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब ब्यास का पानी उधर जाएगा तो यह वाटर अलांउस भी भाखड़ा के बराबर ही सारी स्टेट में कर दिया जाएगा ताकि करनाल और कुरूक्षेत्र के इलाके को भी इससे फायदा हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इरीगे ान के साथ–साथ हमारी स्टेट मैं ड्रेनेज के लिए भी सराहनीय काम हुआ है। हमारे यहां ऐसे इलाके थे जहां मीलों तक पानी खड़ा रहता था। उनकी जमीन वत्र में नहीं आती थी। वहां कोई फसल बोई नहीं जाती थी। सावनी की फसल तो खराब होती ही थी क्योंकि बारि ा उसी वक्त होती थी लेकिन आशाढ़ी की फसल भी खराब होती थी। तो ड्रेनेज के लिए भी बहुत काम हमारी सरकार ने किया है। फालतू पानी उन इलाकों से निकाला गया है। उसको इस्तेमाल करने का बंदोबस्त भी बना है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं मानता हूं कि पावर की हमारे यहां कुछ कमी है लेकिन इसके लिए भी आव यक कदम उठाए जा रहे है। बाजोकात डिप्टी स्पीकर साहिबा, ब्लैंसिंग इन डिसगाइज वाली बात भी हो जाती है। इस पावर की कमी और ड्रौट की वजह से वे स्कीमें भी हमारी सैन्टर से क्लीयर हुई हैं जिन्हें वे पहले सैंक ान नहीं कर रहे थे। पानीपत और

फरीदाबाद थर्मल प्लांटस भी डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी गवर्नमैंट की कोि ा ा का नतीजा है। ब्यास का पानी जब सतलुज रिवर में, गोबिन्दसागर में गिराया जाएगा तो उससे भी हमारे हिस्से में बिजली ज्यादा आएगी और पानी भी हमें ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से डहर के पावर हाउस और पौंग डैम से भी हमें बिजली मिलेगी। तो ये कुछैक कदम हैं जो कि बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार उठा रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यही नहीं, सरकार ने उन इंडस्ट्रियलिस्टस को जो अपने कारखानों को चलाने के लिए अपने जैनरेटर लगाने जा रहे है, सबसिडी देने का भी ऐलान किया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप इस बात को मानेंगे कि कोई भी प्रोजैक्ट हो, चाहे उस पर तीनौं ि ाफ्टों में काम क्यों न किया जाए, जायज टाईम तो उस पर लगता ही है लेकिन फिर भी हमारी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोि ा ा कर रही है कि वह जल्दी से जल्दी पूरा हो। इन बातों के होते हुए भी जो ये भाई कहते है कि तरक्की नहीं हो रहीं है यह बड़ी गलत बात सी बात है। ये तो सब बाते बिल्कुल जाहिर है। डिप्टी स्पकीर साहिबा, पहले अकाल पड़ा करता था। उसमें लोग घर छोड़कर बाहर निकल जाते थे। अपने प ाुओं को साथ ले जाते थे। पता नहीं कितने प ाु मर जाते थे। लेकिन अब बारि ा की कमी होने के बावजूद भी ऐसी हालत नहीं हुई। सरकार ने जो ड्रौट इफैक्टिड एरियाज है उनके लिए फैमिन रिलीफ फंड में पांच करोड़ रूपये रख कर काफी सहूलियतें दी हैं जिनकी उन्हे जरूरतें है।

इसी तरह, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐग्रीक्लचर में भी हमारी स्टेट ने काफी तरक्की की है। यह जो इतनी पैदावार बढ़ी है यह सब नए बीजों आदि की रिसर्च की वजह से बढ़ी है। काफी रिसर्च ऐग्रीक्लचर के फील्ड में हमारे यहां हुई हैं जिसे ऐजुके ान और ऐक्सटैं ान प्रोग्राम के तहत आम किसानों तक पहुंचाया गया है। चौधरी ि ाव राम जी कह रहे थे कि अब भी गेहूं के बीज दिए जाते है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह लेट वैरायटी है। बहुत सी ऐसी जमीनें है जिसमें तोड़ियां था और वे बोई नहीं जा सकीं। ऐसी जगहों पर यह लेट वैरायटी चलती है। लोग अब भी बो रहे है। यह यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके नया बीज निकाला है। इससे पैदावार भी कम नहीं होगी। लेट बीज जहां बोया है वहां भी यह उगा हुआ है। इससे भी उतनी ही प्रोडक ान होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो आकंड़ें दिए जाते है कि 1967–68 में पैदावार बहुत हुई थी लेकिन अब कुछ घटी है, इसके बारे में अर्ज यह है कि उस समय बारि ा की वजह से सारी जमीन बोई गई थी और खासकर चने की पैदावार में काफी इजाफा हुआ था। जहां तक इरीगे ान का ताल्लुक है, यह तो सभी को पता है कि ट्यूबवैल्ज 22–23 हजार से बढ़कर जो एक लाख तीस हजार हुए वे आखिर खाली तो नहीं रहे। उन ट्यूबवैल्ज ने पैदावार बढ़ाई है। फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये कहते हैं कि ट्यूबवैल्ज के कनैक ान अब दिए जा रहे है जबकि बिजली की कमी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा जमींदार है जो बिजली नहीं चाहता? आखिर जिस किसी ने भी

दरख्वास्त दी है उसने जरूरत से ही दी होगी। हम भी लोगों से पूछते हैं कि भाई जब बिजली की कमी है तो तुम कनैक ान के लिए दरख्वास्त क्यों देते हो? वे जवाब देते है कि कम से कम मिल जाएग। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजल लेना हरेक चाहता है। कई लोगों ने तो अपने साधनों से डीजल पम्प भी चलाए है और प्रोडक ान को काफी बढ़ाया है। इन सब बातों को देखते हुए, हम कह सकते है कि हरियाणा मैं प्रोडक ान बढ़ी है और यह इस सरकार के प्रयत्नों का नतीजा है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले हरियाणा ऐग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी का एक ही कैम्पस था और वह था हिसार में लेकिन कुरूक्षेत्र और करनाल जिला जो पैडी के लिए खास तौर पर म ाहूर हैं, जिसकी जमीन उसकी प्रोडक ान के लिए सूटेबल है, जहां गन्ने और सब्जियों की का त भी काफी मात्रा में होती हैं, उनको सुविधा देने के लिए कौल गांव में, जो कुरूक्षेत्र जिले में है, इस साल एक नया कैम्पस हरियाणा ऐग्रीक्लचर यूनिवर्सिटी का खोला है जिसमैं रिसर्च भी होगी। राईस की इस वक्त वहां 600 वैराईटीज टैस्ट हो रही है और नई स्ट्रेन्ज भी इवोल्व की जा रही हैं। यह एक ऐसा कैम्पस है जिसमें वैजिटेबल की रिसर्च का सैन्टर भी कायम किया गया है। इसी साल वहां ऐग्रीकल्चर कालेज भी स्टार्ट किया गया है। मैं तो इस राय का हूं कि हमारा ऐम्फैसिज टैक्निकल ऐजुके ान की तरफ ज्यादा होना चाहिए। आजकल आर्टस पर कोई पाबंदी नहीं है। पता नहीं कितने हजार

ग्रेजुएटस ज्यादा से ज्यादा पैदा हों। ताकि हम सैन्टर की और बैंकों के अन्दर नौकरी भी ने सकें। आजकल बैंकों में भी ऐग्रीकल्चर ग्रेजुएट काफी लिए जाने लगे है। एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट अपनी खेती भी कर सकते हैं, नौकरियों में भी जा सकते हैं। एग्रीक्लचर का टैक्नीकल नालेज होना बहुत जरूरी है। हमें यह सोचना है कि आर्ट का ग्रेजुएट जब कुछ कर सकता है तो एग्रीकलचर का ग्रेजुएट और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी खेती तो कर सकता है। एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट आर्ट के ग्रेजुएट से बहुत ज्यादा कीमत रखता है। हमारे प्रदे ा में जहां हर साल 10–20 हजार आर्ट के ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वहां हिसार यूनिवर्सिटी से केवल 100 ग्रेजुएट एग्रकल्चर के निकलते है। आज जरूरत इस बात कि है कि उनकी तादाद बढ़ायी जाए। आज हमारे यहां हरियाणा में 1800–1900 हायर सैकेण्डरी स्कूल, हाई स्कूल, और मिडिल स्कूल है। हरेक स्कूल में एग्रीकल्चर टीचर की जरूरत है। इस स्टेट के हर स्कूल के अन्दर एक एग्रीकल्चर का ट्रेन्ड टीचर होना चाहिए। मैं तो चौधरी माडू सिंह जी से यह कहूंगा कि हर हर हाई स्कूल, हायर सैकेण्डरी स्कूल और मिडल स्कूल के साथ कोई फार्म होना चाहिए, जमीन एक्वायर की जानी चाहिए, ट्यूबवैल होना चाहिए, एग्रीकल्चर ट्रेन्ड टीचर होना चाहिए ताकि हर बच्चा अपने यहां एग्रीकल्चर का काम करे। वह सब्जियां बोयें, किचन गार्डनिंग का काम करे और दूसरे ऐग्रीकल्चर में थ्योरी के और प्रैक्टीकल काम करे। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमैं 1800–1900 ग्रेजुएटस की जरूरत पड़ेगी।

हमारे यहां जो ग्रेजुऐट निकलते है वे कम है और हमारी मांग ज्यादा हैं। कुछ लोग तो बी.एस.सी. करने के बाद एम.एस.सी. में दाखिला ले लेते है, कुछ रिसर्च में चले जाते हैं, कुछ गवर्नमैंट आफ इंडिया में चले जाते है, कुछ प्रोफैसर बन जाते है। इस ढ़ंग से प्रोग्राम चलता हैं तो चार–पांच साल के अन्दर ग्रेएजुऐट तैयार होता है। अगर देहातों के अन्दर ऐग्रीकल्चर सब्जैक्ट को पढ़ाया जाये, पढ़ाते तो अब भी है लेकिन अन–ट्रेन्ड टीचर पढ़ाते हैं। अगर हमें ट्रेन्ड टीचर्ज की आव यकता है तो हमें अभी से पांच छः साल पहले ही दाखिला करना पड़ेगा तब यह प्रोग्राम ठीक ढ़ंग से चला पायेंगे वरना हमें अपनी स्टेट के लिए दूसरे सूबों से ग्रेजुऐट मंगाने पड़ेगे। हमारे यहां आज रिसर्च चल रही है, एजुके ान चल रही है वहां एक्सटेन ान भी चली हुई है और यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है उन्होंने देहातों में आकर लेटैस्ट एग्रीकल्चर के तरीके बताये है जिससे ऐग्रीकल्चर में काफी फर्क पड़ा है। आज हमारा स्पै ालाइजे ान की तरफ ज्यादा ध्यान हो, टैक्नीि ायन की नालेज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाये। इस ढ़ंग से हम ज्यादा प्रोडक ान बढ़ा सकेंगे।

आजकल ऐनीमल हैसबेंडरी के महकमें की तरफ से आई.सी.डी.पी. का प्रोग्राम भी चला हुआ हैं। उसमें आर्टीफिि ायल इनसैमिने ान ने हमारे यहां काफी व्हाइट रेवोलू ान लाने में मदद की है। जगह–जगह पर आर्टीफिि ायल इन–सैमिने ान सैन्टर खोलें गये हैं। कर्नल साहब ने और गुप्ता जी ने

कोआपरेटिव डिपार्टमैंट पर काफी जोर दिया है। जो हरियाणा के अन्दर मिल्क कोआप्रेटिव की सोसाइटीज हैं जिनकी वजह से किसान को भाव कुछ ठीक मिला है लेकिन और जो ज्यादा भाव देने की जरूरत है क्योंकि कनसैंट रेट मंहगा है। जब तक दाना, बिनौला मंहगा रहेगा तब तक इस भाव से वे दूध नहीं दे सकते। जितना फैट कनटेन्ट मांगते हैं, उसके हिसाब से महंगा पड़ता है। उनके हिसाब से वह ठीक नहीं बैठता। दूध की कीमत जरूर बढ़ायी जानी चाहिए। मैं एग्रो इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने फीडिंग प्लांट लगाया है उससे जो फीड मिलता है वह सस्ता और बैलेन्सड है। जिन्होंने अपने दूध को बढ़ाना है, घी को बढ़ाना हैं उसके लिए वह बैलैन्सड और सस्ता फीड तैयार कर रहे है जिससे किसान को काफी फायदा होगा। हमारे कोआप्रेटिव महकमे की अलग अलग कोआप्रेटिव सोसाइटीज है। एग्रीकल्चरल सर्विस सोसाइटिज हैं वे अपने ढ़ंग से काम कर रही है, उनमें भी बहुत सी कमियां है लेकिन खास तौर से कोआपरेटिव के महकमैं ने हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल और कुरूक्षेत्र के अन्दर बहुत तरक्की की है। हमारे यहां जो पानीपत में भूगर मिल है इससे काफी अच्छी रिकवरी हो रही है उतनी तो नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, साउथ इंडिया की मिलों से कम है लेकिन उसके बाद भी हम जमींदारो को भाव अच्छा दे रहे है। गन्ने के कै ा कौप है। आजकल कहा जाता है कि मलेि िया मैं 31 रूपये के भाव से चीनी बिक रही है और श्री लंका में 25 रूपए के भाव से बिक रही है। चीनी से हमें फौरन एक्सचेंज आता है।

इस लाभ के साथ ही हम करनाल में और सानीपत में दो भूगर मिल लगाने जा रहे है। हमारे भूगर मिलों ने अच्छे भाव दिए है साउथ में आठ परसैन्ट की रिकवरी है। वे साढ़े आठ रूपए देते है। उसके ऊपर एक परसैंट फरदर रिकवरी एक रूपया पा एडी ानल देते है। हमारी पानीपत की भूगर मिल ने पिछले साल कोई साढ़े 12 रूपए प्रति क्विंटल दिया है और फिर कुछ चीनी भी दी, कुछ डिविडेन्ट भी मिला, उन से करनाल भूगर मिल मैं हिस्से खरीदे गए है। सारा हिसाब लगाया जाए, तो सवा 14 रूनए के हिसाब से पड़ा है। मैं समझता हूं कि सारे इंडिया में जो हमारे फारमर्ज है, उनको ज्यादा पेमैंट हुई है प्रति क्विंटल के हिसाब से। रिकवरी के हिसाब से भी सारे इंडिया में ज्यादा है। को–आप्रेटिव महकमे की जो मार्कीटिंग फैडरे ान है, उन्होंने जो पैडी के भौलर्ज लगाए है वे ऐसे एरिया में लगाए हैं, जहां पैडी की पैदावार ज्यादा होती है। पहले अकेले डीलर्ज मैदान मैं थे वे पूछ कर लेते थे नतीजा यहा हाता थे कि किसान को काफी कीमत नहीं मिल सकती थी। बाज दफा तो छोटी मंडियौं में यह इन्तजार करना पड़ता था कि करनाल से कोई व्यापारी आयेगा, तब बोली होगी। को–आप्रेटिव के महकमै ने भौलर लगाए है और वे भी लेटैस्ट मार्डन टाईप भौलर्ज लगाए है। उन्होंने पूल नहीं होने दिया बल्कि कीमतें कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट ने और मार्कीटिंग फैड्रे ान ने अच्छी दी है। पंजाब के अन्दर जो कोरस जीरी बिकी उसकी कीमत 75,76 और 78 रूपए से ज्यादा नहीं गई लेकिन हमारे यहां हरियाणा में 91–92 और 93–94 के भाव तक बिकी है

तो यह सब कुछ सरकार की वजह से ही हुआ है। हमारे किसानों को चौदह–पन्द्रह रूपए फालतू कीमत मिली है। जहां तक बासमती का सम्बन्ध है वह हमारी बासमती से कुछ ज्यादा बिकी है। पंजाब ने सप्लाइज कारपोरे ान बनाई है। वहां डायरैक्ट स्टेट ट्रेडिंग कारपोरे ान गवर्नमैंट आफ इंडिया से की है जिन्होंने ईराक और ईरान कन्ट्रीज को चावल सप्लाई करना है। बासमती की कीमत पंजाब वालों ने हमारे से ज्यादा दी है। सप्लाई कारपोरे ान ने खरीदी है लेकिन यहां कुछ कीमत कम रही। हमारी बासमती फौरन एक्सचेंज और आयल खरीदने में मदद करती है। तो सरकार को चाहिए कि पंजाब की तरह यहां भी भाव को इन्क्रीज करे। हमारे करनाल जिले के अन्दर तरावड़ी के आसपास और नीलोखेड़ी के आसपास का पैडी ग्रोईंग एरिया है। वहां पर बहुत अच्छे किस्म की पैडी होती है, उससे हम फौरन एक्सचेंज अरन कर सकते है। तो हमारे किसानों को भी पंजाब के भाव मिलने चाहिए। हमारे याहं कोरस पैडी के भाव पंजाब से ज्यादा दिये है। हमारे यहां कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट ने जितनी भी कदम उठाये है चाहे वह दाल प्लांट है, चाहे खाद प्लांट है, उनसे जनता को बड़ा भारी लाभ हुआ है। अगल बात यह है कि जब प्रोडयूसर की प्रोडयूस प्रोसैस होती है तो प्रोसैसिंग करने वाले और डिस्ट्रिब्यू ान करने वाले ज्यादा मुनाफा ले जाते है। अगर सरकार उस प्रोसैसिंग मे भाामिल हो जाती है तो अगर सरकार उस प्रोसैसिंग मे भाामिल हो जाती है तो उससे सरकार का जो ध्येय है वह पूरा होगा। उससे एक तो प्रोडयूसर को ज्यादा से

ज्यादा कीमत मिलेगी और दूसरे सरकार ने प्रोसैसिंग से जो नफा लेना है, वह लेगी। अगर नफा होता है तो सरकार उससे और प्रोसैसिंग प्लांटस खोल देगी। वह नफा भी जनहित या सरकार खजाने मे जायेगा, जो आम आदमी या पब्लिक की डिवैल्पमैंट के काम आएगा। इसलिये मेरे कहना यह है कि सरकार की ओर से प्लांटस लगाए जाये और प्रोडयूसर को पूरी कीमत दे जाये। हर तरफ प्रोसैसिंग प्लांटस खोले। एग्रीकल्चर की प्रोडक ान ठीक ढंग से करने के लिये सरकार के कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के द्वारा या एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के द्वारा जा`भी कदम उठाए जा रहे है, वे सब बहुत ही सराहनीय कदम है। सड़कों के बारे मे यह ठीक हे कि सड़कों को अब उतनी प्रायरटी नही दी जाती जितनी इरीगे ान को दी जाती रही है लेकिन फिर भी हमने 64 प्रति ात गांवो को सड़कों से मिला दिया है। सड़के हमारी लाईफ लाईन है। अगर हिसाब लगाकर देखा जाये कि किसानों को अपनी प्रोडयूस मंडियों तक ले आने मे कितनी दिक्कत होती थी, कितना खर्चा देना पड़ता था, कितनी दिक्कत होती थी, तो पता चलेगा कि अब किसान को बहुत सहूलियत हो गई है। अपनी प्रोडयूस को खेत से मंडियों तक पहुंचाने मे और मंडियों से सामान अपने घर तक ले जाने मे उसे बहुत खर्च करना पड़ता था। जब पक्की सड़के बनने की वजह से उन्हे काफी सहूलियत हो गई है। जहां जहां पक्की सड़के बनी हुई है, वहां वहां उन उनके साथ ही साथ बसे भी भेज दी गई है। अब ज्यादातर गांवो मे बसें पहुंच चुकी है जिससे लोगों को बड़ी भारी सहूलियत हो गई है। लोग यह

महसूस करते है और यह ठीक भी है भाहरों की या सिविलाईजे ान की बाते उन तक पहुंच गई है। बिजली की वजह से और सड़कों की वजह से लोग यह महसूस करते है कि देहातों को छोड़कर भाहरों मे बसने की जरूरत नही, बल्कि गांवों मे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाहरों मे तो यर पालयू ान है और भाोर बहुत है। गांवों के अंदर जब सड़के बन गई, बिजली पहुंच गई तो लोग देहातो मे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। उसने हर किस्म की बसे दिन मे डिलक्स बसें भी है, सेमी डी लक्स भी है, ऐक्सप्रैस बसें भी है, लांग रूट बसे भी है, पेसैंजर बसे भी है, चलाई है। खासकर हरियाणा के देहातों मे जो बसें भेजी गई है, यह बड़ी अच्छी बात है। बस देहात मे जाकर सवारी लेकर आती है और भााम को घर छोड़ देती है। यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ट्रांसपोर्ट मे जो खराबी है, वह वर्कशाप मे है। वर्क ााप मे है। वर्क ााप मे खराबी इसलिये भी है जैसे कि हमने 10 डिपो बना दिये। हर जगह वही स्टाफ है, हर जगह वही सब कुछ है, लेकिन कोई सैंट्रल वर्क ााप नही है । कोइ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कि हम सैंट्रल वर्क ााप बना सके। टायरों की रीट्रीडिंग का, मुरम्मत का या कुद और काम है, वे काम वहां होने चाहिए। जो म ाीनरी बाज जगह आईडल पड़ी रहती है और लाखों रूपये की म ारिनी है, उससे हम पूरा और एग्जैक्ट काम ले सके। इसके लिये कोई सैंट्रल वर्क ााप चाहिए जिससे कि वह काम दस जगह ने लेकर तीन चार जगह तक हो सके। इससे स्टाफ मे और दूसरे खर्च मे भी कमी

हो सकती है। इसलिये वर्क ाप की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा यहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रे ान और एजुके ान के बारे मे भी कहा गया । जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान हमारी सरकार की तरफ से तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बाज जगह यह हो सकता है कि कोई अफसर ठीक न हो , जिससे पब्लिक की ि ाकायत हो। जनरल एडमिनिस्ट्र ान का दारामदार अफसरों पर होता है। आम तौर पर तो यह ठीक है लेकिन अगर कहीं अफसर की वजह से पब्लिक को ि ाकायत हो तो दूसरी बात है। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी मे कुछ अपोजी ान पार्टीज ने बच्चों मे घूसकर उनका नाजायज इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी मे स्ट्राइक करवानी चाही और करवाई और आखिर मे वह स्ट्राईक फेल हुई। वह स्ट्राइक इसलिये फेल हुई क्योंकि उसका कोई कारण नही था। कुछ ऐसी पार्टिया है, जो यह चाहती है, कि बच्चों को इस्तेमाल करें और उनके कंधों पर अपनी बंदूक रखकर चलाएं और मूल्क के अंदर और यहां पर अमर और भाांति को भंग किया जाये। उनके ऐंडज पालिटीकल है। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी है, कुछ टाईम के लिये तो वे थोड़ा सा भावुकता मे बह जाते है लेकिन बाद मे उनको समझ आया । उन लोगों को भी जिनके बच्चे थे समझ आया कि हमारे बच्चों का कुछ पालिटीकल पार्टीज नाजायज इस्तेमाल करना चाहती है। चौधरी दल सिंह जी ने कहा कि गुरू का मान होना चाहिए और माता पिता का भी मान

होना चाहिए। उनहोने स्टूडैंटस के बारे मे ऐसी बाते कही, लेकिन कुछ स्टूडैंटस ऐसे होते है, जो पालिटीक्स मे डील करते है। वे स्टूडैंअस न रहकर पालिटीि ायन बन जाते है। खराबी सारी वहां होती है, जहां ये किसी दूसरे के बहकावे मे आ जाते है। इसी तरह से कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी मे भी कुछ लड़कों ने ऐसी पोलिटिक्स चलानी चाही लेकिन जब ये फेल हो गए, तो कुछ दूसरे लोगो ने अपने सिर पर ताज रखने के लिये इन बच्चों को ऐसे इस्तेमाल करना चाहा जैसे कि कोई खूद तो सूखी लकड़ियां आग मे डाल देता है लेकिन खुद आग मे पड़ना नही चाहता। ऐसा उन्होंने किया। उन्होने वहां के डिसिप्लन की बात कही। मैं वहां के बोर्ड मे हरियाणा असैम्बली का एक रिप्रैंटेटिव हूं, असैम्बली को रिप्रैजैंट करता हूं। मुझें पता है कि लड़कों ने रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर के आगे भामियाने लगाये और वहां पर तरह तरह के गाने गाये। उनके गाने इस से भाुरू होते थे 'सर फरो ाी की तमन्ना अब हमारे दिल मे है.....' और इसके अलावा बौबी फिल्म के गाने बजाए जाते थे। यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को ऐक्सपैल कर दिया गया। ऐसा करना कोई बुरी बात नही । अगर यूनिवर्सिटी ने ऐसा स्टैप लिया है तभी जनरल एडमिनिस्ट्र ान की हालत बहुत अच्छी है। (घंटी) टूरिजम के बारे मे बहुत सी बाते कही गयी।

Deputy Speaker: It is more than half an hour that you have been speaking. Please wind up.

चौधरी ई वर सिंहः टूरिजम के बारे मे यहां पर बहुत कुद सुना गया। मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि यहां पर टूरिस्ट न होते हुए भी सरकार ने जो टूरिजम के लिये स्पाटस बनाए है, वे किसी एक व्यक्ति की पूंजी नही बल्कि सारी की सारी पब्लिक की जायदाद है। इसलिये हमें उन पर फक्र करना चाहिए। अंत मे मैं फाईनैंस मिनिस्टर को जिन्होंने बैलैन्सड बजट पे ा किया है, इसके लिये उनको मुबारिकबाद देता हूं और सरकार ने जो साधान लोगो को दिये है, उसके लिये उनको बधाई देता हूं।

Deputy Speaker: Shri Girish Chander Jishi.

श्री अमर सिंहः फिर हमें टाईम कब मिलेगा ?

Deputy Speaker: You have already spoken on the budget.

श्री गिरी ा चंद जो ीः न मैं बजट पर बोला हूं और न ही डिमांडस पर बोला हूं। गवर्नर एड्रैस के बाद मैं आज ही बोल रहा हू।

Deputy Speaker: Joshi ji, you may not take more than 15 minutes so that I could give time to some other member also.

श्री गिरी ा चंद्र जो ी (यमुनानगर): उपाध्यक्ष महोदया, मैं थोड़ा सा समय ही लूंगा और मैं अपने आप जल्दी ही खत्म कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के साम ने

बजट रखा और फिर डिमांडज भी आई। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण मे सरकार की नीति निर्धारित की। आर्थिक न्याय और सामाजिक समता । उसी बुनियाद पर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा वह बिल्कुल सही और सच्चाई के तौर पर रखां बजट की सबसे बड़ी चीज होती है सरकार की फिसकल पालिसी । फिसकल पालिसी के मायने यह है कि क्या क्या चीजो की जरूरत है और क्या क्या हमारे जराए है। किन चीजो पर हम मबनी है और क्या क्या हमारी आव यकताएं ह। सप्लाई ओर डिमांड जो हे, यह इकोनोमी का मुख्य अंग है। इसी बुनियाद पर हमने किस चीज को प्राथमिकता देनी है, यह फिसकल पालिसी हमारी सरकार निर्धारित करती है। हमारी सरकार ने, चाहे वह राज्यपाल का अभिभाशण हो, चाहे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाशण दिया—वह हो, जिन बातों का उल्लेख किया, उससे साफ जाहिर हो गया कि हमने आज इस दे ा मे ऐग्रीकल्चर को प्राथमिकता देनी है। इसकी वजह यह है कि हमारा दे ा एक कृशि प्रधान दे ा है और इससे जेसी हालत है जब तक हम खेती को प्राथमिकता नही देंगे हम आगे नही बढ़ सकते और खेती के जो बड़े जराए है वे है इरीगे ान एंड पावरं इन दो जराओ को अगे बढ़ाकर हम काफी आगे बढ़ सकते है। अगर हम पावर मे सैल्फ सफि ाऐंट न हो, तो हम तरक्की नही कर सकते और यही वजह है कि राज्यपाल महोदय ने एक टाईम बाउंड प्रोग्राम पावर का रखा हे कि 1977—78 तक हम पावर मे सैल्फ सफि ैंट हो जायेगे और इसी तरीके मे खेती को आगे बढ़ाने के लिये चाहे वह

खाद का मामना हो, चाहे बीज का मसला हो, सरकार की तरफ से जो कार्यवाही की गई है वह सिर्फ खेती को आगे बढ़ाने की कोि ा ा की है। कोई भी फिस्कल पालिसी या डिवेल्पमैंट प्रोग्राम कामयाब नही हो सकता जब तक कि सरकार के अंदर स्टेबिलिटी न हो। चौधरी बंसी लाल से पहले यहां पर सरकार के अंदर स्टेबिलिटी नही थी। हरियाणा मे आया राम और गया का बोलबाला था और आज वही हरियाणा है, जहां आज सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। आज हरियाणा सबसे महत्पूर्ण स्टेट है। हिन्दुस्तान मे कोई भी ऐसी स्टेट नही है जिसने इतने थोड़े समय मे इतनी तरक्की की हों आज हमारा प्रदे ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन पिछले दो वर्शो मे प्रगति कुछ कम हुई। मैं यह तो नही कहता कि इसने बहुत ज्यादा प्रगति की है। कई मामलों मे हमने प्राथमिकतादी है, लकिन बड़ी वजह यह है कि हमे सैंटर के साथ रहना पड़ता है, हमे लोन्ज वगैरा उनसे मिलते है। अगर आप असल बजट मे देखे और जो यहां पर दिया गया है हरियाणा बजट एट ए ग्लान्स कि कितना लोन बिजली के लिये लेना पड़ा, कितना लोन सिंचाई के लिये, नहरों के लिये लेना पड़ा और उस लोन के ऊपर जो ब्याज देना पड़ता है। आज सारे दे ा मे जो ब्याज की पूरी भाक्ल है, वह 350 करोड़ है और अगर पांचवीं पंचवर्शीय योजना का सही सैट अप हो गया तो यह 350 करोड़ रूपये का ब्याज एक हजार करोड़ रूपये पर पहुंच जायेगा। यह ब्याज महज बिजली और सिंचाई के लिये लिया गया जो लोन है उसके ऊपर है। मैं एक चीज जरूरी समझता हूं कि जहां हम कृशि

उपज बढ़ाने को प्राथमिकता देने है, और कृशि इन पुटस को बढ़ाने को प्राथमिकता देते है, बिजली और नहरों के लिये प्राथमिकता देते है और इन चीजों के लिये जो लोन लेना पड़ता है, उसके ऊपर ब्याज नही होना चाहिए। यह ब्याज माफ होना चाहिए तभी आगे बढ़ सकते है। कई मेरे साथियों ने कहा कि यह तो डैफिसिट बजट है। मैं कहता हूं कि डैफिसिट बजट हमें माटिवेट करता है। डैफिसेट बजट होना तो बड़ी खु ाी की बात है। हमारा यह मोटिव है कि हम वेस्टफुल ऐक्सपेंडीचर न करे, हम ऐसी चीजे रखे, जो प्रोडक ान मोटिवेटिड हो जो हमें इमिजियेट रिटर्न दे। तीन दायरे है। सब से पहला दायरा है एग्रीकल्चर । एग्रीकल्चर मे एमिजिएट रिटर्न होती है । खर्च की किफायत की तरफ नजरसानी रखे। दूसरा हे इंडिस्ट्रिसल सैक्टर इसमे जो हम इंडस्ट्री जगाते है पांच साल बाद रिटर्न आने लगती है। ऐग्रीकल्चर सैक्टर ऐसा सैक्टर है जिसमे तुरन्त रिटर्न होती है। तीसरा दायरा हे कम्युनिके ा, ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार से प्रोडक ान के जो दायरे है, उनमे पैसा ऐसे दायरों पर खर्च किया जाये, जिनसे तुरंत रिटर्न आए। यह हमारी इकनोमी को रिजनरेट करती है और हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हें इस वक्त नुक्ताचीनी करने का वक्त नही है। हमे यह देखना हे कि आज हरियाणा किस जगह पर खड़ा हुआ है और अपनी इकनोमी को कैसे साउंड करने की कोि ा ा कर रहा है और जनता की उन्नति के लिये लिये हरियाणा क्या कर रहा है। सारे हिन्दुस्तान के अंदर जो तरक्की आज तक हरियाणा ने की है, वह किसी दूसरी स्टेट ने नही की

है। लेकिन इसके बाद भी हमारी समझ मे नही आता कि हमारे कुछ साथी इधर उधर से आंकड़े लेकन सदन के सामने ऐसी बेबुनियाद बाते रखते है जिनका कोई मतलब नही होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जो मेरे ख्यालात मे है, उनको रखना चाहता हूं। आज हरियाणा मे जो रैवेन्यू आता है वह दो अदारो से आता है। एक है इनकम से रैवेनयू और दूसरे प्रोपर्टी एक्साइज डयूटी से आता है। इनकम टैक्स मे हमारा भोयर है और दूसरा प्रोफै ानल टैक्स है। 1966–67 मे जब प्रोफै ानल टैक्स नही है। प्रोफै ानल टैक्स इनकम कर लगे और इनकम टैक्स का भोयर हम लेते है। दो टैक्स एक ही चीज पर लगे, दो प्वायंट पर लगे, दो प्वायंट पर एक ही किस्म का टैक्स लगे, यह मौरली और लीगली ठीक नही है। आज जो हरियाणा के कर्मचारी चण्डीगढ़ मे है उन पर प्रोफै ानल टैक्स नहीं है और अगर वह कर्मचारी हरियाणा में ट्रान्सफर हो जाता है और आज की कीमत के हिसाब से एक रुपए की कीमत तीन आना है। इस प्रकार आज पांच सौ रुपए की कीमत 100 सौ रुपए है। एक और चीज है कि अरग सैंन्ट्रल गवर्नमैंअ का एम्पलाई हरियाणा में कामा करता है तो उस पर प्रोफै ानल टैक्स नहीं लगता। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सरकार का जितना खर्चा इ स प्रोफै ानल टैक्स नहीं लगता। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सरकार का जितना खर्चा इस प्रोफै ानल टैक्स को लेने में खर्च होता है उससे दूसरे मद में अधिक टैक्स वसूल किया जा सकता है। अगर इस टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे। वैसे भी केवल पचास लाख

की बात है। इसलिए मैं दा तीन साल से चीख रहा था कि प्रोफै ानल टैक्स को खत्म कर दिया जाए। मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इस टैक्स को खत्म कर दें जब हमारी स्टेट सब बातों में आगे है, तो इस प्रोफै ानल टैक्स को खत्म करके हम और ऊंचे क्यों न हों।

दूसरी बात मैं प्रोपर्टी टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। प्रोपट्री टैक्स दो तरह से लेते हैं, एक तो हमारी लोकल बाड़ीज का हाउस टैक्स है और दूसरा एक्साईज टैक ोसन का है। एक ही किस्म का टैक्स दो जगह पर लगे यह ठीक नहीं हैं यह मौरली भी ठीक नहीं और न ही कानूनी ठीक है। मेरा कहना यह है कि चाहे हाउस टैक्स हो और चाहे प्रापर्टी टैक्स हो एक ही प्वायंट पर रिकवर किया जाए और लोकल बाडीज को उनकी परसैन्टेज वापिस कर दी जाए। आज होता यह है कि जो बड़े लोग हैं और उन्होंने बड़े–बड़े मकान बनाए हुए हैं और उनके कमरे खाली प्ड़े रहते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लेकिन एक गरीब आदमी जिसके कर्जा लेकर मकान बनाया है और उसका दो तीन कमरे का मकान है, आमदनी को कोई और साधन नहीं है अपना गुजारा करने के लिए वह कुछ पोर ान किराए पर लगा देता है तो उस पर प्रापर्टी टैक्स और हाउस टैक्स लग जाता है। यह टैक्स जब एस0वो0डी0 की सरकार थी उस वक्त भुरू किया गया था। इस बारे में मेरी यह सुजै ान है कि मकान की मालियत देखकर कुछ एक सीलिंग लेवल लगा दिया जाए और उसके

मुताबिक प्रापर्टी टैक्स लिया जाए। जो बड़े लोग हैं उन पर डट कर टैक्स लगाया जाए, ताकि ऊपर लगाया जाए, ताकि ऊपर और नीचे का जो आमदनी का फक है, वह समता में आ सके और जिस बुनियाद पर हम एक नए समाज की रचना करना चाहते हैं, वह समाज हम बना सकें। इस सिलसिले में मेरी यह तजवीज है कि एक ही टैक्स को दो प्वांयटस से वसूल न किया जाए।

तीसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि हमने पावर और इरीगे ान को तो प्राथमिकता दी हुई है लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि हमारे प्रदे ा में जहां हम जराए बढ़ाते जा रहे हैं वहां पापुले ान भी बढ़ती जा रही हैं यह मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के टाईम में कहा था कि पापुले ान भी बढ़ती जाती है और हम जितनी भी प्रोडक ान और डिवैल्पमैंट करते हैं, उससे आम जनता के स्टैझडर्ड आफ लीविंग को प्रोत्साहन नहीं मिला और हमारी परकैपिटा इनकम पर भी फर्क पड़ता है। तो नतीजा क्या है, इस पापुले ान को कन्ट्रोल करने के लिए जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे एक साथी ने कायदे कानून की बात कही कि इस पर कानून लगाया जाए। मैं कहता हूं कि जब तक हम इस पर मौरल सैंक ान नही लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो क्यों न हम इन तरीकों को अपनाएं। सोसाइटी में चाहे वहां पंडित हों, चाहे ग्रन्थी या और महाधी ा हों, हमैं यह तहैया कर लेना चाहिए कि हमने पापुले ान पर कन्ट्रोल करना है। कानून के बजाय हम मर्यादा

सैन्क ान से इस काम को कर सकते हैं। जैसे लड़ाई के टाईम पर हम इकट्ठे होकर मुकाबिला करते हैं, तो क्यों न ऐसे ही इसका भी मुकाबिला करें सरकारी लेवल पर जो काम चल रहा है ऐसो करने से हम उसमें काफी मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जमुना नगर में फैमिली प्लानिंग के लिए मैं मजदूरों में कोि ा ा कर रहा था तो एक पंडित जी बोले कि अगर सरकार की फैमिली प्लानिंग उस समय भुरू होती, जब बाल्मिकी जी पैदा हुए थे तो न बाल्मिकी जी होते और न वे रामायण रचते। तो ऐसे धर्म में वि वास रखने वाले लोगों को मैं इस सदन के द्वारा बताना चाहता हूं कि आज हमारा दे ा किस तरफ जा रहा है। जब मिश्र व ईरान जैसे मुस्लिम दे ाों ने यह घोशणा कर दी है कि एक भाादी से ज्यादा भाादी नहीं करेंगे और इतने बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदाा नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान क्यों नही कर सकता। आज हमारे लिए यह बड़े अफसोस की बात है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वर्श 2000 में हमारी पापुले ान बढ़ कर दो सौ करोड़ तक हो जाएगी तो क्या हालत होगी। इसमें एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि गरीब तबके में ज्यादा पापुले ान बढ़ती है। जिसमें हरिजन आ जाते हैं। मैं अपने हरिजन भाईयों से माफी चाहूंगा। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक सुधार की बात कह रहा हूं। इसमें एक कारण यह भी है कि गरीब आदमियों की एन्टरनटेनमैंट व रोजगार के साधन कम हैं इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कम से कम हरिजन क्लास और गरीब तबके के लिए ऐन्टरटेनमैंट व रोजगार के साधन जरूर जुटाए

जाएं, ताकि बढ़ती हुई पापुले ान को कुछ तो रोका जाए और काम में लगे रहने के कारण पैदावार की तरफ इनका रूझान न हो।

श्री अमर सिंहः ब्राह्माणों के भी 11–11 हैं।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः उनके नहीं हैं। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए यह साधन प्रोवाइड करें। मैं हरिजनों के लिए ही नहीं कहता, बल्कि मैं तो उन सबके लिए कह रहा हूं जिके पास एन्टरटेनमैंट व रोजगार के साधन नहीं हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो पापुले ान पर भी कन्ट्रोल होगा और हमारा दे ा भी विकास करेगा।

Deputy Speaker: I will request the Hon. Member to wind up his speech withing five minutes.

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः मैं पांच मिनट में खत्म कर देता हूं। लेकिन आप बीच में टोक कर मेरा टाईम वैसे ही खत्म कर देंगी।

Deputy Speaker: Some other Members are also keen to speak and the Finance Minister has to reply to the debate .....

श्री गिरी ा चन्द्र जो ीः अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं, वह है बच्चों की एजुके ान के सिलसिले में। मैं इस में एक बात रखता हूं कि आज बच्चों का रूझान इधर हो गया है .....

Deputy Speaker: Please wind up within five minutes.....

Shri Girish Chander Joshi: I will certainly do, Madam..... आज बच्चों को ि ाक्षा इस प्रकार की दी जाती है कि वे बच्चे गुनहगार नहीं हैं, बल्कि बच्चों की निस्बत हम गुनगहार हैं। इसलिए ि ाक्षा को जो तरीका है, उसमें तबदीली जरूर आनी चाहिए और वह इस तरीके की हो कि बच्चे जिस समय भी क्लास में रहें वे खाली न रहें। जब उनका पीरियड खाली हो तो उस समय उनको कोई ऐसा काम दिया जाए जिससे वे बिजी रह सकें। टैक्नीकल और साईंस साईड में तो बिजी रहते ही हैं लेकिन जो आर्टस के स्टूडैन्ट हैं, वे गड़बड़ करते हैं। इसलिए ि ाक्षा की पद्धति हमारी ऐसी हो, जिससे कि उनको नौकरयां न ढूंढनी पडें वे अपना काम खुछ कर सकें। जापान में आप देखें आज घर–घर में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और इसी तरह से जर्मन में देख लें वहां पर आप देख लें कि औरतें अपने बच्चों को भी खिला रही हैं और काम भी कर रही हैं। इस तरह से हमारे बच्चे अगर घरों में काम करें तो वे अपने पांवों पर भी खड़े होंगे और हमारा दे ा भी तरक्की करेगा। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ई वर सिंह पदासनी हुए) चेयरमैन साहब, मुझे खत्म करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं इन भाब्दों के साथ वित्त मंत्री ने जो बजट रखा है और डिमांडज पुट अप की हैं मैं उसका जोरदार भाब्दों में अनुमोदन करता हूं

और उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उस पर गौर की जाएगी।

चौधरी पीर चन्द बरवाला एस0सीः चेयरमैन साहब, आपने जो मुझे बोलने के लिए टाईम दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम दैंगे। मैं डिमांड नंबर, 13,2,3 और 17 पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, डिमांड नंबर 13 के अन्दर एमाउंट तो काफी रखा गया है। यह समाज कल्याण विभाग से संबंधित हैं। इसमें 24259380 रुपये रखे गए हैं। लेकिन जब यह किताब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हरिजनों पर कितना रुपया खर्च होता है। यानी बहुत कम रकम उन पर खर्च की जाती है। यह जो सारी की सारी रकम है यह तो किसी और मदों के लिये रखी गई है। कुछ तो फैमिली प्लांनिंग के लिये है और कुछ स्टाफ के लिये हैं। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फैमिली प्लानिंग जो है यह हरिजनों के ऊपर जबरन लागू किया जाएगा और उसी पर यह सररा रुपया खर्च करना चाहते हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह रुपया उन्हीं के लिये खर्च किया जा रहा है या हरियाणा के हर व्यक्ति पर यह लागू होगा ? जैसे अभी जो ी साहब ने बताया कि हरिजनों को फैमिली प्लानिंग ज्यादा करना चाहिये। क्या हरिजन बाहर के हैं, इनको पुलिस भी पकउ़ कर ले जाए, अफसर भी ले जाएुं और बीच के दलाल भी ले जाएं क्योंकि तहसीलदार उनको ले जायेगा तो उसे

ट्रांजिस्टर मिल जायेगा और अगर गांव का जमींदार ले जायेगा तो उसे सीमैंट के पांच दस कट्टे मिल जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह फैमिली प्लानिंग का प्रचार करते हैं कि हमारे समाज को कम बच्चे पैदा करने चाहियें क्योंकि हमारे साधन इतने नहीं हैं हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ज्यादा बच्चों का पालन पोशण कर सकें, उनको तालीम दे सकें और रोटी कपड़ा दे सकें। इसलिये हमें यह समझ नहीं आती कि यह सारे लोग क्यों इस बात पर उतारू हैं कि हरिजनों पर सारी बातें लाद दी जायें। हर कोई कहता है कि हरिजनों को ही फैमिली प्लानिंग की स्कीम का ि ाकार बनाया जाये। मैं अर्ज करता हूं कि बहुत जगह तो ऐसा हुआ है 18/20 साल के गैर भाादी भाुदा लड़कों के आप्रे ान कर दिये गये और उनकी जिन्दगी खराब कर दी गई। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब यह स्कीम है कि दो बच्चे या तीन बच्चे इससे ज्यादा पैदा नहीं करने हैं तो फिर क्यों ऐसा नहीं किया जाता कि जिनके तीन से ज्यादा बच्चे हैं उन सबका आप्रे ान कर दिया जाये लेकिन यह बात नहीं करते जो आता है वह यही कहता है कि हरिजनों की फैमिली प्लानिंग कर दो, यह बात ठीक नहीं है कि हरिजनों को ि ाकार बनाया जाये। यह स्कीम सब पर लागू की जाये। फिर हरिजनों के उद्दार के लिये 20 लाख की रकम रखी गई है। इसमें महकमा की बिल्डिंग भी आ गई और उन कर्मचारियों का स्टाफ का खर्च आ गया है जो इस में काम करते हैं जहां तक स्टाफ की बात है इसके अन्दर बड़ी मु ि कल से पांच फीसदी इस जमात के कर्मचारी मिलेंगे बाकी सारे स्वर्ण हिन्दू ही

यह तनखा का पैसा ले जाते हैं इस महकमा के नाम पर। तो यह सारी रकम काटने के बाद बहुत थोड़ी रकम रह जाती है जिसका हमारी यह सरकार ढिंढोरा पीटती फिरती है कि हरिजन के लिए यह कर दिया वह कर दिया। यहां हाउस में भी और बाहर भी यही चर्चा किया जाता है कि साहब हरिजनों के लिए बहुत खर्च कर रहे हें उनको बहुत सहूलियतें दे रहे हैं, उनके लिए मकान भी बना दिए, प्लाट भी दे दिए, जमीनों भी दे रहे हैं और उनके लिए धर्म ाालाएं और कुएं भी बना दिये हैं, लेकिन आप देखें इस रकम से क्या कुछ हो सकता है, जो हरिजनों के लिए बजट में रखी गई हैं। ऐलान करते हैं कि हम तीन हजार प्लाट हरिजनों को देंगे मकान बनाने के लिए लेकिन मकान बनाने के लिए कुछ नहीं। हमारे एक साथी जो अपोजी ान में हैं और अब कांग्रेस मे जाने के लिये बहुत उत्सुक है, कहा था कि हरिजनों को चांद पर प्लाट मिलेंगे। तो यह हालत है। सारे बजट मे अगर देखा जाये, तो 21 लाख 90 हजार रूपये बाकी रह जाता है जो इस साल हरिजनो पर खर्च करने जा रहे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते है कि इस रकम से कितने मकान बनेंगे और कितनी जमीन खरीद कर हरिजनों को द देंगे और दूसरे इनके मामने हल कर सकेंगे। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हरियाणा मे हरिजनों की आबादी 22 लाख और इन पर इस साल जो खर्चा किया जा रहा है, जिसमे वजीफे भी आ गये, मकान प्लाट भी आ गये, ग्रांटें और लोन भी आ गये और इंडस्ट्री लगाने के लिये लोन भी आ गये, आ गया 21 लाख 90 हजार रूपये का अमाउंट है और 22 लाख

हरिजनों की आबादी है। इसका मतलब है कि एक साल मे एक हरजन के लिये 95 पैसे से भी कम खर्च होना है। तो आप अंदाजा लगा ले कि इन 95 पैसो से हरिजन की कितनी तरक्की हो जायेगी। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हरिजनों के बारे मे उनकी यही पालिसी है, नीयत है, तो इसस अच्छा यह है कि हमें यह भी न दो ताकि हमारे ऊपर यह जो कलंक लगता है कि साहब हरिजन ही सब कुछ ले गये, खा गये, वह तो न लगे, आज हर आदमी चाहे देहात मे हे, या भाहर मे यही कहता है कि सब कुछ हरिजन ही ले गये, सरकार हरजनों को खु ाहाल कर रही है?, हरिजनो को यह दे दिया वह दे दिया। लेकिन ई वर ही जानता है कि यह सरकार हरिजनों की किस तरह से खु ाहाली करना चाहती है, उनको तरक्की देनाचहाती हे, उनका स्टैंडर्ड आफ लीविंग ऊंचा करना चाहती है, तो उनकी तरक्की के लिये फराखदिली से खर्च करों यह सरकार, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के मालिक है, उनको पांच पांच दस दस लाख के लोन देती है, लेकिन हरिजन के लिये केवल पचास हजार रूपया रखा गया है, तो इस ढंग से यह सरकार चलती है, जो कहते है कि सब कुछ हरजनों को ही दे दियाकृ

चेयरमैनः जो दूसरे लोन है, उनमे भी हरिजन उसी तरह ले सकते है, जैसे बाकी के।

चौधरी पीर चंदः एक धेला नही दिया जाता है।

चेयरमैनः वह सब के लिये ओपन है हर कोई ले सकता है।

चौधरी पीर चंदः हमें उन से कुछ नही मिलता है। यह वित्त मंत्री और इंडस्ट्री के मंत्री बैठे है एक इंडस्ट्री का नाम लेकर बात दे जिसके लिये लोन दिया हो। अब में डिमांड नं. दो और तीन के बारे मे जो जनरल एडमिनिस्ट्रे ान और पुलिस के बारे मे है कुछ अर्ज करना चाहता हूं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, पुलिस पर खर्च करने के लिये 103907790 रूपये रखे गये है और इस पुसिल पर जो पैसा खर्च किया जाता है, उसके बारे मे मैं करना चाहता हूं कि यह पुलिस हरिजनो, गरीबों की कोई मदद नही करती। पुलिस को और बढ़ाया जा रहा है, पता नही इतनी पुलिस क्यों और भर्ती कर रहे है। इस पुलिस से किसी गरीब और हरिजन को इंसाफ मिलने की गुंजाइ ा नही है, उम्मीद नही है कि मैं इस बारे मे आपको कई केस बता सकता हूं कि गरीबों को रगड़ा ही जाता है, उनको इंसाफ नही दिया जाता है। हिसार जिले के अंदर, हांसी तहसील मे गांव साकर की ढानी मे एक हरिजन बनवारी को खेत मे दूसरे आदमियों ने पानी लगाते हुए मारा और मारने के बार खेत मे ही पड़ा रहा। जब रिपोर्ट की गई, तो सदन थाने वालो ने उसकी कोई परवाह नही की और सिटी के थाने वाले उसको उठा कर लाए। इसके बार इस केस की रफ्ट तक दर्ज नही की गई, बल्कि इसके उलट, जिसने उसको मारा था, उसने इसके खिलाफ 325 का पर्चा दर्ज करके उल्टा

इसके खिलाफ के स बना दिया। डाक्टरों ने इसका मैडिकल किया, उसके हाथ टूटे हुए थे, लेकिन उसको हांसी के हस्पताल मे दवाई तक नही मिली और वह हिसार हास्पिटल मे गया। इसके बाद एस. पी. साहब को कहा, उन्होंने चार दिन के बाद पर्चा दर्ज किया। न ही उसाके हांसी मे दाखिल किया और न ही कोई दवाई मिली। इस तरह से पुलिस ने उसको परे ाान किया। अब हालत यह है कि उसको बुलाते है, धमकाते है और कहते है कि राजीनामा करो, क्योंकि जिस ने उसे पीटा वह भाख्स भैंस बांधता है, उनको चारा देता है और उनके घर मे काम करता है। एक गरीब आदमी के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है और फिर गवर्नमैंट कहती है कि ला एंड आर्डर की हालत ठीक है...

श्री अध्यक्षः क्या यह केस अदालत मे चल रहा है ?

चौधरी पीर चंदः अदालत मे नही चल रहा अगर अदालत मे होता तो मैं ऐसा कहता नही। इसके अलावा मैं करनाल का किस्सा सुनाता हूं। पिछले दिनों 26 नवम्बर को 15–16 वकीलों को इस बात पर पकड़ा गया कि वे जय प्रका ा नारायण की पार्टी के है। उनको पकड़ने के बाद मिनिस्अर साहब ने यह इत्तलाह दी गई कि उनको 27 तारीख को गिरफ्तार किया गया। दरअसल वे 26 नवम्बर को गिरफ्तार हुए थे। जब जय प्रका ा नारायण आये तो वहां पर लाठियां पड़ी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब मैं कुरूक्षेत्र गया तो रेलवे फाटक पर मेरी कार रूकी। मैंने देखा कि एक बस मे सिपाही भरे हुए थे, उनके सफेद

कपड़े थे, हाथ मे एक एक कापी दे रखी थी जेसे वे स्टूडैंट हो। सब के हाथ मे एक एक झण्डा था। यह हालत पुलिस की है, अगर आपने ऐसा करना है तो पुलिस को रखने का क्या फायदा है ? यह तो लोगों के जान माल की हिफाजत करने के लिये रखी जाती है, न कि इस तरह के काम करने के लिये। क्या सरकार ने पुलिस इन्ही कामों के लिये रखी है ? पुलिस पर दस दस, ग्यारह ग्यारह करोड़ रूपया खर्च किया जाता है और गलत कामों पर खर्च होता है। इस तरह के हालात नही होने चाहिए, पुलिस का ठीक इस्तेमाल होना चाहिए।

इसके अलावा देहातो मे बिजली की हालत तो देखो। बिजली के लिये इन्होंने 23 करोड़ रूपया मांगा है, लेकिन देहातों मे बिजली की बुरी हालत है। इधर बजट मे घाटा चला आ रहा है लेकिन फिर भी बिजली पर खर्च करते आ रहे है। अगर जमींदार को बिजली नही मिलनी है तो इस पर इतना ज्यादा खर्च करने का क्या मतलब है ? आज एग्रीकल्चरिस्टस को बिजली नही मिलती, इंडस्ट्रीज वालो की फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, सब लोग बिजली के बगैर तंग है। अगर ऐसा है तो तार खींचने के लिये, खम्भे लगाने के लिये जो रूपया आपने 23 करोड़ के करीब मांगा है, इसकी क्या जरूरत है, यह ठीक नही है। इतना रूपया इस छोटी सी स्टेट का खर्च किया जाये जिससे जनता का कोई भला हनी होने वाला तो बुरी बात है क्योंकि फायदा तो जनता को हो नही रहा। जहां तक हैल्थ डिपार्टमैंट का ताल्लुक है, ठीक है, बिल्डिंग्ज बनानी

चाहिएं जो अच्छे काम हुए है मैं उनकी तारीफ कंरूगा। बिल्डिंग बनानी ठीक है, डाक्टरों को रखना ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूं लेकिन ऐसे काम नही होने चाहिए जिन पर रूपया नाजायज खर्च हो और स्टेट को नुक्सान हो, यह तो स्टेट पर एक भार बन कर रह जायेगा। इस खर्चे हो कम करने के लिये मैं आपकी मारफत यही कहूंगा कि जहां डिमांड ज्यादा है और खर्च कम होता है वहां ज्यादा किया जाये लेकिन वैलफेयर डिपार्टमैंट को पैसा दो पुलिस को दो जिससे फायदा कोई नही होात, ऐसा नही होना चाहिए, इस तरह स्टेट का घाटा पूरा नही हो सकता। इससे जनता का हित नही है बल्कि धोखा है और इस धोखे का नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज दे ा के लिये हालत अच्छी नही है। गरीब आदमी की हालत इतनी खराब है कि उसको खाने के लिये रोटी नही मिलती, पहनने के लिये कपड़ा नही मिलता। आप पैसा उन कामों पर लगाओं जहां मजदूर लोग काम करते है। सड़कों पर लगाओ, नहरो पर लगाओ, कारखानो पर लगाओ लेकिन इन कामो मे सरकार ने पैसा कम रखा है जहां मजदूर लोग काम करते है। गरीब आदमी के लिये तो इन के पास कोई रोजगार है ही नही। रोजगार का कोई साधन नही, इंडस्ट्रीज लगाने के साधन नही, सिर्फ इस बात के लिये साधन है कि टैक्स बढ़ा दो और पुलिस मे पैसा दे दो ताकि डंडा चलता रहे। डंडे के लिये सरकार हुक्म देती रहती है.....

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): क्या बजट पढ़ कर बोल रहे हो या ऐसे ही ?

चौधरी पीर चंद: पढ़ कर बोल रहा हूं। अगर गरीब आदमी को रोजगार देना है तो इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा पैसा दो और हर गांव मे कोई न कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाई जाये जैसे लोहार का काम, खड्डी का काम, लकड़ी का काम और भी कई छोटे छोटे काम है। आज बैकवर्ड क्लासिज के काम खत्म हो रहे है, लोहार गांवों मे है लेकिन उन का काम बड़ी इंडस्ट्रीज वालों ने ले लिया है। आज बड़े बड़े आदमी अमीर होते जा रहे है और गरीब मरते जा रहे है। स्पीकर साहब, आज हरियाणा मे यह हालत है कि हर व्यक्ति यह बात सोचता है कि मेरा गुजारा कैसे चलेगा ? सरकार की यह नीति है कि बड़े बड़े आदमियों को पांच लाख, दस लाख और बीस लाख तक लोन देती है और जब गरीब आदमी की बारी आती है तो भार्ते लगा देती है। गरीब आदमी उन भार्तो को पूरा ही नही कर पाता और अगर कोई पूरा करें तो दफ्तारों के चक्कर काटने पड़ते है। वे तो बड़े आदमियो के रिसोर्सिज है, नीचे से ऊपर तक मिले हुए है, इनको लोन मिल जाता है लेकिन गरीब आदमी को कोई पूछता ही नही। मैं आपका ज्यादा वक्त नही लेता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: राव अभय सिंह जी बोलेंगे। समय कम है इसलिये आपको 5 मिनट मिलेंगे।

राव अभय सिंह (रिवाड़ी): स्पीकर साहब, मैं गवर्नर ऐड्रैस पर भी नही बोला था लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये जनरल डिस्क ान पर न बोल कर आपने इलाके के मुताल्लिक ही कुछ बातें आप के सामने रखूंगा। अभी एक मैंबर साहब ने फरमाया कि स्टेट का स्ट्रक्चर बुलन्द नही है और हरियाणा मे कोई तरक्की नही हुई। स्पीकर साहब, जब बाहर उन भाईयों से बात होती है तो ये कहते है कि वाक्या ही हरियाणा मे बड़ी तरक्की हुई है लेकिन यहां पर सिर्फ अपोजी ान ने नाते, सिर्फ क्रिटिसिज्म के नात वे कहते है कि हरियाणा मे कोई खास तरक्की नही हुई। स्पीकर साहब, चूंकि मैंने अपने हल्के के मुताल्लिक कहना है इसलिये सिर्फ दो चार बातों की तरफ ही उन मैंबर साहेबान का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस वक्त हरियाणा बना, जैसाहमारे जो ी साहब ने फरमाया था, यह आया राम और गया राम के नाम से बिल्कुल बदनाम हो गया था। जहां कहीं भी हम हरियाणा के लोग जाते थे लोग पहले यही कहते थे कि लो आया राम और गया राम के सूबे से ये लोग आ रहे है लेकिन जब से चौधरी बंसी लाल की सरकार पावर मे आई तब से इस 6 साल के अस्र मे उन्होंने हमारी हकूमत को भी स्टेबल बनाया और जनरल ऐडमिनिस्ट्रे ान को भी काफी मजबूत किया है। तो मैं अपनी सरकार को मुबारिकबाद देता हूं, खासकर चौधरी बंसी लाल जी, जिन्होंने इस 6 साल के अर्सा मे हमारी हकूमत को स्टेबल बनाया और जिसकी वजह से हम लोग काफी तरक्की कर सके।

दूसरी बात, स्पीकर साहब, मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि बहुत से इलाके हमारे इस सूबे मे ऐसे थे जो बहुत बैकवर्ड थे। कुछ इलाके ऐसे थे जहां पीने का पानी तीन तीन चार चार मील से लाते थे। कई जगह तो ऊंटों पर काफी दूर दूर से पानी लाते थे जैसे तो ाम के इलाके मे या दूसरे इलाके मे, इस सरकार ने मीठा पीने कापानी मुहैया किया है। अब वहां पर तीन तीन चार चार मील से पानी नही लाना पड़ता बल्कि हर गांव मे नल हमारी सरकार ने मुहैया किये है और लोगों को बड़ी सहूलियत दी है।

यही नही स्पीकर साहब, हमारी इस सरकार ने तीन चार बड़ी बड़ी नहरे भी बनाई है। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, चक्रवर्ती कैनाल हे, जो कि हमारे गवर्नर साहब के नाम पर है। हमारे महेन्द्रगढ़ के इलाके मे जो एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है उसे नेहरू कैनाल कहते है। उस पर भी अब काम भाुरू हो गया है। दो तीन नहरें तो कंप्ली ान के नजदीक है और एक दो कंप्लीअ हो गई है। वे नहरें ऐसे इलाके मे बनाई गई है जहां बारि ा बहुत कम होती थी और हर साल, दूसरे साल या तीसरे साल बहुत कहत पड़ता रहता था। तो क्या हरियाणा के स्ट्रक्चर को बुलंद करने मे या हरियाणा की मियार को बुलन्द करने मे ये नहरे काफी नही है ?

इसके अलावा, स्पीकर साहब, सबसे बड़ा अहम काम जो हमारी सरकार ने किया वह यह है कि गांव गांव मे बिजली

पहुंचाई गई। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आने से पहले सिर्फ दो हजार गांवों मे बिजली थी, बल्कि इससे भी कम गांव मे थी, लेकिन आज हरियाणा मे कोई गांव बाकी नही जहां बिजली के लट्टू न जलते हो या जहां हमारे टयूबवैल के पाईप न कूदते हो। मैं अब फिर उन भाईयों से पूछूंगा कि क्या इससे हरियाणा का स्ट्रक्चर नही बढ़ा है ?

इसके अलावा स्पीकर साहब, हर जिले के हैडक्वार्टर्ज पर, चाहे आप करनाल को देख लीजिए, चाहे गुड़गांव को देख लीजिए, बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि सब डिविजनल हैडक्वार्टर्ज पर भी, जहां पर पहले हस्पताल की बिल्डिंगज की दिक्कत थी आज वहां बड़ी आलो ाान बिल्डिंग तैयार की गई है। रोहतक मे आप देखते है कि एक हजार बिस्तारों का हस्पताल हमारी सरकार ने मुहैया किया है और उसमे हर तरह की सहुलियते दी गई है। इसके अलावा भी स्पीकर साहब, और बहुत सी बाते है जिनसे यह साबित होता है कि हमारे हरियाणा के सूबे ने हर भाोअबे मे, चारो तरक्की की है और इसका मियाद बुलन्द हुआ है।

स्पीकर साहब, अब मैं चंद बाते अपने हल्का के मुताल्लिक अज्र करना चाहता हूं डिमांड 1 ननरल ऐडिमिनिस्ट्रे ान के बारे मे है। जब पहले रिवाड़ी तहसील जिला गुड़गांव का हिस्सा थी क्योंकि अब तो तकरीबन एक डेढ़ साल से महेन्द्रगढ़ जिला मे जो एक बैकवर्ड जिला है भाामिल कर दी गई, उसके एम्पलाईज को बैकवर्ड अलांउस नही मिलता था लेकिन जिस वक्त रिवाड़ी

सब डिविजन को महेन्द्रगढ़ मे भामिल किया गया था उस वक्त य यकीन दिलाया गया था कि चूंकि महेन्द्रगढ़ बैकवर्ड एरिया है इसलिये रिवाड़ी के मुलाजमिन को भी उनके ऐट पर रख जायेगा, बैकवर्ड अलांउस दिया जायेगा लेकिन अभी तक वह उन्हें नही मिला है। इसलिये मेरी गुजारि ा है कि रिवाड़ी सब डिविजन के मुलाजमीन को भी बैकवर्ड अलांउस दिया जाये और ऐट पार उनके किया जाये।

दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये मद नं. चार पर रैवन्यू डिपार्टमैंट के बाबत रखना चाहता हूं। इस साल, स्पीकर साहब, हमारे जिला महेन्द्रगढ़ मे, खास तौर पर रिवाड़ी तहसील मे, काफी जब्रदस्त कहत के लिये, जो ड्रौट हिट एरिया है उनके लिये, काफी इंतजाम किया हे लेकिन मैं अपने हल्के के मुताल्लिक एक अर्ज करूंगा। मैने पहले भी पंडित जी से अर्ज की थी और क्वै चर अवर मे भी सप्लीमैंटरी क्वै चर पुट किये थे कि चार की हालत वहां नातसल्लीबख्भा है, चारा बहुत कम तादाद मे वहां जा रहा है। धारूहेड़ा और उसके आसपास के गांव मे तो चारा गया ही नही। मैंने अपने पंडित जी से, रैवेन्यू मिनिस्टर साहब से अर्ज किया था और जिले के डिप्टी कमि नर तथा एस.डी.ओ. से भी कहा था कि धारूहेड़ा मे जो रिवाड़ी से तकरीबन 11 मील के फासले पर है, चारे का डिपो खोला जाये ताकि लोगो को ज्यादा दूर न जाना पड़े । गवर्नमैंअ की यह पालिसी भी है कि तीन चार मील से दूर, चारा या तकाबी लेने के लिये, जाने की दिक्कत

लोगो को नही दी जानी चाहिए। तो सरकार अपनी पालिसी के मुताबिक भी मेरा यह निवेदन हे, धारूहेड़ा मे जल्दी से जल्दी चारे का डिपो खोले।

इसके बाद, स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि मेरे हल्के मे धारूहेड़ा, खटावली और हटसाना इन गांव मे हरिजन बस्तियां बसी हुई है। पहले यह बहुत बंजर, उबड़ खाबड़ और बिल्कुल ही निकम्मी जमीन थी। (घंटी).....सिर्फ दो चार मिनट स्पीकर साहब और लूंगा। तो मैं कह रहा था कि पहले वह जमीन बेकार थी और हमारी सरकार ने उसे यूटिलाईजे ान आफ वेस्ट लैंड एक्ट के तहत तथा चूंकि वह कस्टोडियन जमीन भी थी, उन हरिजनों को अलौट कर दिया था और अलौट करते वक्त यह भार्त लगाई थी कि जब वे उसे आबाद कर लेंगे तो उन्हे ही वह जमीन दे दी जायेगी, उनको उसका मालिक बना दिया जायेगा और उसकी रजिस्ट्री उनके नाम करा दी जायेगी। उन लोगों ने काफी पैसा लगा करके मेहनत करके, कईयों ने तो टयूबवेल भी लगाये हए है, जब उसे काबिलेका त कर लिया तो अब उन्हे नोटिस जा रहा है कि तुम्हारी यह जमीन नीलाम की जायेगी। तो मेरी सरकार से यह गुजारि ा है कि ऐसा न किया जाये क्योंकि वे बहुत गरीब लोग है। उन्होंने पंद्रह बीस साल मेहनत करके उसे काबिले का त बनाया है। ऐसी ही जमीन, स्पीकर साहब, फरूखनगर, गुड़गांव, मे भी थी। वहां भी हरिजनों को जमीन अलौट की गई थी। उनकी रजिस्ट्री हो गई है,उन्हे उसका मालिक बना दिया गया

है, तो मेरी गुजारि ा यह है कि इन लोगो को भभ इस जमीन का मालिक बनाया जाये और ठीक भाव पर वह जमीन उनको दे दी जाये।

स्पीकर साहब, डिमांड नं. 8 पी.डब्ल्यू.डी. के मुताल्लिक है। यह भी पंडित जी का महकमा है। इसके बारे मे अर्ज यह है कि जिस वक्म हमारी सरकार ने क्रै ा प्रोग्राम रोड़ज का बनाया था तो उस वक्त यानी तकरीबन 60–65 फीसदी गांव हरियाणा के सड़कों के साथ मिला दिये गये लेकिन बदकिस्मती से मेरे हल्के मे 10–12 मुरब्बा मील के कम्पैक्ट एरिया मे 14–15 गांव ऐसे रह गये है जिनमे अभी तक कोई ऐप्रोच रोड़ नही बनी हुई है उन गांवो के नाम लूंगा तो टाईम काफी लगेगा लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं वे है मालेहड़ा, ढाकिया, सूरजपूरा, सूनारिया, तारपूर, मीरपूर, तुरकियावास, जांट, गोकलपूर, कुम्भावास, रामगढ़, भगवानपुर, और जांटी। ये कोई 15 करीब गांव है जो इस ऐप्रोच रोड़ की सहूलियत से बिल्कुल महरूम रह गये है। यह 10–12 मील का कम्पैक्ट एरिया है। इसलिये मेरी गुजारि ा हे कि इन गांवो को प्रायरिटी देकर या रीलिफ फण्ड से पैसा ले कर ऐप्रोच रोड़ बनायी जाये। (घंटी) स्पीकर साहब, दो चार बाते और रहा गई है, अभी खत्म करता हूं इसके अलावा डिमांड नंबर 10 है। यह हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे मे है। रिवाड़ी का हस्पताल दो साल से बन रहा है। इस पुराने हस्पताल की बिल्डिंग को गिरा कर नयी बिल्डिंग बनायी जा रही है। पुरानी बिल्डिंग तो गिरा दी है लेकिन

अभी तक नयी बनी नही है इसलिये मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से अर्ज हे कि इस हस्पताल को ज्यादा पैसा दे कर इस साल मे बना दिया जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी। लोगो की जो दिक्कत हे वह भी दूर हो जायेगी।

डिमांड नंबर 11 अरबन डिवैल्पमैंट के बारे मे है। रिवाड़ी भाहर एक बड़ा अहम भाहर है। रिवाड़ी भाहर की हालत बहुत खराब है। सारी सड़के टूटी हुई है, सेनीटे ान की हालत बड़ी खराब है। सीवरेज का काम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। गन्दगी के ढेर वहां पड़े रहते है इस भाहर की तरफ जब तक सरकार कोई खास ध्यान नही देगी तब तक इसकी हालत नही सुधर सकती। कोई अच्छी रकम गवर्नमैंट की तरफ से म्युनिसिपल कमेटी को नही दी जायेगी तब तक इस भाहर का कल्याण नही हो सकता। अभी परसो एस.डी.ओ. सिविल के महकमे ने एक मीटिंग बुलायी थी, वहां पर यह बताया गया कि भाहर की डिवैल्पमैंट के लिये कमेटी के पास से एक या सवा लाख रूपया सालाना लग सकता ह। तो स्पीकर साहब, इस रिवाड़ी भाहर की इतनी खराब हालत है जिसके विशय मे ब्यान नही किया जा सकता। मैं सरकार से, लोकल बाडीज के मिनिस्टर साहब से दखास्त करूंगा कि इस भाहर की तरफ खास तौर से ध्यान दे। इसके लिये खास रकम मोहैया नही करेंगे तो इसकी डिवैल्पमैंट नही होगी।

पब्लिक हैल्थ कि मुताल्लिक भी मैं अर्ज करूंगा। मेरे अपने हल्के मे मसानी वाटर सप्लाई स्कीम है। उसके पास ही

डूंगरवास, फीदडी, बुडानी, तुरकीयावास, रामगढ़ और भगवानपुर गांव है। ये गांव इस स्कीम के साथ कुनैक्ट होने चाहिए। इन गांवो का एस्टीमेट बन चुका है। मिनिसटर साहब ने भी अ योरेन्स दी थी। सिर्फ ये चार चार पांच गांव रह गये और सब जगह पानी चला गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस साल के बजट मे ऐसा स्कीम के नीचे इन गांवों को पानी देना निहायत जरूरी है। मैं फाइनेंस मिनिस्अर साहब से और पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इन चार गांवो को जरूर पानी दिया जाये। कहना तो काफी था लेकिन समय नही है इसलिये मैं खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्षः मित्तल साहब आप कम से कम कितना वक्त लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): जितना आप टाईम देंग।

चौधरी फूल चंद (मुलाना एस.सी.): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा होते हुए कई दिन हो गये है। इस सदन के सदस्यों द्वारा दिखाए गये ड्रामें सदन के सामने आये। आपके देखा होगा कई सदस्यों ने अपना पूरा समय लेने के प चात आपके ऊपर ऊंगली उठायी कि समय पूर नही दिया जाता। मैं आपके कुछ आंकड़े बता देना चाहूंगा इंफर्मे ान के लिये। जब से यह सदन इस बार आरम्भ हुआ है गवर्नर एड्रैस मे भाग लेते हुए

हमारे ट्रेजरी बैंचीज के साथियों ने कुल समय लिया चार घंटे 14 मिनट और अपोजी ान के सदस्यों ने लिया तीन घंटे 39 मिनट। इसमे स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह जी ने एक घंटा 14 मिनट लिये और चौधरी ि ाव राम वर्मा ने 46 मिनट लिये गवर्नर ऐड्रैस परं बजट पर जनसंघ की तरफ से चौधरी राम लाल ने 38 मिनट लिये और श्री ि ाव राम वर्मा ने 33 मिनट लिये। बजट डिमांडज पर बोलते हुए ट्रेजरी बैंचीज ने कुल समय तीन घंटे 32 मिनट लिया और अपोजी ान ने चार घंटे 32 मिनट लिया। इसका मतलब यह है कि इतना समय देने के बावजूद भी कुद सदस्यों की यह आदत बन गई है कि वे गलत किस्म की बाते करे, स्पीकर साहब को ब्लेम करे, ट्रेजरी बैंचीज को ब्लेम करें कि उनका पूरा समय नही दिया जाता। अजीब बात हैं। कोइ मौन धारणा करता है, कोई वाक आउट करता है। वाक आउट भी किस तरह से ? लोबी मे गये तो फिर अंदर आकर बैठ गये। एक माननीय सदस्य ने डिक्लेयर किया कि मैं बजट सै ान से वाक आउट करता हूं और करते क्या है बाहर हाजरी का रजिस्टर रखा है, हारजी लगायी और चले गये। तो यह किस प्रकार का वाक आउट माना जाना चाहिए और फिर हाजरी लगा कर अपना टी.ए.डी.ए. क्लेम करने का अधिकार बनता है या नही और जो सदन के जिम्मे, सरकार के जिम्मे इल्जाम लगाये है उसकी पूरी जांच करायें।

स्पीकर साहब, आपने बजट पर बोलने के लिये पांच मिनट का समय दिया है इस अर्से मे मैं कुछ विचार रखूंगा।

समाज कल्याण के बारे मे जो डिमांड नंबर 13 के अंदर फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने दो करोड़ 42 लाख 59 हजार 380 रूपया रखा है। मैं समझता हूं इस मांग मे जो पैसा रखा गया है यह बहुत कम है इसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा वर्ग सब से पिछड़ा हुआ वर्ग है। हमारी पार्टी भी चाहती है सरकार भी चाहती है कि यह वर्ग तरक्की करें इसलिये समाज कल्याण के लिये यह बहुत कम पैसा है। आपने स्पीकर साहब देखा है कि यह समाज सदियों से दबा चला आरहा हैं इसकी उन्नति का अब समय आया है। भारतवर्श की आजादी के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी भी इस वर्ग को उठाना चाहती है लेकिन स्पीकर साहब, देखने मे जो आया हे जो होना चाहिये था वह सब कुछ नही हो पाया ह। इसके बारे मे मैं आपे विचार आपकी मार्फत सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि यदि इस वर्ग को ऊंचा उठाना है तो उनकी आर्थिक द ाा को हर हालत मे सुधारना पड़ेगा। जब किसी वर्ग की आर्थिक द ाा अच्छी नही होगी तो सिर ऊंचा करके नही चला सकता। उनको रोजगार के धंधे उपलब्ध कराये जायें आज बात करने को सैकड़ो है, मैं दावे के साथ कह सता हूं कि हमारा बच्चा, मजदूर किसी भी हालत मे किसी से कम नही। ि ाक्षा प्राप्त करने के प चात चाहे वह अफसर लगे, चाहे किसी और बात मे हो वह किसी से पीछे नही रह सकता है। जब एक गरीब हरिजन को इग्नोर किया जाये कि यह हरिजन है, इस भावना को हटाना है। हमे उन्हे ऊंचा उठाने के लिये प्रयतन करना चाहिए। आपने स्पीकर साहब, समय कम दिया है इसलिये मैं इस विशय मे एक बात कहूंगा कि यहां

कर्ज की बात हाउस मे बार बार कही जाती है। मैं इस बारे मे कहूंगा कि कर्ज से इतना भला होने वाला नही है। जहां तक ग्रांट की बात है, हमारे मंत्री महोदय ने पिछले वर्श चौपालों के लिये कुछ प्रोविजन किया था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बार सारे हरियाणा के लिये केवल 5 लाख रूपये का प्रोवीजन किया गया है जो मैं समझता हूं कि बहुत नाकाफी है। 5 लाख रूपये से कितनी चौपाले हम बना सकेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस तरफ जयादा बजट ऐलोकेट करके सामज के उत्थान के लिये हमें पूर्णतया प्रयत्न करना चाहिए।

अब मैं एक दो बातें अपने हल्के के मुताल्लिक आपके सामने रखूंगा। सड़कों की बात डिमांड नं. 8 के नीचे आती है। हमारे यहां एक सड़क अधोया छप्पर रोड़ है, यह डिस्ट्रिक्अ बोर्ड के समय से मेन रोड है लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनो तरफ से तो यह सड़क बनकर तैयार है लेकिन बीच मे एक किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा छोड़ दिया गया है और नाम रख दिया गया है अधाया छप्पर रोड़। जब तक वह लिंक पूरा नही हो जाता, तब तक हम कैसे उसे अधोया छप्पर रोड़। जब तक वह लिंक पूरा हो जाता, तब तक हम कैसे उसे अधोया छप्पर कह सकते है। इसलिये मेरी गुजारि ा यह है कि इस सड़क को जल्दी से पूर्ण किया जाये। स्पीकर साहब इसी तरह से खेड़ा महुआ खेड़ी की सड़के है। इसके अलावा बए बहुत अहम चीज कालपी जौली रोड़ पर बेगुना का पुल है। यह बात हम कई बाद सरकार के

नोटिस मे ला चुके है लेकिन अब तक उस पर कोइ कार्यवाही नही हुई है। मेरी अर्ज है कि इस काम को जल्दी किया जाये। पब्लिक हैल्थ के बारे मे मेरी यह मांग है कि जिस गांव मे भी यह स्कीम जाये, वहां पर ड्रेनेज का होना बहुत जरूरी है। देखने मे यह आया है कि पानी का ठीक तरह से निकास नही हो पाता ।

अब मैं लेबर एण्ड ऐम्पलायमैंट के बारे मे कहना चाहूंगा। हमारे देहातों के अन्दर लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। उन्हे रोजगार की समस्या हर वक्त काटती रहती है। गरीब आदमी के पास अपने कोई साधन नही होते, जिससे कि वह किसी प्रकार से गुजारा कर सके। इससे भी बहुत बड़ी समस्या हमारे पढ़े लिखे बच्चों की है जो बार बार दिन रात कभी एम.एल.एज. के पीछे, कभी मिनिस्टर्ज के पीछे ऐम्पलायमैंट के लिये घूमते रहते है। आज यह समस्या बे ाक दे ाव्यापी है लेकिन हमें इस बात मे भी पहले करनी होगी कि हम इस समस्या बे ाक दे ाव्यापी है लेकिन हमें इस बात मे भी पहल करनी होगी कि हम इस समस्या को हल करने के लिये ऐसे साधन जुटाये जिससे कि हमारी यह प्रौब्लम समाप्त हो सके। (घंटी) अब मैं और अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर यह बात दोहराना चाहूंगा कि पिछड़े वर्गों के लिये हम जितना ज्यादा बजट ऐलोकेट कर सके, उतना करे ताकि गरीब आदमी भी सामज के अंदर अपना निर्वाह कर सके, उनका पूर्ण रूप से उत्थान हो सके, वे बराबरी पर आ सकें और जो समाजवाद की भावना को लेकर हम चले है, उसको पूर्ण कर सके। धन्यावाद।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोज से बजअ के ऊपर सदन चर्चा कर रहा है ओर तकरीबन 27–28 सदस्यों ने इसमे भाग लिया है जिनमें से आधे से ज्यादा सदस्यों ने जहां तक मैं समझता हूं विरोधी दल या स्वतंत्र एम.एल.एज. समेत, इसकी सराहना की है। मुझे इस बात की बहुत खु ाी है कि तीन चार विरोधी दल के सदस्यों को छोड़ करके बाकी सब ट्रेजरी बैंचिज के भी और उधर के भी सदस्यों ने बजट की बहुत सराहना की हैं बजट का सबसे पहला ट्रिब्यूट यह हो सकता है कि बजट एक बैलेन्सड बजट है और विरोधी दल के कई सदस्यों ने इसको बैलेन्सड बजट बतलाया भी है। मैं उन सब का बहुत आभारी हूं। जनसंध के दोनो सदस्यों और चौधरी चांद राम जी ने बजट को छोड़कर इस तरह बोले जैसे कि वे गवर्नर के ऐड्रेस पर बोल रहे हों और पार्लियामैंट्री ऐटीकेट्स यह है कि जो साहिबान क्रिटीसिजम करें या नुक्ताचीनी करे, वे अपनी नुक्ताचीनी का जवाब सुनने के लिये भी सदन मे मौजूद रहने चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि वे लोग यहां नही है। बजट के ऊपर एक बड़ा भारी हमला उन दो तीन साहिबान ने यह किया कि बहुत जयादा कर्जा लिया गया। हरियाणा हैविली इनडैटिड है और यहां पर टैक्स बहुत हैवी लगे हुए है और पैदावार घटती जा रही हैं जहां तक कर्जे का ताल्लुक है अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने यह बात की, उन्होंने इस बात पर विचार नही किया कि अगर कर्जा न लिया जाता, अगर हरियाणा गवर्नमैंअ कर्जा न लेती तो आज आप जो इतनी तरक्की देख रहे है, यह कहां से आती ? कोई भी

व्यक्ति अगर कारोबार करता है, खेती करता है या दुकान करता है तो उसको कुछ पूंजी की जरूरत होती है। किसान भी जब खेती करेगा तो उसको बीज चाहिए, खाद चाहिए, इनपुटस चाहिएं खेती के औजार चाहिये, ट्रैक्टर चाहिए चा बैल चाहिए। इसके अलावा उसे और भी कई चीजों की जरूरत होती है जिसके लिये वक कर्जा लेता है। अगर कोई आदमी इतना खु ाहाल हो कि वह अपने आप ले सके तब तो चल सकता है वरना अमूमन उनको कुछ न कुछ कर्जा लेकर ही भाुरू करता है। ये जो बड़ी बड़ी कम्पनियां बनती है ये क्या है? कम्पनियां भी इसी तरह करती है कि भोयर होल्डर्ज से रूपया लेती है और उस रूपया को काम मे ला करके, बड़े बड़े कारखाने लगाती है या व्यापार या तिजारत करती है। इसी तरह से हरियाणा गवर्नमैंट का भी वगैर कर्जे के काम नही चल सकता। यह बात ठीक हे कि अगर कर्जा लिया जाये तो वह कंसट्रक्टिव कामों पर लगाया जाये। यह नही कि वह कोई अन प्रोडक्टिव ऐस्पैंडीचर हो। उससे नहरे निकले, बिजली लगायी जाये या पावर जनरे ान का काम किया जाये। इस तरह का खर्च एक प्रोडक्टिव ऐक्सपेंडीचर हे और यह जरूरी चीज हैं इसलिये अगर कर्जा लिया जाये तो ऐसी चीजों पर खर्चा हो। अगर कोई आदमी भाादी के लिये कर्जा लेता है तो वह अनप्रोडक्टिव कहलाता हैं लेकिन अगर कोई कारोबार के लिये कर्जा लेता है तो वह अनप्रोडक्टिव कहलाता हैं लेकिन अगर कोई कारोबार के लिये कर्जा लेना है तो वह प्रोडक्टिव है। इसी तरह से हरियाणा गवर्नमैंट ने भी जितना कर्जा लिया है, उस कर्ज की तादाद बजट

के अंदर बखूबी दी हुई है, प्रोडक्टिव कामों के लिये लिया है, उस कर्जे की तादाद बजट के अंदर बखूबी दी हुई है, प्रोडक्टिव कामो के लिये लिया है । बजअ के अंदर एक और बात है वह यह है कि इसके अंदर कोई हेरा फेरी की बात नही है। जितनी सही फिगर्ज हो सकती है, दी गयी है, जहां पर हमारी कमजोरी है, जहां पर हमारी प्रतिभा है और हम जहां पर आगे बढ़ने वाले है, वह सब उसमे दी हुई है। उसको देखकर अगर हिसाब लगाया जाये तो वह देखा जायेगा कि हमारे हरियाणा की जो अर्थ व्यवस्था है, इकोनौमी है, वह बड़ी साउंउ इकोनौमी है। हमारी इकौनोमी के अंदर कोई ऐसी बात नही है जिस पर अफसोस किया जाये या किसी तरह का खतरा जाहिर किया जाये। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब चौधरी राम लाल जी ने यह कहा कि हमारा दिवाला निकलने वाला है। आप देखिये, कभी कोई ऐसा मोका नही आया जब हम अपनी लायबिलटी को मीट न कर सके हो। जहां तक हम से होता है, हम सब तरफ से अपनी लायबिलटी को मीट करते है। कोई भी ऐसा मौका नही आया जबकि हमें यह कहना पड़ा हो कि हमारे पास देने पड़ा हो कि हमारे पास देने के लिये पैसा नही है यह ठीक है कि कुछ फाइनैंि ायल स्ट्रिन्जैंसी बंगला दे ा की लड़ाई की वजह से हुई और सैंट्रल गवर्नमैंट से हमने जो ओवर ड्राफ्ट लिया था, वे भी इस बार मांगते है लेकिन हमारी अर्थ व्यवस्था ठीक न हो ऐसी बात नही है और हमें कोई खतरे की बात नजर नही आती।

लोंज के बारे मे जो ये लोग इतना कहते है कि हमने इतना लोन लिया हुआ है, अगर हिसाब लगाया जाये तो यह इस बात का इंडैक्स है कि हमारी प्रौसपैरिटी कैसी है ? अध्यक्ष महोदय, हमसे तो पंजाब ज्यादा प्रौसपरस है। पंजाब के बारे मे तो भ्रुबहा भी नही कर सकते कि वह एक प्रौसपरस स्टेट है। वहां पर जो लोन्ज के बारे मे इन्सीटैंटस है, वह मेरे पास है। वहां पर टैक्सिज के इन्सीडैंटस है 92.67 जबकि हमारे यहां हरियाणा मे 73.97 है। अब आप देख लीजिये कि टैक्सिज के अंदर हम पंजाब के मुकाबले मे कहां पर है। इसके अलावा और जितनी भी स्टेटस है जिसमे इंडिया की सब बड़ी से बड़ी स्टेट्स भ्रामिल है, महाराश्ट्र भी आ गयी, यू.पी. भी आ गई, उन सब मे हमारी फिगर सिवाये पंजाब के बाकी सबसे ऊंची है। मेरा कहने का मतलब यह था कि हमारी जो इकौनोमी है, उसमे साउंडनैस है और वेसी कोई बात नही है तो उन्होंने कही । ऐसी कोई बात नही है कि जिस पर कम से कम कोई भ्रुबहा हो या कोई और रूकावट की बात हो। ये सब बाते ठीक चल रही है। ग्रोथ रेट के ऊपर उन्होंने बताया कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वह ठीक नही है। मैं अर्ज करूंगा जिस किताब से उन्होंने पढ़ा था उसी किताब मे बड़ा साफ लिखा हुआ है।

किताब का नाम इकानोमिक सर्वे आफ हरियाणा 1972–73। इसमे लिखा है–

"The economic growth in Haryana during 1968-69 to 1970-71 has been particularly spectaculay, being 14.4% per year against 4.9% in India."

सारे भारतवर्श का ग्रोथ रेट उस अर्से मे 4.9 परसेन्ट हे और हरियाणा का 14.4 परसैंट है। अब आप बतलाईये कि हरियाणा के मुताल्लिक यह कहा जाये कि हमारे यहां कोइ तरक्की नही हुई, मुझे यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ जब यह कहा कगया कि तार है लेकिन बिजली नही ओर नहर है मगर पानी नही है। मैं तो चाहता हूं कि गुप्ता साहब इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर माननीय सदस्य को लेकर किसी तार के पास जाएं और कहे कि तार को हाथ लगाकर देखो कि बिजली हे या नही है और नहर मे डूबकी लगवाकर दिखवा दे कि उनमे पानी है या नही है। आप बजट एट ए ग्लांस को देखे उनमे हमारी पर कैपिटा इंकम दी हुई है। पेज 18 पर यह इंकम दी हुई है–

1965–66	319
1966–67	343
1967–68	399
1968–69	354
1969–70	429 और सब से ज्यादा
1970–71	445

अब आप देखिए कि हमारी पर कैपिटा इंकम कितनी बढ़ी है। ठीक है तो तीन साल मे हमारी पर कैपिटा कुछ कम हुई है और इसका कारण है कि बारि ा कम हुई, ड्राउट हुआ, पैदावार कम हुई और साथ ही पापूले ान भी बढ़ गई। लेकिन फिर भी आप हिसाब लगा लीजिए कि जब से चौधरी बंसी लाल की सरकार आई उस वक्त से हमारी पर कैपिटा इंकम बढ़ती रही है। 1971–72 मे वह 441 हो गई। 1972–73 मे वह 435 रही और 1973–74 मे 4433 हो गई। मतलब कहने का यह है कि यह पैदावार और पापूले ान पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से 1966–67 का जो ग्रोथ रेट था उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़ा है। यह बात कहना कि हमारी कोई तरक्की नही हुई यह तो एक स्वीपिंग स्टेटमैंट है और अगर बेलेंस आफ माइंड रखा जाये तो ऐसा स्टेटमैंट नही आना चाहिए।

अब एक बात और कहते है कि हमारी टेक्से ान बहुत आई है। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा और माननीय सदस्य ने हिसाब नही लगाया होगा कि सारे हिन्दुस्तान मे हमारे जो टैक्स है वे कम है। आप सब से पहले इलैक्ट्रिसिटी डयूटी को लीजिए–

ऐग्रीकल्चर सप्लाई

हरियाणा का 15 है। पंजाब की फिगर मेरे पास नही है। राजस्थान मे 21 है। यू.पी. मे 21.67 है और दिल्ली मे 26 है। इसी तरह से आप इंडस्ट्रीज को ले लीजिए।

इंडस्ट्रियल लार्ज सप्लाई

हरियाणा का 11.2 है। पंजाब का 11.51 है। राजस्थान का 17.00 है। यू.पी. मे 21.67 है और दिल्ली मे 13.85 है। कोई भी आंकड़े ले लीजिए हरियाणा मे सब से कम है।

इंडस्ट्रियल मीडियम सप्लाई

हरियाणा मे 14.42 है। पंजाब मे 16.50 है। राजस्थान मे 22.00 है। यू.पी. मे 18.01 है और दिल्ली मे 16.00 है। अब मैं आपको कौमि र्यिल रेट्स बताता हूं।

कौमि र्लिय सप्लाई

हरियाणा मे 35.23 है। पंजाब मे 52.97 है। राजस्थान मे 48.00 है। यू.पी. मे 40.00 है और दिल्ली मे 24 है। पंजाब के मुकाबले और जितनी दूसरी स्टेटस है उनके मुकाबले मे हमारे रेट्स काफी कम है। अब मैं आपको वाअर रेट्स बताता हूं।

वाटर रेट फा राइस जो है वह इस तरह है–

हरियाणा मे 7.75, आंध्र प्रदे ा मे 15.00, महाराश्ट्र 9 से 15 तक, मध्य प्रदे ा 16 से 24 तक, मैसूर 11 से 16.50 और पंजाब 9.75 से 9.88 है। पंजाब को छोड़ कर जो दूसरी स्टेटस है उनसे हरियाणा का कम है।

काटन के लिये रेट्स इस तरह से है–

हरियाणा 6.75, गुजरात 37, मध्य प्रदे ा 16, उड़ीसा 10, पंजाब 7.88 है। हमारे टैक्सिज है वे आप इन फिगर्ज से देख सकते है कि दूसरी स्टेटों से कम है। अब आप सेल्ज टैक्स को लीजिए। पंजाब और हरियाणा मे एकसां है 6 परसैंट, राजस्थान मे 7 परसैंट है, स्पै ाल गुड्ज पर सब स्टेटो मे वही है । रेजिन पर सैज्ल टैक्स है हरियाणा मे 2 परसैंट, पंजाब मे 6 परसैंटं ग्राउंड नट पर हरियाणा मे है 2 परसैंट और पंजाब मे 3 परसैंट है। काटन यार्न पर हरियाणा मे 1 परसैंट और पंजाब मे 3 परसैंट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे टैक्सिज का आप हिसाब लगा लीजिए और स्टेटस के मुकाबले ऐसा कोई टैक्स नही है जो कम न हो। यह कहना कि हमारी हैविली टैक्स स्टेट है, यह ठीक नही है।

अब यह कहा जाता है कि पैदावार कम होती जा रही है। इसका हिसाब भी लगा लीजिए। फूड ग्रेंज 1966–67 मे हमारी थी 25.92 लाख टन और एरिया था 35.17 लाख हैक्टेयर्ज और हाई यील्डिंग वैरायटी पहले थी 16.8 हजार हैक्टेयर और

1970–71 मे वह 1094 हजार हैक्टैयर हो गई। इसी तरह सवे फूड ग्रेन्ज का उत्पादन 1966–67 मे 25.92 लाख टन था और 1970–71 मे 47.71 लाख टन हो गया लेकिन 1971–72 और 1972–72 मे इसकी हमारी कुछ कमी हुई इसका कारण मैं बाद मे बताउंगा किन्तु 1966–67 मे जहां 25.26 लाख टन थी उससे तो फिर भी करीब दो गुना रही है। इसी तरह से खरीफ फूडग्रेन्ज है। यह 1966–67 मे 7.47 लाख टन थे और 1973–74 मे इससे डबल यानी 14.15 लाख टन हो गये। राइस 1966–67 मे 2.23 लाख टन थे और 1973–74 मे 5.40 लाख टन हो गये इसका मतलब है कि 142.15 प्रति ात इसमे बढोतरी हुई। टोटल एरिया जो पहले था 1.92 लाख हैक्टेयर और अब हो गया है 2.92 लाख हैक्टेयर। इसी तरह से 1966–67 मे हाई यील्डिंग वैरायटीज का 4 हजार हैक्टैयर था और अब वह 1973–74 मे 125 हजार हैक्टेयर हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब से हरियाणा बना है उस वक्त से हमारी पैदावार मे कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब हम फूड ग्रेन्ज के उत्पादन मे सरप्लस हो गये है और हम दूसरी स्टेटस को फूड ग्रेनज देते है। मैं एक दफा का मीर मे एक कांनफ्रैंस मे गया था तो वहां पर हमारी वैस्टर्न स्टेट का भी एक मैंबर बैठा हुआ था । उन्होंने मुझे कहा कि आप हमको भूखा मारेंगे तो मैंने कहा कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन आपका भूखे नही मारेंगे। इसी तरह से हमारा गेहूं का प्रोडक ान 1966–67 मे 10.59 लाख टन था और 1971–72 मे 24.02 लाख टन हो गया। आप अंदाजा लगा ले कि कितना बढ़ गया ? 1973–74 मे चूंकि बरसात और पानी की कमी

थी इस वजह से हमारा प्रोडक ान कुछ कम हुआ लेकिन फिर भी पहले से तो डेढ़ गुना हुआ है। इसी तरह से 1972–73 मे बाजरा हमारा ठीक तरह से पैदा नही हुआं बाजरा बरसात से पैदा होता है और जब कीाी इंद्र भगवान बरसात न करें तो यह क्राप फेल हो जाती है इसी तरह 1972–73 मे रबी के अंदर विंटर रेन नही हुई उससे भी बड़ा फर्क पड़ गया। इसलिये जहां बरसात का यानी कुदरत का ताल्लुक होता है वहां पर आदमी कुछ नही कर सकता। इसके बाद फूड ग्रेंज का पिछले पांच साल का ग्रोथ रेट जो हे वह 2.6 प्रति ात के मुकाबिले 4 प्रति ात हो गया है। हमारी हर तरह से प्रोडक ान घटती जारही हे यह एक इररिसपोंसिबल स्टेटमैंट है जोकि नही कहनी चाहिए फिर एक बात की गई कि यह जो प्रोडक ान की कमी हुई यह मेन मिसटेक से हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाखड़ा जो है वह तो उस वक्त की गवर्नमैंट ने और इंजिनिसरों ने बनाया था या सैंट्रल गवर्नमैंट ने बनाया था। भाखड़ा मे पानी तो सतलुज से आएगा और अगर बरसात नही होगी और बर्फ नही गिरेगी तो भाखड़ा मे पानी कहां से आयेगा ? तो क्या यह भी मैन मेड मिसटेक है ? चौधरी चांद राम जी ने एक बात कही थी कि यह जो प्रोडक ान बढ़ी हे उसका क्रैडिट चौधरी बंसी लाल को नही जाता क्योंकि 1967 मे गवर्नर ऐड्रैस मे भी यह लिखा हुआ था दो थर्मल प्लांट बनने चाहिए। अब इनसे पूछा जाये कि 1967 मे पंडित भगवत दयाल की गवर्नमैंअ इनहोंने ही टापल की थी और उसे टापल करके ये खूद पावर मे आये थे। भाायद ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। मैं

इनसे पूछना चाहता हूं कि जितना समय ये रहे इन्होने उस समय मे थर्मल प्लांटस को बनाने मे क्या स्टैपसय लिये। सवाल तो यह है कि हम डिपैंड करते हे नहरों पर। भाखड़ा मे हमें बिजली मिलती है तो यह इंद्र भगवान पर डिपैंड करता है जब तक वह हमारे पर खु ा रहेगा और हमे पानी बिजली मिलती रहेगी लेकिन जब बरसात ही नही होगी तो हम किसको दोश दे सकते है इसलिये भविशय मे कुदरत पर हमं डिपैंड नही करना चाहिये, हमे अपनी कोि ा ा से और कदम उठाने चाहिएं और चीज को देखते हुए ये थर्मल प्लांटस बनाए जा रहे है। लेकिन यह कहना कि यह जो हुआ है यह सब मैन मेड मिसटेक से हुआ हे यह ठीक नही है। यह इन्होंने एक बहुत ही अन डिजरविंग बात कह डाली जोकि कहनी नही चाहिए थी। चौधरी मनफूल सिंह जी ने फैमिली प्लानिंग के बारे मे कहा कि इसके लिये जो रूपया रखा गया है वह कुछ भी नही है। इसके बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये हमने एक करोड़ 74 लाख रूपये प्रोवाइड किये है। यह फिग्गर इस किताब के पेज 5 के ऊपर आइटम 281 पर है। इसके मुत्तलिक एक बात मैं अर्ज करूंगा कि हमारे गुलाटी साहब ने एक बड़ी अच्छी प्रोपोजल रखी है कि चाइल्ड टैक्स लगना चाहिए। मैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा क्योंकि सिर्फ इन्होंने ही कहा है कि टैक्स लगना चाहिए। यह बड़ी हिम्मत की बात है कि एक आनरेबल मैंबर की तरफ से ऐसी प्रोपोजल आए। हमारे प्रधान जी ने कहा कि आप कंसिडर करो कि चाइल्ड पर टैक्स कैसे लगाए। हम चाइल्ड पर टैक्स नही लगा सकते, उसकी मां पर भी

टैक्स नही लगा सकतें उसके फादर पर लगना चाहिये लेकिन अगर उसने टैक्स से बचने के लिये बच्चे को डिसओन कर दिया कि हय मेरी गल्ती हनी है (हंसी) तो क्या होगा ? तो मैं इसके लिये गुलाटी साहब से अर्ज करूंगा कि वह कोई इस बारे मे अच्छी सी स्कीम सारे पहलूओं को कंसिडर करके बनाये और मैं मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जरूर लागू कर दे (हंसी) मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उससे जो इंकम हो वह भी फरीदाबाद की डिवैल्पमैंट पर खर्च कर दी जाये (विघ्न) और भी बहुत बाते थी जिनका मैं जिक्र करना चाहता था लेकिन अब समय हो गया और स्पीकर साहब आप गिलोटीन भी लगाना चाहेंगे इसलिये मैं अब ज्यादा समय नही लेना चाहता और यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंबर साहिबानने अपने अपने हल्कों के बारे मे जो सजै ांज दिये है उनको कंसिडर किया जायेगा और जो उचित बात है वह की जायेगी। इन भाब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि यह डिमांडज पास कर दी जाये। (थम्पिंग)

Mr. Speaker: Quesiton is—

That a sume not exceeding Rs. 2191000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No. 1 Vidhan Sabha..

That a sume not exceeding Rs. 41184160 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.2 General Administration.

That a sume not exceeding Rs. 103907790 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No. 3 Home Department.

That a sume not exceeding Rs. 29786060 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.4 Revenue Department.

That a sume not exceeding Rs. 13365390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.5 Excise and Taxation Department.

That a sume not exceeding Rs. 28537780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.6 Finance Department.

That a sume not exceeding Rs. 27731645be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.7 Other Aministrative Services.

That a sume not exceeding Rs. 213507630 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.8 Buildings and Roads Department.

That a sume not exceeding Rs. 319550450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.9 Educaiton Department.

That a sume not exceeding Rs. 154085010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.10 Medical and Public Health Department.

That a sume not exceeding Rs. 112209440 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.11 Urban Development Department.

That a sume not exceeding Rs. 17540820 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.12 Labour and Employment Department.

That a sume not exceeding Rs. 24259380 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No. 13 Social welfare and Rehabilitaiton Department.

That a sume not exceeding Rs. 998816300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.14 Food and Supplies Department.

That a sume not exceeding Rs. 526409495 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.15 Irrigation Department.

That a sume not exceeding Rs. 28070720 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.16 Industries Department.

That a sume not exceeding Rs. 91613300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.17 Agriculture Department.

That a sume not exceeding Rs. 30287700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.18 Animal Husbandry.

That a sume not exceeding Rs. 1819000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.19 Fisheries Department.

That a sume not exceeding Rs. 13904310 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.20 Forest Department.

That a sume not exceeding Rs. 25452690 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.21 Community Development Department.

That a sume not exceeding Rs. 322363490 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.22 Co-operation Department.

That a sume not exceeding Rs. 328346180 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No. 23 Transport Department.

That a sume not exceeding Rs. 693500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.24 Tourism Department.

That a sume not exceeding Rs. 264469200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1975-76 is respect of the charges under Demand No.25 Loans and Advances.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands *adjourned till 2.00 p.m. on tomorrow.

18.04 बजे

(The Sabha then *adjourned till 2.00 p.m. on Wednesday the 15th January, 1975)